R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 10
16 से 28 फरवरी 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

सूत न कपास नेताओं में लट्ठम-लट्ठा

भाजपा विकास यात्रा निकाल साध रही चुनावी गणित

कांग्रेस कमजोर संगठन के साथ जोड़ रही हाथ से हाथ

ANU SALES CORPORATION
R1+S
R1+S
R2
R2
R1+S
R1+S
R2
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
1 2 3 • 17 18 19 20 • 33 34 35 36 37 • 45 46
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology & Medical Equipment
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

वल्लभगाथा

9 | एलिजिबिलिटी नहीं सूटेबिलिटी चाहिए

मप्र में एक तरफ सरकार सुशासन के लिए नए-नए नवाचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जबसे प्रदेश में चौथी मंजिल का दबदबा बढ़ा है, प्रशासन में भर्राशाही और लालफीताशाही बढ़ गई है। आलम यह है कि अफसरों की...

राजपथ

10-11 | 'नवाचारों' से 51...

मप्र में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में 51 फीसदी वोट को जो लक्ष्य रखा है उसे पाने के लिए पार्टी सरकार के नवाचारों का सहारा लेगी। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान...

पहल

14 | अब पांच वर्षों के लिए रेत...

सरकारी खजाने को भरने के लिए प्रदेश सरकार नई रेत नीति लाने की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही प्रदेश में नई रेत नीति देखने को मिलेगी। इस बार जिले में एकल ठेका देने के स्थान पर राज्य की शिवराज सरकार तहसील एवं पंचायत स्तर पर छोटे-छोटे...

शराब

18 | बंद हो सकते हैं अहाते

मप्र में नई शराब नीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विरोध के बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। नीति का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके मुताबिक अहाते बंद हो सकते हैं। यदि चालू रखने का निर्णय होता भी है, तो शाम 5 बजे से रात 11 बजे...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

नवंबर में मप्र में चुनावी डंका बजेगा। लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। खासकर भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। चुनावी तैयारी के प्रथम चरण में दोनों पार्टियां जनता के दर पर दस्तक दे रही हैं। इसलिए मप्र में यात्रा पॉलिटिक्स का माहौल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह की मैदानी रिपोर्ट मिल रही है, उससे यह साफ दिख रहा है कि मतदाता दोनों पार्टियों से नाखुश हैं।

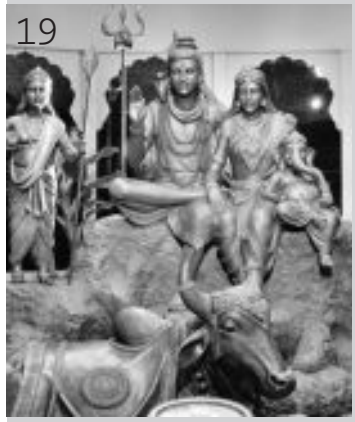
19

37

44

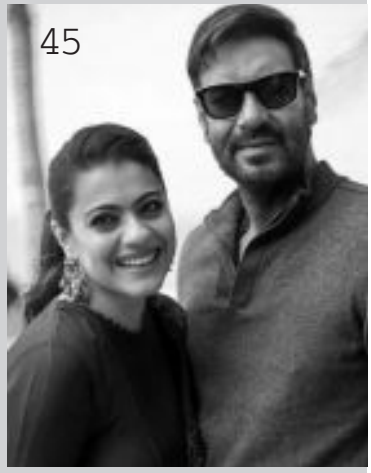
45

राजनीति

30-31 | विपक्ष की अपनी...

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल को उम्मीद थी कि यात्रा के दौरान कई दल उसके साथ जुड़ेंगे व राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बन 2024 में उन्हें ही भाजपा का विकल्प बन प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। पर यात्रा के समापन के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि अब कोई उम्मीद...

महाराष्ट्र

35 | शिंदे की ब्रांडिंग

चीन के स्टार के फीका पड़ने पर भारत ने दावोस में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। दावोस से लौटे भारतीय तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला, बेशक, आरके सिंह का भोजन, ऊर्जा और पानी की परस्पर क्रिया पर एक सत्र में शानदार प्रदर्शन है। जब न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट और...

बिहार

38 | जाति के जंजाल में बिहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जाति गणना की कवायद शुरू कर दी है। 7 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान के 15 दिनों के पहले चरण में मकानों की गिनती होगी जबकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले दूसरे चरण में लोगों से...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

बाबाओं का मायाजाल...

कबीर दास की ये पंक्तियां तो सभी ने पढ़ी होंगी...

माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माहि।
मनवा तो चहु दिश फिरै, ये तो सुमिरन नाहिं॥

ये पंक्तियां वर्तमान समय में सटीक बैठ रही हैं। इस समय बाबाओं ने अपने अध्यात्म का ऐसा मायाजाल फैलाया है, कि लोग धर्म के नाम पर उसमें फंसते जा रहे हैं। धर्म के प्रति आस्थावान होना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन जिस तरह लोगों को धर्मभीरू बनाया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। कोई बाबा चिट्ठी-पत्री पर लिखकर भविष्य बता रहा है, तो कोई रूद्राक्ष बांटकर भविष्य सुधारने का दावा कर रहा है। यही नहीं बाबाओं के बिगड़े बोल के कारण देश-प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। इन सबके बावजूद शासन-प्रशासन बाबाओं के बड़े-बड़े आयोजनों की व्यवस्था में अपना वक्त जाया कर रहा है। हमें बचपन से किताबों में यही पढ़ाया जाता रहा है कि सच बोलो, झूठ पाप के समान है। मगर इसी झूठ से अंधविश्वास की दुकानों में खूब नफा कमाया जा रहा है, वह भी उसी धर्म-मजहब के नाम पर जिसमें सच बोलने की सीख दी जाती है। जो लोग मजहब के रहनुमा बनने की बात करते हैं, उन्हीं की नाक के नीचे अंधविश्वास का यह कारोबार फल-फूल रहा है। ऐसे में यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्हें इसकी खबर नहीं, मगर यह सवाल जरूर उठता है कि अंधविश्वास फैलाने वाले ढोंगी मौलानाओं, बाबाओं का विरोध पुरजोर तरीके से क्यों नहीं किया जाता, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मुहिम या फतवा जारी क्यों नहीं होता। 21वीं सदी में विज्ञान इंसान को चांद पर बसाने की कोशिश कर रहा है। कोई ठीक नहीं कि कुछ समय में चांद पर पहुंचाने के दावे ढोंगी तांत्रिक बाबाओं की ओर से किए जाने लगें, क्योंकि विज्ञान से ज्यादा आज लोग अंधविश्वास और जादू-टोने में अपनी मुसीबतों का इलाज तलाश रहे हैं। इसकी वजह है कि लोगों में पैसा कमाने की जल्दी और जल्द से जल्द दिक्कतों को दूर कराने की होड़। इसका हल वे अपने प्रयासों में कम, इन ढोंगियों के पास ज्यादा ढूंढ़ने लगे हैं। यही वजह है कि अभी तक कुछ आसूमल, निर्मल बाबाओं की एक खेप लोगों को झूठे ख्वाब दिखाकर उल्लू बना रही थी। अब बाबाजी, मौलानाजी जैसे फर्जी दावे वाले लोग भी अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के बाजार में पूरी तरह उतर आए हैं। इनके हौंसले भी इतने बुलंद हैं कि अभी तक इनकी पहुंच मुहल्लों, कस्बों तक थी पर अब इनका मायाजाल शहरों की चकाचौंध तक जा पहुंचा है। इसकी एक वजह यह भी है कि इन ढोंगियों को मीडिया का सहयोग हासिल है। जैसे सरकारें सिगरेट, तंबाकू, शराब से बचने की ताकीद विज्ञापनों के जरिए करती हैं और इनको बेचने का लाइसेंस भी वही मुहैया कराती हैं। ऐसे ही मीडिया भी एक तरफ अंधविश्वास की खबरों को दिखाकर उसका विरोध करता है और दूसरी तरफ अखबारों और चैनलों में तांत्रिकों, बाबाओं के विज्ञापन भी छापता और दिखाता है। मीडिया झूठे दावों को प्रचार-प्रसार भी करता है, क्योंकि सरकार को भी मीडिया से कर के रूप में आमदनी होती है। शायद सरकार भी इसीलिए चुप रहती है। यही वजह है कि इन अंधविश्वास फैलाने वालों के हौंसले बुलंद हैं और इनका जाल अब अशिक्षित, गरीब लोगों के दायरे से बढ़कर शिक्षित युवाओं और विदेशों तक फैल चुका है। इनकी साइटें हैं, ब्लॉग हैं और जिन पर गरीबी, बीमारी को दूर करने से लेकर हर समस्या के समाधान की बात लिखी हुई है। साथ ही एक बड़ी फेहरिस्त उन दावों की है जिससे प्रभावित होकर लोग इनके जाल में फंसते हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 10, पृष्ठ-48, 16 से 28 फरवरी, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

बजट से कई उम्मीदें

आगामी बजट में सरकार को रोजगार और शिक्षा पर अधिक फोकस करना चाहिए। जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सरकार अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ केंद्रीय योजनाओं के भरपूर उपयोग की कार्ययोजना पर काम कर रही है। आगामी बजट से कई उम्मीदें हैं।

● **अंकिता सेन,** भोपाल (म.प्र.)

मेट्रो की सौगात

मप्र के दो बड़े शहरों में मेट्रो जल्द दौड़ेगी। इंदौर मेट्रो और भोपाल मेट्रो दोनों ही प्रोजेक्ट पर काम साल 2018 में शुरू किया गया था। अब इस साल के अंत तक दोनों शहरों के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। अब जल्द ही भोपाल और इंदौर भी मेट्रो सिटी कहलाएंगी।

● **कार्तिक सोनी,** इंदौर (म.प्र.)

आदिवासी वोटर अहम

मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर सरकार तय करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मप्र की सियासत में आदिवासी वोटर गेमचेंजर साबित होता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मप्र में हर पांचवा व्यक्ति आदिवासी वर्ग का है।

● **गंगाराम केवट,** सीहोर (म.प्र.)

दुनियाभर में छा रहा देश के खिलाड़ियों का नाम

देश के खेल मानचित्र पर मप्र का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों ने एक बार फिर गौरव बढ़ाया है। मप्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओवर चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीतकर प्रदेश का गौरव प्रदान किया है। भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने में मप्र आगे है। यूथ गेम्स में पहली बार मलखंभ को जोड़ा गया है। प्रदेश में मलखंभ को करीब दस वर्ष पहले राज्य खेल घोषित करने की पहल हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे आयोजन से एक तरफ जहां खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ दुनियाभर में देश के खिलाड़ियों को पहचान भी मिलती है। जिससे देश गर्वान्वित महसूस करता है। आने वाले समय में भी इस प्रकार के आयोजनों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा।

● **शारदा शिंदे,** ग्वालियर (म.प्र.)

चुनाव को लेकर नेता एक्टिव

2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। विधानसभा चुनावों के नतीजे 2024 की चुनावी लड़ाई की रणनीति तय करेंगे। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावी साल में हर नेता हाईली एक्टिव होगा। कभी जनता के बीच, कभी सभा, कभी रैली और जब फुर्सत मिलेगी, तब नई रणनीति पर सोच विचार। आने वाले कुछ दिन मप्र के प्रमुख और दिग्गज नेताओं का यही हाल होगा जिनके कंधों पर जीत की जिम्मेदारी होगी।

● **पंकज शर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

मप्र की पहचान पर्यटन से

मप्र के हर इलाके की अपनी संस्कृति है और अपनी धार्मिक परम्पराएं हैं जो उनके उत्सवों और मेलों में अपना रंग भरती हैं। पर्यटन स्थलों में मप्र अहम भूमिका रखता है। इसके साथ ही अब मप्र के धार्मिक स्थल देशभर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। महाकालेश्वर से लेकर अन्य धार्मिक स्थल मप्र को एक अलग पहचान दिला रहे हैं। रीवा भी अब पर्यटन के लिहाज से मप्र की पहचान के रूप में उभरने की तैयारी कर रहा है।

● **शंकर पांडे,** शहडोल (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

फिर कुबोल

बड़बोले नेता चाहे जिस पार्टी के हों, अक्सर फजीहत ही कराते हैं अपने बड़बोलेपन से अपनी पार्टी और खुद की। तेलंगाना के भाजपा विधायक रघुनंदन राव का नाम भी ऐसे ही बड़बोले नेताओं की सूची में शामिल हो गया है। हाल ही में बिहारियों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी कर विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। दरअसल, तेलंगाना सरकार ने सूबे का पुलिस महानिदेशक बिहार काडर के आईपीएस अधिकारी अंजनी कुमार को बनाया है। इससे पहले भी बिहार के कुछ अफसरों को उन्होंने सूबे में तैनाती दे रखी थी। रघुनंदन राव चूंकि भाजपाई हैं सो मुख्यमंत्री केसीआर पर हमला करने के अवसर की तलाश में रहेंगे ही। केसीआर की आलोचना करते-करते जुबान ऐसी फिसली कि बिहारियों को गुंडाराज का प्रतीक बता बैठे। केंद्रीय सेवा के अफसरों का काडर चाहे कोई भी हो पर वे डेपुटेशन पर किसी भी राज्य में जा सकते हैं। केंद्र का तो अपना कोई काडर होता नहीं, लिहाजा सभी आईएएस व आईपीएस अफसर केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों से ही डेपुटेशन पर मांगती है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम जैसे राज्यों में दूसरे राज्यों के आईपीएस अधिकारी पुलिस महानिदेशक पहले भी रहे हैं। रघुनंदन राव ने केसीआर पर हमला करते हुए बयान दिया कि बिहारी अफसरों को लेकर वे बिहार का गुंडाराज तेलंगाना में भी चलाना चाहते हैं।

क्या गुल खिलाएंगे वरुण गांधी

मिशन 2024 की सियासी जंग नजदीक होने के कारण अब वरुण गांधी के सियासी भविष्य को लेकर राजनीतिक हलकों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। सत्ता गलियारों में कहा-सुना जा रहा है कि वरुण गांधी नए राजनीतिक दल का गठन करके 2024 के चुनाव के दौरान सियासी अखाड़े में कूद सकते हैं। दरअसल भाजपा और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बागी तेवर अपना चुके पार्टी सांसद वरुण गांधी के सियासी भविष्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। भाजपा नेतृत्व की ओर से वरुण गांधी के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है मगर अगले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी का टिकट न मिलना तय माना जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिर वरुण गांधी आने वाले दिनों में क्या सियासी गुल खिलाने वाले हैं। पिछले दिनों वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था लेकिन राहुल गांधी के अलग विचारधारा वाले बयान के बाद इन चर्चाओं पर विराम लग गया था। जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं भी जोरों पर सुनी जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं और अलग पार्टी के गठन में उन्हें अपनी मां मेनका गांधी का साथ भी मिल सकता है।

कश्मीर में कमल खिलाएंगे आजाद

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की हलचल के बीच कुछ महीने पहले कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी गठित करने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए गुलाम नबी आजाद की पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। इन अटकलों को बल मिल रहा है कई मौकों पर गुलाम नबी का भाजपा के प्रति नरम रुख के चलते। जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की थी तो उस वक्त गुलाम कांग्रेस में थे। बाद में खुद गुलाम ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद कयास लगने लगे कि क्या अब गुलाम भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में गुलाम ने कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, लेकिन अब जब उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, तो तरह-तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

गाली गाथा

'हराम' शब्द का मतलब क्या है? जो पाप है जो वर्जित है। अपने असंसदीय शब्द पर हंगामे के बाद महुआ मोइत्रा इसके अरबी मूल के जरिए इसे न्यायोचित ठहराने की कोशिश कर रही हैं। आमतौर पर हिंदीभाषी गुस्से में अंग्रेजी बोलने लगते हैं। इन दिनों देखा गया है कि जब उच्च वर्ग की महिलाएं गुस्सा होती हैं तो हिंदी में गाली देती हैं। हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर की हाउसिंग सोसायटी के मुख्यद्वार पर ऐसी कई घटनाएं देखी गईं जब अंग्रेजी में ही बात करने वाली महिलाएं सुरक्षाकर्मियों को हिंदी में भद्दी गालियां देती दिखाई दीं। तृणमूल सांसद महुआ मोईत्रा उन उच्च वर्गीय लोगों में शुमार हो चुकी हैं जो गुस्सा आने पर हिंदी में गाली देती हैं। महुआ मोइत्रा के बोले शब्द संसद के रेकार्ड से हटा दिए गए हैं लेकिन महुआ उसे सोशल मीडिया के रेकार्ड पर ला रही हैं। गलती पर क्षमा कहकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन संसद में असंसदीय शब्द बोलकर उसे अरबी भाषा के जरिए सही ठहराना महुआ के अहंकार को ही दर्शाता है।

दक्षिण का दुख

अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों के बीच जंग तेज हो जाने से भाजपा की दुविधा बढ़ गई है। दक्षिण के इस राज्य में भी केरल की तरह ही भाजपा अभी तक अपनी खुद की कोई जमीन तैयार नहीं कर पाई है। जयललिता के सहारे हालांकि अतीत में उसे यहां लोकसभा और विधानसभा की सीटें मिल चुकी हैं पर जयललिता की विरासत का झगड़ा भाजपा को भी भारी पड़ रहा है। एक तरफ ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी के गुटों में वर्चस्व की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है तो दूसरी तरफ शशिकला भी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही हैं। जेल से तो वे पहले ही बाहर आ गई थी। अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों की लड़ाई के हश्र का इंतजार कर रही होंगी। अन्नाद्रमुक के झगड़े से स्टालिन की द्रमुक निश्चिंत है। इस बीच इरोड पूर्व विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर भी अन्नाद्रमुक के दोनों गुट आमने-सामने हैं। पनीरसेल्वम ने यहां अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और भाजपा से समर्थन मांगा है।

कद्दू कटेगा तो सब में बंटेगा

उपरोक्त कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इन दिनों यह कहावत प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में एक चलन शुरू हो गया है कि किसी योजना के लिए राजधानी से जिलों में फंड जाता है तो उसके साथ ही यह फरमान भी चला जाता है कि अब यह काम अमूक व्यक्ति को दिया जाए। इससे जिलों में पदस्थ अफसरों के सामने विकट स्थिति निर्मित हो रही है। इसकी वजह यह है कि जिस काम के लिए फंड जाता है, वह काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसा ही एक मामला शिक्षा विभाग में घटित हुआ है। सूत्रों का कहना है कि स्कूलों को हाईटेक और सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए जिलों में फंड भेजा गया। इस फंड से स्कूलों में टेबिल-कुर्सी, ब्लैक बोर्ड और अन्य सामग्री खरीदनी है। जैसे ही फंड जिलों में पहुंचा कलेक्टर के पास मौखिक निर्देश भी पहुंच गए कि इस फंड से प्रभारी मंत्री के मंशानुसार काम करवाया जाए। बताया जाता है कि इस निर्देश के बाद अफसर असमंजस में पड़ गए हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस उद्देश्य से यह राशि भेजी गई है, वह महज खानापूर्ति बनकर रह जाएगी। यह फंड पूरी तरह बंदरबांट की भेंट चढ़ जाएगा और स्कूलों में भेजी जाने वाली सामग्री गुणवत्ताहीन होगी। लेकिन अफसर बेचारे करें भी तो क्या करें, उन्हें मालूम है कि कद्दू कटेगा तो सब में बंटेगा।

पूरा विभाग लामबंद

प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री की मनमानी से उनके विभाग के अधिकारी-कर्मचारी परेशान हो उठे हैं और वे लामबंद होकर हड़ताल की मुद्रा में आ गए हैं। दरअसल, जिस विभाग की यहां बात हो रही है, वह विभाग हथियारों के लाइसेंस भी देता है। लेकिन यहां स्थिति यह है कि तमंचे के लाइसेंस अधिकारियों की सिफारिश से नहीं दिया जा रहा है। वजह यह है कि साहब ने पूरी तरह यह काम अपने कब्जे में ले रखा है। इससे अधिकारियों-कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। आलम यह है कि अधिकारियों की सिफारिश के बाद तमंचे का लाइसेंस नहीं मिलने के विरोध में करीब सवा महीने से सभी फाइलें डम्प कर दी गई हैं। यानी एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ पाई है। इस संदर्भ में अधिकारियों का कहना है कि हम साहब का इतना काम करते हैं, तो वे हमें भी तो महत्व दें। अगर महत्व नहीं देते हैं तो वे हमसे उम्मीद क्यों रखते हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी के पास इन दिनों एक नया कलेक्शन अधिकारी आ गया है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा की तर्ज पर इससे मंत्रीजी की कार्यप्रणाली और बिगड़ गई है। जिसका असर यह हुआ है कि पूरा विभाग मंत्रीजी के खिलाफ लामबंद हो गया है।

पर्चे के पीछे कौन?

प्रदेश में अपनी तथाकथित ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले 1989 बैच के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इन दिनों काफी चिंतित हैं। वजह यह है कि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में साहब के खिलाफ एक पर्चा खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस पर्चे की विशेषता यह है कि इसमें साहब की पूरी काली कमाई का विवरण है। इस पर्चे के सार्वजनिक होने के बाद साहब की खूब छिछालेदर हो रही है। जिस बारीकी से पर्चे को तैयार किया गया है, उससे यह बात तो तय है कि इसे किसी मुनीम ने ही तैयार किया होगा। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रसूख और रूआब से खार खाकर एक कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही जाति बिरादरी के एक रिटायर्ड अकाउंटेंट से यह पर्चा बनवाया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी की निशानदेही पर बनाए गए, इस पर्चे को मंत्रीजी के बंगले पर ही टाइप किया गया है। पर्चे में जो विवरण अंकित है, उसे प्रशासनिक वीथिका में कई अफसर पूरी तरह सही मान रहे हैं। इस कारण ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले साहब इन दिनों चिंतित दिख रहे हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि साहब की छवि खराब होने से उनके विभाग में पदस्थ अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। 2012 बैच के एक आईएएस अधिकारी ने तो पर्चाकांड के बाद दूसरे विभाग में तबादले की कोशिश भी शुरू कर दी है। वे यहां अब एक पल भी ठहरना नहीं चाहते हैं।

खुला खेल फर्रूखाबादी

यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसे इन दिनों एक पुराना आरटीओ में डेपुटेशन पर पदस्थ रहा इंस्पेक्टर साकार कर रहा है। जब यह इंस्पेक्टर नौकरी में था तो उस समय भी अफसरों का पैसा ठिकाने लगाने का काम करता था। जिसके कारण उसके खिलाफ आयकर विभाग की रेड भी पड़ चुकी है। अब वह इंस्पेक्टर रिटायर होने के बाद पूरी तरह हवाला में जुट गया है। सूत्रों का कहना है कि वह शहर के कुछ बड़े माफिया के साथ ही वह राजधानी में पदस्थ एक आईजी की कमाई को भी इधर-उधर कर रहा है। जानकारों का कहना है कि वह इंस्पेक्टर यह भलीभांति जानता है कि काली कमाई को व्हाइट कैसे किया जाता है। इस खेल में पारंगत होने के कारण माफिया के साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारी भी उसकी सेवाएं ले रहे हैं। पुलिस विभाग में रहने के कारण वह सारे तिकड़म तो जानता ही है। अब वह रिटायर होने के बाद पूरी तरह खाली है। ऐसे में उसका पूरा समय इसी काम में लगा रहता है। उसे अब इस बात का भी डर नहीं है कि उसके खिलाफ शासकीय एजेंसियां कोई कदम उठा सकती हैं।

चुनावी या अपना फंड

प्रदेश के लिए यह साल चुनाव का है। इसके लिए सरकार के साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी भी जुट गई है। लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच एक चौंकाने वाली खबर ऐसी आई है, जिससे प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में हलचल मच गई है। दरअसल, बुंदेलखंड क्षेत्र के एक सांसद के प्रतिनिधि पर एक पूर्व विधायक के पुत्र जो वर्तमान में विधायक हैं, ने आरोप लगाया है कि वे खनिज माफिया को वरदहस्त देकर जमकर काली कमाई कर रहे हैं। यही नहीं आरोप तो यह भी है कि एक तरफ प्रदेश में जहां नई रेत खनन नीति आकार ले रही है, वहीं दूसरी तरफ सांसद प्रतिनिधि ने खनन माफिया के साथ संसदीय क्षेत्र के एक फाइव स्टार होटल में सांसद जी की मीटिंग कराई है। बताया जाता है कि इस मीटिंग के दौरान संरक्षण के नाम पर माफिया से मोटी रकम के लिए चर्चा हुई। यह मोटी रकम चुनावी साल में पार्टी फंड के लिए ली जाएगी या अपने लिए, यह तो वे ही लोग जानते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बैठक की खबर विभागीय मंत्री तक को नहीं लग पाई है। ऐसे में यह बैठक सवालों के घेरे में है।

त्रिवेणी संग्रहालय में सजेगी 18 पुराणों की गाथा

महाकाल लोक के बाद उज्जैन में 18 पुराणों की सचित्रगाथा आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। महाकाल मंदिर के समीप संस्कृति विभाग के त्रिवेणी संग्रहालय में 18 पुराणों की गाथा सजेगी। यह गाथा पेंटिंग्स के रूप में रहेगी। 18 चित्रकार 18 पुराणों की पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं। इन पेंटिंग्स की विशेषता यह होगी कि इन्हें देखकर पुराणों की गाथा को लोग जान सकेंगे। संग्रहालय को इस तरह संचालित किया जाता है कि विभिन्न अवसरों पर आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। संग्रहालय में ओपन थिएटर व सभागृह भी हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी महाकाल मंदिर क्षेत्र को पर्यटन के नजरिए से विकसित कर रही है। संग्रहालय प्रबंधक डॉ. भावना व्यास बताती हैं कि संग्रहालय को और दर्शनीय बनाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न उपाय होंगे।

गौरतलब है कि त्रिवेणी संग्रहालय महाकाल मंदिर के समीप होने से इसे शिव, शक्ति और श्रीकृष्ण पर केंद्रित किया है। यहां शिव, देवी और श्रीकृष्ण से संबंधित चित्र व मूर्ति कला के अलावा अन्य पौराणिक व लोक संदर्भों को संग्रहित किया है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को ज्ञानवर्द्धक व शोधपरक जानकारी मिलती है। अब इसी कड़ी में यहां 18 पुराणों की चित्रमयी गाथा सजेगी। ताकी यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक पुराणों को जान और समझ सकें। पुरी के के आर्टिस्ट प्रहलाद महाराणा ने बताया कि उन्होंने उड़िया पट्ट शैली में विष्णु पुराण के चित्रों को तैयार किया है। कैनवास हाथों से तैयार करना पड़ता है। इसके लिए काथा गोंद मिलाकर वॉटर कलर तैयार किए जाते हैं। इससे 100 सालों तक पेंटिंग खराब नहीं होती। किशनगढ़ के रहने वाले शहजाद अली ने बताया कि पदम पुराण के संस्कृत का हिंदी अनुवाद कर उसे पढ़ा और कथा को समझा। मैंने 280 चित्र तैयार किए हैं। ज्यादातर पेंटिंग में स्टोन कलर का यूज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें ईश्वर के स्वरूपों और उनकी लीलाओं के जरिए उनकी महिमा और जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों की कुल संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग-अलग देवी-देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। इन्हें अब तक सिर्फ सुना या पढ़ा ही जाता है, लेकिन अब देश में पहली बार इनमें लिखी उपदेश नियमों को चित्रों के माध्यम से भी समझा जा सकेगा। मप्र संस्कृति विभाग इन पर देश के ख्यात 18 चित्रकारों से पेंटिंग्स तैयार करवा रहा है। नौ पुराणों पर अब तक काम पूरा हो चुका है और शेष पर चल रहा है। इन्हें उज्जैन स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में लगाया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय के क्यूरेटर अशोक मिश्रा ने बताया कि तैयार किए जा रहे चित्रों में सबसे ज्यादा चित्र श्रीमद्भागवत के हैं। इनकी संख्या 300 है और सबसे कम 25 चित्र अग्नि पुराण में हैं। भविष्य, नारद और मतस्य पुराण के लिए अब तक चित्रकार नहीं मिल पाए हैं।

त्रिवेणी संग्रहालय में शिव, देवी और श्रीकृष्ण से संबंधित पर्व-त्योहारों पर सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। संग्रहालय को इस तरह संचालित किया जाता है कि विभिन्न अवसरों पर आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। जब यहां पुराणों का चित्रण होगा तो यह अपने आप में आकर्षक होगा। अशोक मिश्रा के अनुसार कैलाश चंद्र शर्मा ने लिंग पुराण में लघु चित्र जैन शैली में 179 चित्र बनाए हैं, वहीं रघुपति भट्ट ने ब्रह्माण्ड पुराण में गंजिफा शैली में 48 चित्र तैयार किए हैं। विष्णु पुराण के चित्र उड़िया पट्ट शैली में प्रहलाद महाराण बना रहे हैं। इसमें 150 चित्रों के माध्यम से कथा को कहा गया है। मार्कण्डेय पुराण के 90 चित्रों को वैकुण्ठम नक्काश ने चेरियाल पट्टम शैली में तैयार किया है। विश्वनाथ रेड्डी ने ब्रह्म पुराण को कलमकारी में तैयार किया है, इस शैली में 90 चित्रों का संयोजन है। सुजीथ कुमार ने शिव पुराण के 50 चित्रों को केरला म्यूरल में तैयार किया है। वराह पुराण के 50 चित्र पद्मश्री भज्जू श्याम गोंड चित्र शैली में बनाए हैं। शहजाद अली ने पद्म पुराण के 280 चित्र किशनगढ़ शैली में तैयार किए हैं। गरुड़ पुराण की नाथद्वारा शैली में 50 चित्रों को नरोत्तम मिश्रा ने तैयार किया है। विजय शर्मा गुलेर शैली में भागवत पुराण के 250 चित्र तैयार कर रहे हैं। इसी तरह अग्नि पुराण के 27 चित्रों को मैसूर शैली में जेएस श्रीधर राव बना रहे हैं। वामन पुराण के 45 चित्रों को तंजावुर शैली में महेश राज और कूर्म पुराण के 50 चित्रों को एम रमेश राज नायका शैली में बना रहे हैं। शांति देवी झा स्कंद पुराण के 250 चित्रों को मधुबनी शैली में बना रही हैं, वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के 160 चित्रों को जयशंकर शर्मा बूंदी चित्र शैली में तैयार कर रहे हैं। कैलाश चंद्र शर्मा नारद पुराण को जोधपुर जैन शैली में तैयार करेंगे, इसमें 175 चित्र होंगे।

● बृजेश साहू

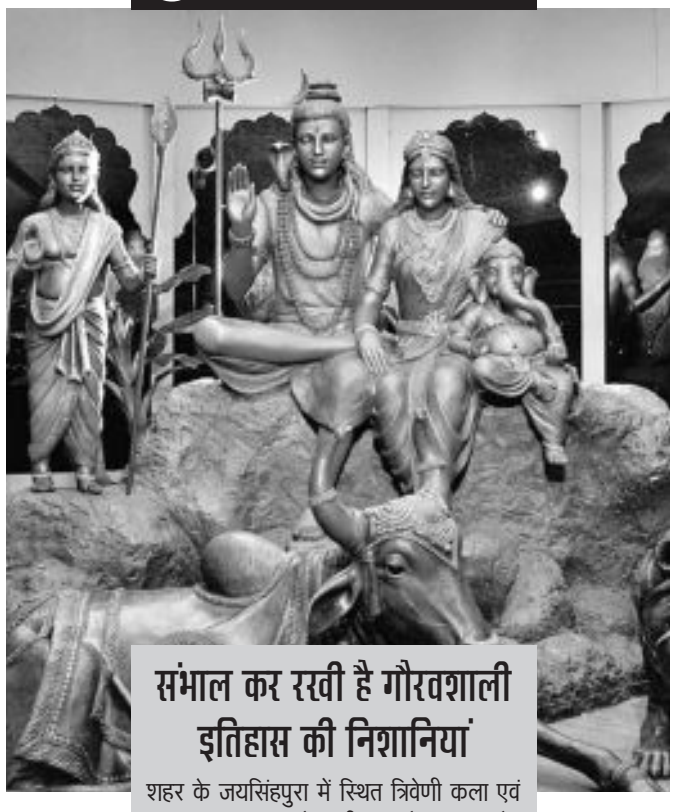

संभाल कर रखी है गौरवशाली इतिहास की निशानियां

शहर के जयसिंहपुरा में स्थित त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में प्राचीन उज्जैन शहर और सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास से संबंधित कई निशानियां, छायाचित्र, मूर्तियां और सिक्के सहेजकर रखे गए हैं। इन पर एक नजर डालने से ही मन गौरवांवित होने लगता है कि हमारा इतिहास कितना रोचक था और सम्राट विक्रमादित्य ने कई वर्षों तक जिस क्षेत्र में राज किया, उस अवंतिका क्षेत्र में हम आज रह रहे हैं। भारतीय अस्मिता के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य के समय (प्रथम सदी ईस्वीपूर्व) के समय की पुरातात्विक सामग्री जैसे- सीलें, मुद्राएं, मूर्तिलेख, शिलालेख, सिक्के और प्रचुर मात्रा में साहित्य संग्रहालय में उपलब्ध है। महाराजा विक्रमादित्य केवल एक नाम ही नहीं, बल्कि एक उपाधि के रूप में भी भारतीय शासकों को गौरवांवित करते रहे हैं। जन-सामान्य तक विक्रमादित्यकालीन सामाजिक और पुरातत्वीय सामग्री छायाचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने का यह एक प्रयास है। यह प्रदर्शनी अगले 15 दिनों तक त्रिवेणी संग्रहालय में लगाई जाएगी।

एलिजिबिलिटी नहीं सूटेबिलिटी चाहिए

मप्र में एक तरफ सरकार सुशासन के लिए नए-नए नवाचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जबसे प्रदेश में चौथी मंजिल का दबदबा बढ़ा है, प्रशासन में भर्राशाही और लालफीताशाही बढ़ गई है। आलम यह है कि अफसरों की पदस्थापना एलिजिबिलिटी की बजाय सूटेबिलिटी के तहत हो रही है। यानी चौथी मंजिल पर बैठने वाले बड़े साहब अपनी सहूलियत के अनुसार अफसरों को जिम्मेदारी देते हैं। दरअसल, जबसे साहब को नई पारी मिली है और उनकी वरिष्ठता सर्वोच्च हो गई है, तब से वे न तो किसी को भाव दे रहे हैं और न सुन रहे हैं। इस कारण प्रदेश की नौकरशाही में असंतोष देखा जा रहा है। आलम यह है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। अगर पुलिस विभाग की बात करें तो वह पूरी तरह चरमरा गई है। 4 जोन के आईजी बदलना है, लेकिन अभी तक मामला अधर में है। डीएसपी-आरक्षक की फाइल अटकी हुई है, तबादले रुके हैं। कई एसपी डीआईजी हो गए हैं, लेकिन फाइल अटकी हुई है। कई जिलों के एसपी की पदस्थापना के 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उनके तबादले कब होंगे, इसका कोई संकेत नहीं मिल रहा है। इससे अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है।

प्रदेश में स्थिति यह है कि कलेक्टर और एसपी जो कहते हैं, वही सही माना जाता है। अपराधों की समीक्षा होती है तो सबकुछ सही बताया जाता है। जबकि असलीयत यह है कि कोई भी जिला अपने यहां घटित होने वाले अपराधों की जानकारी नहीं दे रहा है। प्रदेश में अपराधों की स्थिति क्या है, यह रोजाना समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है। कलेक्टरों का भी लगभग यही हाल है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रदेश में सबकुछ अच्छा चल रहा है तो सरकार विकास यात्रा क्यों निकाल रही है। हालांकि विकास यात्रा के दौरान जनता के आक्रोश की जो तस्वीर रोजाना सामने आ रही है, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखना यह है कि एलिजिबिलिटी को दरकिनार कर सूटेबिलिटी वाला यह फॉर्मूला कब तक कायम रहता है।

● **कुमार राजेन्द्र**

आईएएस बन सकते हैं एनएएस!

प्रदेश के गैर राज्य प्रशासनिक सेवा (एनएएस) के अधिकारियों को बीते 6 साल से प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इस कारण करीब 70 अधिकारी बनने का सपना लिए ही रिटायर हो गए। साथ ही 100 से ज्यादा अधिकारी इस कतार में हैं। इस बीच प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का चयन आईएएस संवर्ग में करने के लिए 27 फरवरी को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। ये सभी पद वर्ष 2021 के हैं। अब सरकार इस प्रयास में है कि वर्ष 2022 के 14 पदों के लिए भी समिति की बैठक एक साथ हो जाए। इनमें छह पद आईएएस संवर्ग के पुनरीक्षण में प्राप्त हुए हैं। यदि केंद्र सरकार से अनुमति मिल जाती है तो गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी आईएएस बनने का मौका मिल सकता है। बता दें कि दरअसल राज्य प्रशासनिक सेवा का 439 अधिकारियों का कैडर है। इसमें से 33 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का नियम है। इनमें से 15 प्रतिशत पद गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरने का भी नियम बनाया गया है। लेकिन 2015 के बाद से गैर राज्य प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी आईएएस के पदों पर पदोन्नत नहीं हो सका है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से संबंधित विभागों से योग्य अधिकारियों के आवेदन ही नहीं मंगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार वर्ष 2022 के 14 पदों के लिए अनुमति दे देती है तो एनएएस के अधिकारियों की लॉटरी लग सकती है और वे आईएएस बन सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2016 से गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस नहीं बने हैं। आईएएस संवर्ग में चयन के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के साथ गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मौका दिया जाता है। 2016 में चार गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अवसर मिला था। कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में चार पद देने का प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन यह केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया। इसके बाद से केवल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही मौका मिल रहा है। इसको लेकर बार-बार मांग उठाने पर यही तर्क दिया जाता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, इसलिए अन्य संवर्ग के अधिकारियों के नामों पर विचार ही नहीं किया जा रहा है। जबकि, पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा का कहना है कि दूसरी सेवाओं के अधिकारियों को भी पर्याप्त अनुभव रहता है, जिसका सरकार को लाभ उठाना चाहिए।

सीनियर तहसीलदार बनेंगे डिप्टी कलेक्टर

मप्र सरकार 220 सीनियर तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर बनाने जा रही है। इसकी फाइल भी दौड़ रही है। संभवत: 25 फरवरी के बाद लिस्ट आ सकती है। ये तहसीलदार पिछले 7 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 1999 से 2008 के बीच के तहसीलदार इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। जिनकी विभागीय जांच चल रही है, वे डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। इधर, कुल 173 नायब तहसीलदारों को भी तहसीलदार का प्रभार दिए जाने की प्रोसेस चल रही है। बता दें कि मप्र राजस्व अधिकारी संघ पिछले एक साल से पुलिस विभाग की तर्ज पर तहसीलदारों को प्रमोशन देने की मांग उठा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री व मंत्री से गुहार लगाई जा रही थी। इसके बाद सरकार स्तर पर प्रोसेस शुरू की गई, जो अब अंतिम दौर में है। बताया जा रहा है कि जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग) में फाइल दौड़ रही है। वर्ष 1999 से 2008 के बीच जो नायब तहसीलदार बने और फिर तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हुए, लेकिन इसके बाद उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। उन तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया जाएगा, जिन पर जांच चल रही हो। यानि, ऐसे तहसीलदारों को मौका नहीं मिलेगा। मप्र राजस्व अधिकारी संघ की मानें तो वर्ष 1999 से 2008 के बीच एमपीपीएससी के जरिए नायब तहसीलदारों की भर्ती की गई थी, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। यदि नियम के अनुसार प्रमोशन होता तो दो बार पदोन्नति हो जाती। अब तक वे जॉइंट कलेक्टर बन चुके होते, लेकिन पदोन्नति रुकने के कारण डिप्टी कलेक्टर भी नहीं बन सके। वर्तमान में 220 तहसीलदार हैं, जो पदोन्नति का रास्ता देख रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं, जिन पर विभागीय जांच लंबित है। तहसीलदारों की कुर्सी खाली होने के बाद नायब तहसीलदारों को कार्यवाहक तहसीलदार बनाया जा रहा है। इसकी फाइल भी दौड़ रही है। इनकी संख्या 173 बताई जा रही है। संभवत: सीनियर तहसीलदारों की कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर बनाए जाने वाली लिस्ट के साथ ही नायब तहसीलदारों के कार्यवाहक तहसीलदार बनाने की लिस्ट भी आ सकती है। इधर, एक बार फिर आरआई (राजस्व निरीक्षक) को नायब तहसीलदार बनाने की प्रोसेस भी जारी है। पिछले साल अक्टूबर में प्रस्ताव भी बन चुका है। जिसमें क्राइटेरिया भी तय हो चुका है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक की स्थिति में नायब तहसीलदार के कुल 1242 पद मंजूर हैं।

मप्र में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में 51 फीसदी वोट को जो लक्ष्य रखा है उसे पाने के लिए पार्टी सरकार के नवाचारों का सहारा लेगी। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अब तक के कार्यकाल में सरकार ने ऐसे कई नवाचार किए हैं जिसके सहारे इस बार 200 सीटों का आंकड़ा पार किया जा सकता है। खासकर चौथी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितने नवाचार किए हैं उन्हें चुनाव के दौरान भुनाने की तैयारी की जा रही है।

'नवाचारों' से 51 फीसदी वोट का टारगेट

मप्र में नवंबर में चुनाव होंगे। इसके लिए पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार पार्टियों का सबसे अधिक फोकस महिला मतदाताओं पर है। क्योंकि 5 करोड़ 39 लाख 87 हजार 876 मतदाताओं में 2 करोड़ 60 लाख 23 हजार 711 महिला वोटर हैं। यानी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। हार-जीत का फैसला महिलाओं के हाथ में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के 41 जिलों में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा हो गई है। वहीं 18 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इस बार महिला वोटर जिस भी पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगी उस पार्टी की जीत आसान होगी।

वैसे तो भाजपा ने आगामी चुनाव के मद्देनजर हर वर्ग को साधने का फॉर्मूला बना रखा है। इसके लिए कई तरह के नवाचार किए गए हैं। इसी कड़ी में आधी आबादी का पूरा समर्थन और सत्ता बरकरार, इस फॉर्मूले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 15 साल बाद नए अंदाज में दोहराने की तैयारी में दिख रहे हैं। 2007 में अपनी पहली पारी में उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू कर बेटियों को आगे बढ़ाने की जो पहल की, उससे उन्हें 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में सफलता मिली। 2018 के चुनाव में हार से सबक लेते हुए इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे खासे सतर्क हैं और उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडली बहना योजना की घोषणा कर दी है। इसके तहत वह प्रदेश की उन सभी गरीब एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1000 रुपए देंगे, जो आयकर सीमा से बाहर हैं। एक अनुमान के मुताबिक मप्र में एक करोड़ से अधिक महिलाएं इस दायरे में आएंगी। ऐसे में सरकार पर प्रतिवर्ष 12 हजार करोड़ रुपए का खर्च बढ़ सकता है। योजना का प्रारूप अभी तैयार होना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आश्वस्त कर रहे हैं कि रक्षाबंधन तक लाडली बहनों के खातों में पैसे आने शुरू हो सकते हैं।

अलग-अलग समितियां भी गठित

प्रदेश में 51 फीसदी से अधिक वोट प्रतिशत पाने के लिए भाजपा ने हर वर्ग से जुड़ाव की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए हाल ही में संपन्न हुई प्रदेश कार्यसमिति के दौरान संगठन ने अलग-अलग समितियां भी गठित की हैं। इन समितियों की एक-एक मंत्री को जवाबदारी सौंपी गई है। इसमें जनाधार बढ़ाने पार्टी से नए लोगों को जोड़ने के लिए डॉ. नरोत्तम मिश्रा को जवाबदारी दी गई है। हारी सीटों पर जमावट विश्वास सारंग, युवा वोटर्स जोड़ने डॉ. मोहन यादव, समाजों से संपर्क के लिए भारत सिंह कुशवाहा, सरकार की योजनाओं की ब्रांडिंग व हितग्राहियों को लुभाने अरविंद भदौरिया, बुद्धिजीवियों के बीच पार्टी की ब्रांडिंग व फीडबैक जगदीश देवड़ा, बूथ मजबूती और सोशल मीडिया का दायरा फैलाने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और महिलाओं के बीच पार्टी का जनाधार बढ़ाने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मिशन 2023 को साधने के लिए भाजपा ने किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि सभी वर्गों को साधने का जतन किया है। इसके लिए हर वर्ग के लिए नवाचार किए गए हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग तरीके की सोशल इंजीनियरिंग पर काम करते रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना हो या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, किसानों को सम्मान निधि के साथ अतिरिक्त 4000 रुपए देने हों या हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन कर 12 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, इसी तरह खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच भी शिवराज सरकार नए तरीके का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आयु, आमदनी और जीवन शैली के आधार पर अलग-अलग वर्गों को खुश कर अपने साथ जोड़ने का कोई मौका नहीं गंवाते।

अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अब तक के कार्यकाल का आंकलन किया जाए तो यह तथ्य सामने आता है कि उन्होंने आधी आबादी पर पूरा फोकस किया है। उनके अधिकांश नवाचार महिलाओं के लिए ही हैं। महिलाओं और बच्चियों के बीच उनकी मामा की छवि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिवराज सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर शासकीय सेवाओं तक में महिलाओं को 33 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की है। आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वसहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल भी हो चुकी है। इसके अलावा आदिवासी वर्ग सहरिया-भारिया महिलाओं को भी प्रतिमाह एक हजार रुपए देने के साथ रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शिवराज लंबे समय से दुराचारियों को फांसी की

सजा के पक्षधर रहे हैं। बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मप्र में 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। इस योजना ने पूरे देश में लोकप्रियता हासिल की थी और कई राज्यों ने इसे अलग-अलग नामों से लागू भी किया। आदिवासी क्षेत्रों के लिए पेसा एक्ट लागू करने में भी महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय पर कड़ी सजा का प्रविधान है। आदिवासी महिलाओं से शादी कर पंचायत चुनाव लड़ने या जमीन खरीदने की मंशा रखने वालों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त चेतावनी दी है। इन प्रयासों के बाद लाडली बहना योजना शिवराज सरकार का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है, जो भाजपा को 51 प्रतिशत वोट शेयर दिलाने में महत्वपूर्ण रूप से कारगर साबित हो सकता है।

मप्र में अगले 3 महीने के लिए रोडमैप तैयार हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट आवंटन, व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। चुनावी साल में प्रदेश सरकार का फोकस आदिवासियों पर रहेगा। इसके लिए अगले तीन माह के लिए **रोडमैप तैयार किया गया** है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के जनवरी माह के लिए पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा निर्धारित की गई है। जिसमें ऊर्जा विभाग को 251 करोड़, जनजाति कार्य विभाग को 160 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 102 करोड़ आवंटित किया गया है।

बता दें कि मप्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। 2018 के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भाजपा ने पिछले डेढ़ साल में आदिवासियों को साधने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश में आदिवासी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। मप्र में आदिवासियों की आाबादी करीब 2 करोड़ है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।

मप्र में भाजपा ने 200 से अधिक सीटें जीतने का जो टारगेट सेट किया है, उसके लिए मतदाताओं से सीधे जुड़ाव के लिए पार्टी ने जनता के सहयोग से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यानी पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में दानदाताओं से आर्थिक सहयोग लेगी। इसके लिए संगठन की ओर से पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं रतलाम विधायक चेतन कश्यप को फंड जुटाओ समिति की जवाबदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि लगभग हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा जनता से फंड लेती है। इसके पीछे पार्टी का उद्देश्य होता है कि ऐसा करने से एक तो हर मतदाता तक पार्टी पहुंचती है और सहयोग राशि देने वाला मतदाता पार्टी को वोट जरूर देता है। यानी भाजपा का यह उपक्रम एक तरह से वोट का सर्वे भी होता है। इस बार भी भाजपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फंड जुटाएगी।

उल्लेखनीय है कि भाजपा कोई भी चुनाव पूरी ताकत और तन्मयता से लड़ती है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तैयारी से जुट गई है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी समर्थकों और अपने कार्यकताओं से फंड भी जुटाएगी। इसके लिए हर विधानसभा में ऐसे दानदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है जो पार्टी के लिए आर्थिक मदद भी दे सकें। पार्टी के नए-पुराने कार्यकताओं से भी चुनाव के लिए मदद करने को कहा जाएगा। जिलाध्यक्षों को क्षेत्रीय संभावनाओं के हिसाब से टारगेट भी दिए जाएंगे। संगठन की ओर से पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं रतलाम विधायक चेतन कश्यप को फंड जुटाओ समिति की जवाबदारी सौंपी गई है। भाजपा अभी पार्टी के खर्चों के लिए कार्यकताओं से हर साल आजीवन सहयोग निधि एकत्र करती है। लेकिन अब चुनावी खर्चों के लिए भी समर्थकों और कार्यकताओं से राशि जुटाई जाएगी। जल्दी ही इस अभियान के लिए समिति गठन कर सभी जिलों को विधानसभावार धन जुटाने की भी जवाबदारी सौंपी जाएगी। पार्टी का मानना है कि मिशन 2023 की सफलता के लिए इस अभियान से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जो भी व्यक्ति पार्टी को आर्थिक सहयोग देंगे उनका जुड़ाव भी बढ़ेगा। रतलाम विधायक कश्यप का कहना है कि पारंपरिक रूप से पार्टी को समर्थकों और कार्यकताओं की आर्थिक मदद भी मिलती है। इस बार इसे हर विधानसभावार एकत्र करेंगे। पार्टी के जितने भी शुभचिंतक हैं उनसे संपर्क किया जाएगा और पारदर्शी तरीके से धन संग्रह करेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें जिलाध्यक्षों को भी जवाबदारी सौंपी जाएगी और अलग-अलग समिति भी गठित करेंगे।

● **कुमार विनोद**

अभियान से सधेगा हर वर्ग

मप्र में विधानसभा चुनाव की सियासी चौसर पर अब जातिगत और समुदाय विशेष की राजनीति केंद्र में आ गई है। भाजपा जातियों और वर्गों को रिझाकर अपने वोट बैंक को मजबूत कर चुनावी नैय्या पार लगाने में जुट गई है। इसके तहत सत्ता-संगठन के नेताओं ने चुनावी साल में मैदानी स्तर पर सभी वर्गों तक पहुंच बढ़ाने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है। सरकार ने भी हाल ही में एक साथ कई योजनाओं का ऐलान कर दलित-आदिवासी वर्ग में खासतौर पर युवाओं को अपना कारोबार स्थापित कर उद्यमी बनाने का संकल्प भी जताया गया है। प्रदेश के सभी जिलों से 20 हजार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन के लिए भेजने का कार्यक्रम जारी हो चुका है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल ने मैदानी स्तर पर बूथ सशक्तिकरण के साथ 51 फीसदी वोट शेयर बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम घोषित किए हैं। सरकारी स्तर पर भी एक साथ कई महीनों के कार्यक्रम और योजनाएं घोषित की गई हैं। इनमें जिला स्तर पर प्रशासनिक अमले के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को भी अपनी भूमिका निभाने और जन सामान्य से लाइव संपर्क करने की समझाइश दी गई है। पार्टी का मानना है कि इस नए अभियान से पार्टी हर वर्ग को साध पाएगी।

बिल्डिंग परमिशन की झंझट खत्म

मप्र सरकार बिल्डिंग परमिशन लेने में आने वाली दिक्कतों को खत्म करने के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके तहत जल्द ही 105 वर्गमीटर यानी 1127 वर्गफीट तक के भूखंड पर डीम्ड बिल्डिंग परमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। न तो आर्किटेक्ट के पास जाने की जरूरत होगी और न ही नगर निगम। ऑनलाइन नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन फीस जमा करना ही परमिशन होना माना जाएगा। गौरतलब है कि मौजूदा सिस्टम में निजी आर्किटेक्ट की ओर से एबीपीएएस 2 में मकान या भवन की ड्राइंग अपलोड की जाती है। यह स्क्रूटनी के लिए सीधे बिल्डिंग परमिशन की डीसीआर सेल में पहुंच जाती है। वहां देखा जाता है कि नियमानुसार ड्राइंग बनाई गई है या नहीं। जरूरत होने पर सुधार की सिफारिश की जाती है। इसमें बिल्डिंग परमिशन के किसी इंजीनियर या अन्य अधिकारी का कोई दखल नहीं होता है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने महाराष्ट्र और दिल्ली की तर्ज पर इस सुविधा को शुरू करने के लिए मप्र भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन का खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत आवेदक को विभाग की वेबसाइट पर ऑटोमैटिक बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (एबीपीएस) सॉफ्टवेयर में आवेदन देना होगा। यहां पर मॉडल नक्शे का चयन करना होगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्लॉट का प्रॉपर्टी टैक्स देखकर फीस की गणना करेगा। फीस जमा करते ही इंस्टेंट एंड डीम्ड टू बी के नाम से परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। न तो इसमें किसी आर्किटेक्ट की जरूरत होगी और न ही फाइल बिल्डिंग परमिशन के अफसरों के पास जाएगी।

सरकार का लक्ष्य छोटे प्लॉट मालिक हैं। यह इतने सक्षम नहीं होते कि इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स के चक्कर काटें। दूसरा, छोटे प्लॉट पर बिल्डिंग परमिशन का उल्लंघन से ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है। भूमि विकास नियम में परमिशन की फीस तय करने के लिए 32, 48, 75, 105, 288 वर्गमीटर आदि के स्लैब बनाए गए हैं। लिहाजा स्लैब को देखते हुए 32 से 105 वर्गमीटर तक की एरिया रखा गया। अभी दो तरह से बिल्डिंग परमिशन जारी होती है। पहले में 300 वर्गमीटर तक मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट या नगर निगम से परमिशन लेनी होती है। जबकि इससे ऊपर में सिर्फ निगम ही परमिशन देता है। नगर निगम में ऑनलाइन आवेदन के बाद ड्राफ्टसमैन, बाबू, सब इंजीनियर से लेकर सिटी प्लानर तक फाइल जाती है, फिर इसी तरह फाइल वापस आती है। इसके बाद फीस की सूचना जारी होती है। सभी स्टेज से गुजरने में कम से कम 25 दिन लगते हैं। अब आप सरकार के मॉडल नक्शे या आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाएंगे तो वह नियमों के तहत बना हुआ होगा। ऐसे में सरकार मानकर चल रही है कि इसकी जांच की जरूरत नहीं होगी। चूंकि टीएंडसीपी स्वीकृत कॉलोनी के प्लॉट ही इस सुविधा के लिए पात्र होंगे, इसलिए पहले ही नजूल समेत सारी परमिशन मिल चुकी होगी। हां, नगर निगम के इंजीनियरों को यह अधिकार होगा कि वह मकान बनने की बाद जांच कर सकें।

प्रदेश में जल्द ही 105 वर्गमीटर तक के भूखंड पर डीम्ड बिल्डिंग परमिशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी फाइल नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के पास पहुंच गई है। जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव के मेनिफेस्टो में 105 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर डीम्ड परमिशन देने का वादा किया था। मंशा यह थी कि छोटे प्लॉट मालिकों को भवन निर्माण की अनुमति के लिए निगम दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। सिस्टम में पारदर्शिता आए और लेन-देन की शिकायतों पर लगाम लग सके। इसके बाद शासन ने पिछले साल अक्टूबर में 105 वर्गमीटर तक डीम्ड परमिशन देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हालांकि, चार महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी किसी निकाय में इसका फायदा नहीं मिल पाया है। बिल्डिंग परमिशन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से शासन ने डीम्ड परमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि, इसके मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम अपडेट न हो पाने की वजह से यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। इसका नुकसान यह हो रहा है कि इस आकार तक के प्लॉट मालिकों को ड्रॉइंग-डिजाइन के लिए पैसा खर्च करने के साथ ही आर्किटेक्ट व निगम के इंजीनियरों-कर्मचारियों के आगे-पीछे घूमना पड़ रहा है। राजधानी की बात करें तो हर साल करीब चार हजार बिल्डिंग परमिशन जारी होती हैं। अधिकारियों के मुताबिक इसमें 50 फीसदी से ज्यादा एक हजार वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए होती हैं। बदलाव लागू न होने से ऐसे आवेदकों को परेशान होना पड़ रहा है।

प्रस्तावित नियमों के **तहत डीम्ड परमिशन** के लिए तय प्रारूप में आवेदन व शपथ पत्र देना होगा। मास्टर प्लान व नियमों के मुताबिक मकान की ड्रॉइंग होना चाहिए। शुल्क लेते समय स्थानीय निकाय किसी प्रकार का निरीक्षण या दस्तावेज परीक्षण नहीं करेगा। अपूर्ण दस्तावेज या कोई अन्य जानकारी बाद में ले सकेंगे। निर्माण पूरा होने के बाद कार्य पूर्णता की सूचना लिखित में देना होगी। नियम विरूद्ध निर्माण पर डीम्ड अनुमति खुद ब खुद निरस्त हो जाएगी और अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा।

● **सिद्धार्थ पांडे**

नेतागिरी पर लगेगी लगाम

नगरीय निकायों में नीचे के कैडर पर नकेल कसने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि निकायों द्वारा नीचे के कैडर की जो भर्तियां की जाती हैं **उन पर कार्यवाही परिषद करती है।** लेकिन अब परिषद के साथ आयुक्त को भी उन पर कार्यवाही करने का अधिकार होगा। इससे निकायों में होने वाली नेतागिरी पर लगाम लग सकेगी। वहीं निकायों में आपदा से निपटने के लिए 216 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। इस फंड से ऊंची बिल्डिंगों पर आपदा आने से निपटने के संसाधन जुटाए जाएंगे। जल्द ही राहत आयुक्त भरत यादव और गृह सचिव के साथ एक बैठक होगी। बैठक में नगरीय प्रशासन व विकास विभाग प्रेजेंटेशन देगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

दिग्विजय का नाथ विरोधी अभियान करेगा बंटाधार...

2020 में सत्ता छिनने के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ निरंतर इस कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देकर सरकार बनाए। इसके लिए वे लगातार सक्रिय हैं और पूरी पार्टी को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन उनके मिशन में भाजपा से पहले कांग्रेसी ही बाधा डाल रहे हैं। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक नेता कमलनाथ के मिशन का बंटाधार कर रहे हैं।

विधानसभा चुनाव को करीब 9 माह का समय ही बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस संगठन को मजबूत कर चुनाव की तैयारी में जुटना है। कमलनाथ भी इसी अभियान में लगे हुए हैं। ऐसे में दिग्विजय समर्थक दो नेताओं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और जीतू पटवारी ने कमलनाथ को सवालों के घेरे में लाकर पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे दिग्विजय सिंह की सोची-समझी रणनीति है। यह समय चुनावी तैयारी का है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी कांग्रेस के नेताओं में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही प्रदेश कांग्रेस को उनके ही दो पूर्व मंत्रियों ने झटका दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया है। मुख्यमंत्री पर फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी आलाकमान करता है। यही बात पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी दोहरा चुके हैं। लेकिन जब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सवाल किया तो वे बचकर निकल गए, बोले- मुझसे अरुण यादव ने कुछ नहीं पूछा। ज्ञात रहे कि पूरी प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही है। बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टर में उन्हें अगला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। लेकिन उनके नाम को लेकर पार्टी में ही सभी नेता एकमत नहीं हैं। पूर्व मंत्री यादव ने साफ कहा कि अभी नाथ पीसीसी चीफ हैं और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस मामले में भोपाल में मौजूद दिग्विजय सिंह से मीडिया ने सवाल किया तो वे सवाल का सीधा जवाब देने से बचकर निकल गए।

यह समय कांग्रेस का एकजुट होकर भाजपा से मैदानी जंग का है। लेकिन ऐसी समय में भी दिग्विजय समर्थक दो नेता कमलनाथ को घेरने में लगे हुए हैं। खासकर जीतू पटवारी ने तो नाथ के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। एक तो इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी में जबरदस्त घमासान चल रहा है। ये घमासान भी किसी और के नहीं बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच हो रहा है। मामला इतना बढ़ चुका है कि अब इंदौर का मसला दिल्ली तक पहुंच गया है। और वहां लॉबिंग हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन दूसरी ओर मप्र में कांग्रेस नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई। प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष को लेकर नेताओं के बीच घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अपने करीबी नेता को शहर अध्यक्ष बनवाने के लिए भोपाल नहीं बल्कि दिल्ली में लॉबिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अभी अरुण यादव के बयानों पर कमलनाथ के मैनेजर डैमेज कंट्रोल कर ही रहे थे कि जीतू पटवारी ने यह कहकर कमलनाथ की रणनीति पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया कि वे अभी भी प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। जीतू पटवारी का तर्क है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। उदयपुर में की गई घोषणा के अनुसार यह नियुक्ति 5 वर्ष तक चलेगी। इसलिए वे अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जीतू पटवारी का बयान स्पष्ट रूप से कमलनाथ के खिलाफ बगावत है, क्योंकि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पुनर्गठन किया गया उसमें जीतू पटवारी को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने ऐलान करके कार्यकारी अध्यक्ष प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसी कारण चारों कार्यकारी अध्यक्षों को प्रदेश में उपाध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। जीतू पटवारी इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि प्रदेश में 55 उपाध्यक्ष हैं इस संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। ऐसे में उन्हें भीड़ में पदाधिकारी बनने में कोई रूचि नहीं है।

● **प्रवीण सक्सेना**

दोनों के पीछे दिग्विजय...

देश और प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का कद इतना बड़ा है कि कोई प्रादेशिक स्तर का कांग्रेसी नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलने में सौ बार सोचेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अरुण यादव और जीतू पटवारी की मोर्चाबंदी के पीछे दिग्विजय सिंह का हाथ है। अरुण यादव और जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं। इसलिए इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये दोनों नेता अपने मन से खुलेआम कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी करें? जाहिर है जब तक दिग्विजय सिंह की ओर से संकेत नहीं मिलेगा ये नेता शक्तिशाली कमलनाथ के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकते। अरुण यादव और जीतू पटवारी ही नहीं दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी समय-समय पर कमलनाथ के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बयान देते रहते हैं। कमलनाथ और गोविंद सिंह के बीच तकरार तब सामने आई थी जब गोविंद सिंह ने मानसून सत्र के दौरान बिना कमलनाथ की सहमति के अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था। कमलनाथ इस ऐलान से इतने असहज हो गए कि उन्होंने विधानसभा सत्र में भाग ही नहीं लिया। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव महज एक नाटक बनकर रह गया। समय-समय पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच भी तल्खी सामने आती रही है लेकिन यह दोनों अत्यंत अनुभवी और परिपक्व नेता हैं। इस कारण से इनके मतभेद सतह पर नहीं आते हैं, लेकिन समय-समय पर इनके समर्थक बयानबाजी करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा और उमंग सिंगार ने अतीत में कई बार तीखी बयानबाजी की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जब समापन हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया के समक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को गले लगने के लिए कहा था।

अब पांच वर्षों के लिए रेत खदानों के ठेके

सरकारी खजाने को भरने के लिए प्रदेश सरकार नई रेत नीति लाने की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही प्रदेश में नई रेत नीति देखने को मिलेगी। इस बार जिले में एकल ठेका देने के स्थान पर राज्य की शिवराज सरकार तहसील एवं पंचायत स्तर पर छोटे-छोटे ठेके देने की तैयारी कर रही है। इससे रेत की उपलब्धता भी आसान होगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। खनिज संसाधन विभाग नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसमें जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर ठेका देने के विकल्प पर और लाभ हानि व इसकी चुनौतियों को लेकर चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि उप्र की रेत नीति के प्राविधानों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। विभाग में अधिकारियों का एक दल वहां की नीति को समझने के लिए उप्र भेजा था। इसके अलावा पीएम आवास योजना के लिए मुफ्त रेत बांटने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। रेत सहित अन्य खनिजों के उत्खनन के लिए नदी के आकार, हर साल जमा होने वाली रेत की मात्रा, रेत निकालने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, क्षेत्र की जनसंख्या सहित 32 बिंदुओं पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिसे सार्वजनिक कर दावे-आपत्ति मांगे जाएंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर उत्खनन की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसका अनुमोदन राज्य पर्यावरण मूल्यांकन समिति (स्टेट इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी) करेगी।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार नई रेत नीति बनाने में जुट गई है। इस बार जिले में एकल ठेका देने के स्थान पर तहसील एवं पंचायत स्तर पर छोटे-छोटे ठेके देने की तैयारी है। इससे रेत की उपलब्धता आसान होगी और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि संभावित है। खनिज संसाधन विभाग नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसमें जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर ठेका देने के विकल्प लाभ, हानि और चुनौती के साथ सुझाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में रेत नीति बनाई थी, जिसमें जिलास्तर पर खदानों का समूह बनाकर नीलामी की गई थी। कम समय के लिए खदान मिलने के कारण ठेकेदारों ने रेत के दाम बढ़ाकर रखे। ताकि रॉयल्टी की राशि निकालने के साथ अच्छी बचत भी हो सके।

खदानों से तय मात्रा में ही रेत निकाली जाए, यह जिम्मा कलेक्टरों का रहेगा। इसलिए जिला खनिज अधिकारी हर माह खदानों का निरीक्षण करेंगे। वहीं रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नजर रखी जाएगी। कलेक्टर इसकी भी रिपोर्ट लेंगे। नई रेत नीति के लिए विभाग ने जो विकल्प सुझाए हैं उनमें जिलास्तर पर राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावना है, लेकिन जिलेवार निविदा करने से छोटे उद्यामियों की सहभागिता नहीं होगी। ठेका असफल होने पर पूरे जिले की रेत आपूर्ति एवं शासन का राजस्व प्रभावित होगा। तहसील स्तर पर निविदा करने पर छोटे उद्यमियों की सहभागिता होगा। ठेका असफल होने पर पूरे जिले की रेत आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। प्रतिस्पर्धा होने से बाजार दर पर नियंत्रण रहेगा। वहीं जिला समूह से कम राजस्व अपेक्षित, लेकिन ठेकों की निरंतरता होने से पंचायत स्तर से अधिक राजस्व होना संभावित है। हालांकि, इससे जिले में एक से अधिक ठेके होने पर बाजार नाकों पर नियंत्रण संबंधी विवाद और बाजार मूल्य पर नियंत्रण नहीं होगा।

जानकार बताते हैं कि इस बार की रेत नीति में भी खनिज नाकों का प्रविधान करने पर विचार किया जा रहा है। नाके लगाने के साथ उन पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे नाकों से गुजरने वाली रेत की गाड़ियों की निगरानी तो होगी ही, अवैध परिवहन और झगड़ों की स्थिति पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी आसानी होगी। पंचायत द्वारा खदानों की ई-नीलामी एवं ठेकेदारों के माध्यम से खदान का संचालन करने पर पंचायतों की खदान संचालन में सहभागिता होगी और स्थानीय रोजगार सृजित होगा। इससे राजस्व में कमी होगी। ठेकेदारों की संख्या अत्यधिक होने के कारण पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य पर्यावरणीय प्रविधानों के पालन कराने में कठिनाई होगी। पंचायतों को अनुभव न होने के कारण ठेकेदारों पर नियंत्रण कठिन एवं प्रविधानों के पालन में कठिनाई होगी। निकट की पंचायतों एवं ठेकेदारों से विवाद, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं होगी।

प्रदेश में वर्तमान में जारी रेत नीति से औसत खपत से लगभग दोगुनी मात्रा के ठेके हैं। समूह में शामिल कई **खदानों की वैधानिक** स्वीकृतियां प्राप्त होने में कठिनाई आई। इससे किस्त भरने में कठिनाई होती है। 22 जिलों के ठेके किस्त न भरने के कारण निरस्त हुए। ठेका निरस्त होने से संपूर्ण जिले की रेत आपूर्ति प्रभावित होती है और राजस्व को भारी नुकसान होता है। बड़े ठेके होने से अधिक साझेदार और आपसी विवाद होता है। बता दें कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले रेत की नई नीति को लागू किया जा सकता है। इस नई नीति में तहसील स्तर पर रेत खदानों के समूह बनाकर नीलामी की जाएगी। नीलामी स्थानीय स्तर पर होगी। जिसके पूरे अधिकार कलेक्टर को रहेंगे। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से होगी। वर्षाकाल के बाद कलेक्टर रेत सहित जिले में मौजूद अन्य खनिजों के भंडारण की स्थिति का भी आंकलन शुरू कर देंगे।

● **राकेश ग्रोवर**

उप्र की रेत नीति का अध्ययन

प्रदेश की नई रेत नीति में उप्र की रेत नीति के प्रविधानों को भी इसमें शामिल करना प्रस्तावित है। विभाग ने अधिकारियों का दल वहां की नीति को समझने के लिए भेजा था। हाल ही में प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव भी उप्र की रेत नीति देखने गए थे और वे उप्र की रेत नीति से खासे प्रभावित हैं। उप्र में ई-नाके और चौकियों से रेत के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर नजर रखी जाती है। इससे रेत के अवैध कारोबार पर लगाम लगी है। अब यह व्यवस्था मप्र में लागू करने की तैयारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले मकानों के लिए मुक्त में रेत उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि वर्तमान में 12 ठेकों की अवधि 30 जून एवं 12 अन्य ठेकों की अवधि 30 अगस्त 2023 तक है।

दीदी दे रही दर्द

भाजपा के सामने दुविधा की स्थिति

उमा भारती की राजनीति का अपना एक अलग तरीका है। वे भाजपा के सामने खड़े होकर विरोध न करके भी भाजपा के खिलाफ परोक्ष रूप से दांव चल रही हैं। वे भाजपा के उस 'राम अभियान' को भी चोट पहुंचा रही हैं, जो पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने यहां तक कहा कि राम और हनुमान भाजपा के कॉपीराइट नहीं हैं। यह दोनों भगवान पुरातन काल से हिंदुओं की आस्था के प्रतीक रहे हैं और इन्हें भाजपा ने नहीं बनाया। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए कई तर्क दिए। जहां तक तर्कों की बात है, उमा भारती के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि, वे बचपन से धार्मिक प्रवचनकार रही हैं। इसलिए उन्हें वे सारे धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ हैं, जिनके आधार पर वे कभी भी किसी से भी बहस कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब कांग्रेस के लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया और भाजपा के लोगों ने उसका विरोध किया था, तब सबसे पहले मैंने ही कहा था कि राम सबके हैं राम के भक्त कहीं भी हो सकते हैं।

मप्र में 51 फीसदी वोट के साथ भाजपा ने 200 से अधिक सीटें जीतने का जो लक्ष्य बनाया है, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बगावती सूर भारी पड़ सकता है। गौरतलब है कि उमा भारती शराबबंदी, कभी राम, कभी गाय, तो कभी जाति को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। इससे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है। वहीं उमा भारती की इस बगावत को प्रदेश का सबसे बड़े वोट वाला ओबीसी समाज अपनी उपेक्षा मानने लगा है। खासकर लोधी समाज तो उमा भारती के साथ खड़ा है। ऐसे में भाजपा को उमा करीब 50 सीटों पर नुकसान पहुंचाती नजर आ रही हैं।

वैसे तो भाजपा को इस बार के विधानसभा चुनाव में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन, सबसे बड़ी चुनौती है उमा भारती का बदलता नजरिया। अब वे खुलकर मैदान में आने की तैयारी में हैं। चुनावी साल में मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बगावती सुर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। उमा भारती सरकार चला चुकी हैं और जानती हैं कि शराबबंदी लागू करना आसान नहीं है। इसके बावजूद शराबबंदी के जरिए भाजपा सरकार को घेरने में जुटी है। उमा का यह बागी रुख भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है? उमा भारती लोधी समुदाय से आती हैं, जो बुंदेलखंड और निवाड़ के 17 जिलों में काफी प्रभावी हैं। मप्र विधानसभा के करीब 50 सीटों पर लोधी वोटर्स असरदार हैं। इसी वजह से भाजपा के नेता उमा के खिलाफ सीधे बयानबाजी से परहेज कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर उमा शराबबंदी अभियान के जरिए 6 महीने में अपनी छवि बनाने में फिर से कामयाब रहती हैं, तो भाजपा को नुकसान होना तय है। बुंदेलखंड और निवाड़ इलाकों में उमा की पकड़ अभी भी मजबूत है और शराबबंदी अभियान से सीधे तौर पर महिलाएं जुड़ी हैं।

पार्टी के अंदर सुलग रही उमा भारती लंबे समय से अलग-अलग तरीकों से भाजपा को परेशान करने में लगी हैं। न सिर्फ संगठन को, बल्कि सरकार को भी वे अपने शराबबंदी अभियान से परेशान कर रही हैं। कई बार उन्हें शराब की दुकानों पर पत्थर चलाते देखा जाता है। उमा ने **बागी रुख अख्तियार** करते हुए कहा है कि शराबबंदी नहीं हुई तो आगे जो होगा, वो सब देखेंगे। उमा की चेतावनी पर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में सवाल पूछा गया तो वे जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा दिए। उमा और शिवराज के बीच सियासी द्वंद्व नया नहीं है, लेकिन चुनावी साल में उनके बागी रुख से हाईकमान की टेंशन जरूर बढ़ सकती है। 22 दिसंबर 2022 को उमा ने कहा था कि भाजपा के लोग उप्र और मप्र के चुनाव में मेरा फोटो दिखाकर लोधियों से वोट मांगते हैं। आम दिनों में मेरी तस्वीर पोस्टर पर नहीं लगाया जाता है, लेकिन चुनाव में जरूर लगता है। 28 दिसंबर 2022 को कहा था कि मैं चुनाव में वोट मांगने जरूर आऊंगी, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगी कि लोधियों तुम भाजपा को वोट दो। आप सभी लोग मेरी तरफ से राजनीतिक बंधन से पूरी तरह से आजाद हैं। 2014 में भाजपा की बंपर जीत के बाद उमा भारती को मोदी कैबिनेट में गंगा सफाई और जल विभाग का मंत्री बनाया गया। उमा इसके बाद मप्र और उप्र की स्थानीय राजनीति से दूर होती गईं। 2018 में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इस वजह से 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया। संन्यास की घोषणा के बाद कुछ साल तक उमा राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन अब फिर सक्रिय हो गई हैं।

निसंदेह यह उमा भारती की सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पिछले दिनों उमा भारती ने अपने समाज के एक कार्यक्रम में संदर्भ से अलग हटकर वहां मौजूद लोगों से कहा कि वे उनके कहने से भाजपा को वोट न दें! उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे पार्टी से बंधी हैं, इसलिए वे तो भाजपा को वोट देने के लिए कहेंगी, लेकिन उन्हें जिस भी पार्टी को देना है, उनको वोट दें। इसका सीधा-सा मतलब समझा जा सकता है कि वे मप्र के 9 फीसदी लोधी वोटरों को भाजपा से काटना चाहती हैं, जो अभी तक भाजपा के साथ रहे हैं। जिसके पीछे उमा भारती रही हैं। चुनावी साल में उनका ये मुद्दा अंडर करंट बन सकता है। उमा भारती के इस अभियान को महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। भाजपा का मजबूत माना जाने वाला महिला वोट बैंक यदि उससे छिटका तो बदलावकारी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि टीकमगढ़ और बुंदेलखंड के स्थानीय राजनीति में भी उमा भारती का सियासी वजूद शून्य में पड़ गया था। भतीजे राहुल लोधी के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के बाद वहां की परिस्थितियां भी सही नहीं है। संन्यास लेने के बाद हाईकमान से पूछ नहीं होना है। दरअसल, उमा भारती इस उम्मीद में थी कि सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद उन्हें किसी संवैधानिक पद पर भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमा भारती अब शराबबंदी के मुद्दे को आगे कर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदुत्व की फायर ब्रांड चेहरा होने की वजह से उमा को इसमें फुटेज भी मिल रहा है।

● **विकास दुबे**

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मप्र बनाने का जो अभियान शुरू किया है, उसे वे इस साल हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए इस चुनावी साल में मॉडर्न बजट बनाया जा रहा है। यानी इस बजट में विकास और जनकल्याण पर सबसे अधिक फोकस किया जा रहा है, ताकि जनता के विश्वास पर सरकार 100 फीसदी खरी उतर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा-निर्देश पर अधिकारी बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।

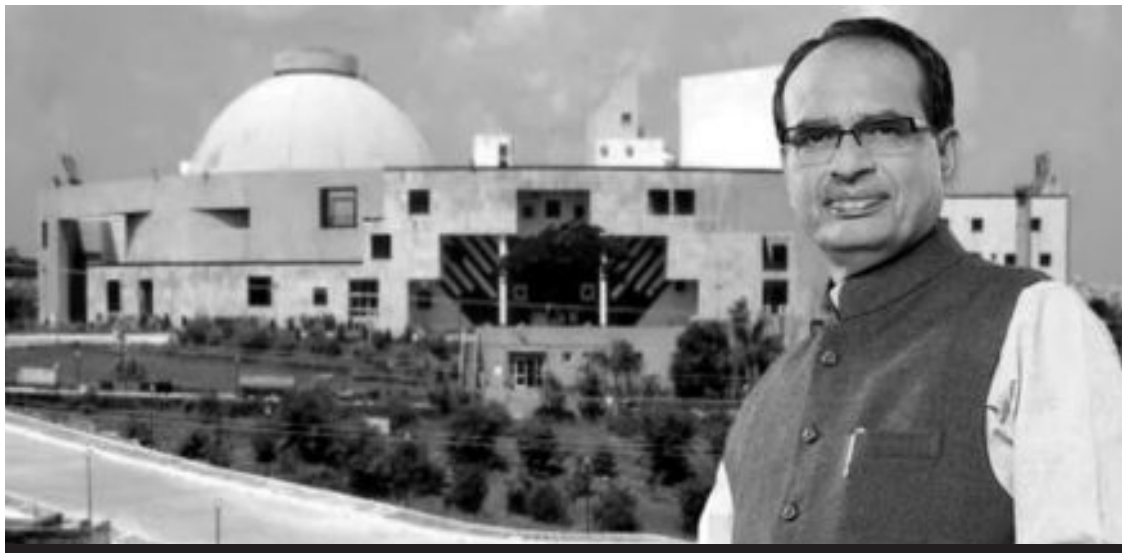

मप्र में इस बार चुनावी बजट...

चुनावी साल में मप्र का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। इस दौरान मप्र का बजट भी पेश किया जाएगा। वित्त विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार तकरीबन सवा तीन लाख करोड़ का बजट होगा, जो मॉडर्न बजट होगा। यह बजट अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला होगा। जिसमें विकास और जनकल्याण पर जोर दिया जाएगा। विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश का बजट तैयार करने संबंधी प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए। जिसमें विकास, कृषि और ग्रामीण आदि बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस साल बजट में आदिवासियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार दिलाने की हमारी प्राथमिकता होगी। 48 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अधो-संरचना विकास पर खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हमारी कोशिश भारत सरकार के बजट में प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने की रहेगी। प्रदेश में चार टूरिस्ट सर्किट विकसित होंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खास बात ये है कि, मप्र की शिवराज सरकार का खास फोकस सूबे के आदिवासी समुदाय पर हैं। ऐसे में चुनावी साल के चलते इस साल बजट में आदिवासियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि, ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार दिलाने की हमारी प्राथमिकता होगी। 48 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अधोसंरचना विकास पर खर्च करने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस बजट के माध्यम से हमारी कोशिश भारत सरकार के बजट में **प्रावधानों का अधिकतम** लाभ उठाने की भी रहेगी। प्रदेश में चार टूरिस्ट सर्किट विकसित होंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

चुनावी साल होने के कारण सरकार का सबसे अधिक फोकस प्राथमिकताओं पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए मप्र का बेहतर बजट बनाया जाए। प्रदेश की प्राथमिकताओं को देखते हुए राज्य का बजट तैयार किया जाए। बजट में विकास और जनकल्याण पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने विशेषज्ञों को प्रदेश के बजट के लिए सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों

अधोसंरचना विकास पर सरकार का फोकस

प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए मप्र सरकार के दिशा-निर्देश पर वित्त विभाग के अधिकारी अभी से बजट की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार का बजट चुनावी रंग में रंगा रहेगा। मुख्य बजट में सरकार का कर्मचारियों के बकाया डीए सहित अधोसंरचना विकास पर फोकस रहेगा। इसके लिए यदि कोई विभाग नई योजना लाना चाहता है, तो उसे औचित्य बताना होगा। विभाग अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे, बल्कि इसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजना होगा और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा ही लिया जाएगा। वित्त विभाग ने आगामी बजट बनाने के लिए विभिन्न विभागों से तैयारियां प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि संभावित है। जानकारी के अनुसार आगामी वर्ष बजट में इसके लिए 46 प्रतिशत सभी विभाग प्रावधान करेंगे। शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए का मुख्य बजट और प्रथम अनुपूरक 9,784 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।

में तेजी से प्रगति कर रहा है। कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार दिलाने की हमारी प्राथमिकता है। इस साल 48 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अधोसंरचना विकास पर खर्च की जाएगी। इसके लिए ग्रामीणों और युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपए अंतरित करने से कुपोषण दूर करने के प्रयासों में सफलता मिली है। महिला पंचायत में मिले सुझावों को लागू किया गया है। भारत सरकार के बजट में प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने की हमारी कोशिश रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी नीति एवं सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश के आगामी बजट को बनाने में केंद्रीय बजट 2023-24 पर अर्थशास्त्रियों द्वारा विशेष समीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मप्र दूरदर्शिता के साथ बजट में प्रावधान करेगा। मप्र में लगातार प्रगति हो रही है। भारत सरकार ने मत्स्य-पालन को बजट में प्राथमिकता दी है। मप्र के बजट में भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। शहरों के विकास, कृषि एवं ग्रामीण आदि बिंदुओं पर **प्रस्तुतिकरण दिया गया।** 27 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय योजनाओं का भरपूर उपयोग किया जाएगा। अधोसंरचना विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कृषि, शहरी और ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त प्रविधान किए जाएंगे।

गौरतलब है कि मप्र को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संकल्पित हैं। इसके लिए मप्र को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए इस बार मप्र का बजट ऐसा होगा, जिससे आत्मनिर्भर मप्र का सपना साकार होगा। प्रदेश के बजट को तैयार करने के लिए वित्त विभाग के अधिकारी अभी से जुट गए हैं और बजट को अंतिम रूप देने से पहले जनता की भी सलाह ली जाएगी। सरकार ने बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह उत्साहित दिख रहे हैं, उससे तो यह साफ हो गया है कि प्रदेश का बजट आत्मनिर्भर मप्र पर आधारित होगा। शिवराज सरकार का आगामी बजट निश्चित रूप से प्रदेश की दिशा तय करने वाला होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट शिवराज सरकार के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इस मायने में कि राज्य में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके मुकाबले आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। जनता को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य को संकट से उबारने में मदद मिली है। हालांकि वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत अभी भी है। प्रदेश का बजट इस बार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। स्वयं का राजस्व बढ़ाने पर सरकार द्वारा जोर दिया जाएगा। साथ ही विभागों को बजट से अतिरिक्त भी वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में 3 प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से प्रविधान रखे जाएंगे तो महंगाई भत्ते के लिए वेतन मद में कुल प्रस्तावित राशि का 32 प्रतिशत हिस्सा रखा जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

अब तक की तैयारियों से माना जा रहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट के जरिए सरकार बड़ा संकल्प जाहिर कर सकती है। सरकार के लिए यह बजट चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी है। माना जा रहा है कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मप्र का खाका खींचने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस बार का बजट अवसर सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि जोखिम लेकर अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं, वे सभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित हुए हैं। कोरोना संकट से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। लगभग सभी क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो रही है। यह शुभ संकेत हैं, क्योंकि सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, उसके लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक जरूरत होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को अतिरिक्त आय सृजित करने के लक्ष्य भी दिए हैं।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

नई योजना लाने का बताना होगा औचित्य

इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यदि विभाग कोई नई योजना लाना चाहते हैं तो उन्हें औचित्य बताना होगा। वे अपने स्तर से कोई निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। उन्हें प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजना होगा और उस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। वहीं, कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में आगामी वर्ष में होने वाली संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग 46 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को बजट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन पर चर्चा 5 जनवरी से प्रारंभ होगी। शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए और 9 हजार 784 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। 19 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस साल चुनाव हैं। इसे देखते हुए बजट 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। सरकार ने आय में वृद्धि के लिए राजस्व संग्रहण पर जोर देने के साथ अन्य विकल्प भी अपनाए हैं। अनुपयोगी सरकारी परिसंपत्तियों की नीलामी की जा रही है तो विभागों को अन्य माध्यमों से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। कर चोरी रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार करने के साथ करदाताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्य के अंशदान को प्राथमिकता के आधार पर अलग से प्रस्तावित किया जाए।

बंद हो सकते हैं अहाते

उमा भारती की नाराजगी दूर करने की कोशिश

चुनावी साल में आबकारी नीति में प्रस्तावित प्रावधान को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की इस मुद्दे पर नाराजगी दूर करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रस्तावित नीति में शराब दुकानों को धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं और हॉस्टल से 50 मीटर की हवाई (एरियल) दूरी पर खोलने की अनुमति दिए जाने का उल्लेख है, जबकि मौजूदा नीति में 50 मीटर की पैदल दूरी पर दुकान खोलने का प्रावधान है। वाणिज्यिक कर विभाग के अफसर कहते हैं कि यदि नया प्रस्ताव मान लिया जाता है तो करीब एक चौथाई यानी 800 दुकानें बंद हो जाएंगी। इन दुकानों को बंद किया जाएगा या फिर शिफ्ट किया जाएगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। प्रदेश में वर्तमान में 3608 शराब दुकानें हैं। बता दें कि उमा भारती पिछले एक साल से शराब दुकानों को बंद करने को लेकर सार्वजनिक तौर बयान देकर शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं।

मप्र में नई शराब नीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विरोध के बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। नीति का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके मुताबिक अहाते बंद हो सकते हैं। यदि चालू रखने का निर्णय होता भी है, तो शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही देशी शराब के दाम 1 से 2 रुपए तक बढ़ सकते हैं। पिछले साल 23 जनवरी को सरकार ने नई शराब नीति जारी कर दी थी, इस बार उमा भारती के विरोध और कुछ सुझावों के कारण नई शराब नीति अटकी पड़ी है। जिस पर जल्द ही फैसला होने की संभावना है।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब नीति को लेकर आबकारी और वाणिज्यिक कर विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। अफसरों ने बताया कि शराब दुकानें धार्मिक स्थलों व स्कूलों से 500 मीटर के दायरे से बाहर करने का फैसला होता है, तो 40 प्रतिशत यानी 1443 दुकानें प्रभावित होंगी, जबकि 250 मीटर के दायरे में 902 दुकानें आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द इन प्रस्तावों पर फैसला लेंगे। बता दें कि प्रदेश में 3608 शराब दुकानें और 2611 अहाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछले कुछ महीनों से शराब नीति को लेकर सरकार को घेर रही हैं। हाल ही में उन्होंने भोपाल के अयोध्या नगर इलाके के एक मंदिर में तीन दिन तक डेरा डाल रखा था। वे मंदिर के सामने स्थित शराब दुकान व प्रदेश की शराब नीति के विरोध में मंदिर में रहकर विरोध कर रही थीं। यहां से जाने से पहले उन्होंने राज्य सरकार को खुली धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश की शराब नीति हमारे अनुरूप नहीं आई तो शराब दुकानों पर जो होगा, वो नजीर बनेगा। उमा ने यह भी कहा था कि वह नियम विरूद्ध शराब दुकानों में गायें बांधेंगी।

चुनावी साल होने के कारण इस बार आबकारी नीति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है। आबकारी विभाग के ड्राफ्ट के मुताबिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव है। नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। पिछले साल देशी शराब सस्ती करने के लिए शराब बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने का कमाई का मार्जिन घटाया गया था। साथ ही आबकारी विभाग ने उप-दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। सरकार ने विदेशी शराब पर एक्साइज डयूटी 10 से 13 प्रतिशत तक कम कर दी थी। इससे शराब सस्ती हो गई थी। खपत बढ़ने से सरकार का खजाना भरा और मौजूदा वित्तीय वर्ष में उसे 1300 करोड़ अधिक आय हुई है।

खास बात यह है कि वाणिज्यिक कर विभाग फिलहाल शराब पर वैट नहीं बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। सरकार ने पिछले साल होम बार लाइसेंस देने का निर्णय लिया था। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय एक करोड़ रुपए है, तो वह व्यक्ति घर पर होम बार खोल सकता है। इसके अलावा, घर पर शराब रखने की लिमिट 4 गुना कर दी गई थी। इससे पहले घर में एक पेटी बीयर और 6 बॉटल शराब रखने की अनुमति थी। इस बार इस नियम में बदलाव करने का प्रस्ताव भी नहीं है।

मप्र में 1 अप्रैल 2022 से शराब दुकानों का नया कंपोजिट शॉप मॉडल लागू किया गया। तभी से बीयर की खपत हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2019-20 की तुलना में 2020-21 की तिमाही में बीयर की खपत 49 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि देशी शराब की खपत 24 प्रतिशत तो विदेशी की 30 प्रतिशत बढ़ी है। आबकारी विभाग ने 2020-21 और 2021-22 को कोविड-19 प्रभावित वर्ष मानकर इस साल की ग्रोथ की तुलना 2019-20 से की है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो देशी शराब के ग्रामीण ठेकों में बीयर पहली बार बेची जा रही है। ज्यादातर वृद्धि वहीं से आ रही है। अप्रैल 2022 में बीयर की खपत 61 प्रतिशत तक बढ़ी है। साल 2021-22 में कुल बीयर का उत्पादन 13.48 करोड़ बल्क लीटर था। 2019-20 की तुलना में यह 31 प्रतिशत बढ़ा था। पिछले वित्तीय वर्ष में नंवबर 2022 तक 12 करोड़ प्रूफ लीटर देशी शराब बिक गई। आबकारी विभाग का अनुमान है कि 31 मार्च 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 14 करोड़ प्रूफ लीटर हो जाएगा। ऐसे में अगले साल 16 करोड़ प्रूफ लीटर शराब की खपत होने की उम्मीद है। आबकारी सूत्रों का कहना है कि पिछले साल 12 करोड़ प्रूफ लीटर देशी शराब की बिक्री का अनुमान था। इसको ध्यान में रखते हुए सप्लाई के लिए 3-3 करोड़ प्रूफ लीटर सप्लाई का ठेका दिया गया था। यह ठेके 4 डिसलर्स ने लिए थे, लेकिन शराब सस्ती होने के कारण डिमांड बढ़ गई, लेकिन डिसलर इसे समय पर पूरा नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति अप्रैल-मई महीने में बन गई थी। इसे ध्यान में रखकर अब नया नियम प्रस्तावित किया गया है। बता दें कि प्रदेश में देशी शराब उत्पादन करने वाली 22 डिसलरीज हैं।

● **सुनील सिंह**

बढ़ेगा चीतों का कुनबा

12 नए चीतों को क्वारंटीन करने के लिए तैयार बाड़े

कूनो नेशनल पार्क में चीतों के आवास और भोजन पानी के प्रबंध किए गए हैं। वहीं, चीतों को क्वारंटीन करने के लिए 10 बाड़े भी तैयार कर लिए गए हैं। इन्हीं में आने वाले सभी 12 चीतों को शुरुआत में रखा जाएगा। खास बात यह है कि इनके लिए 8 नए बाड़े बनाए गए हैं, जबकि चार पुराने बाड़ों को सुधारकर दो नए बाड़े बनाए गए हैं। चीतों के लिए बने 5 वर्ग किमी क्षेत्र के बाड़े के चारों ओर करीब आठ फीट ऊंची चारदीवारी और ऊपरी हिस्से में फेंसिंग की गई है। तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क 750 वर्ग किमी में फैला है जो कि 6800 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले खुले वन क्षेत्र का हिस्सा है। यहां बता दें कि एशियाटिक लॉयन को यहां नया घर देने के लिए 1998 में बने प्रोजेक्ट पर पहले ही करोड़ों रुपयों का बजट खर्च कर तैयारियां हो चुकी थीं, जहां अब तक गुजरात के गिरिवन से बब्बर शेर तो नहीं लाए जा सके थे, लेकिन पिछले साल 17 सितंबर को इसी कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से विशेष बाड़े में छोड़कर चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। नामीबिया से लाए गए सभी 8 चीतों ने यहां सर्वाइव कर प्रोजेक्ट के पहले चरण को सफल बना दिया है। अब यहां साउथ अफ्रीका से इसी माह के आखिरी दिनों में आ रहे 12 नए (7 नर और 5 मादा) चीते की अगवानी के लिए पार्क प्रबंधन पूरी तरह तैयार है।

मप्र के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते पर पिछले महीने हस्ताक्षर किए गए और फरवरी के आखिरी सप्ताह में सात नर और पांच मादा चीतों के कूनो पहुंचने की उम्मीद है। मंत्रालय भारत से लुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के लिए सक्रिय है। दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण विभाग ने कहा कि एक दशक तक हर साल 12 चीतों को भेजने की योजना है। पिछले साल जुलाई से 12 दक्षिण अफ्रीकी चीते पृथक-वास में हैं और उनके इस महीने कूनो पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कुछ प्रक्रियाओं में समय लगने के कारण उनके स्थानांतरण में देरी हुई। उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों को जल्द ही चीतों के हस्तांतरण के लिए वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) के तहत एक निर्यात परमिट और एक प्रमाणपत्र प्राप्त होगा। भारत ने सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है।

वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका पालन राष्ट्र तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन करते हैं। भारत भेजे जाने वाले इन 12 चीतों में से तीन को क्वाजुलु-नताल प्रांत में फिंडा पृथकवास बोमा में और नौ को लिम्पोपो प्रांत में रूइबर्ग पृथकवास बोमा में रखा गया है। उन्हें लेकर विमान जोहानिसबर्ग हवाईअड्डे से उड़ान भरेगा। अत्यधिक शिकार और आवास क्षेत्र की कमी के कारण भारत में चीते पूरी तरह से लुप्त हो गए थे। आखिरी चीता वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में देखा गया था। उसकी 1947 में मौत हो गई थी और 1952 में इस प्रजाति को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।

चीता प्रोजेक्ट के तहत चार माह पहले नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के बाद अब फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में साउथ अफ्रीका से भी 12 चीते लाए जा रहे हैं। इसके लिए बीती 26 जनवरी को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच समझौता भी हो गया है। यही वजह है कि देश की धरती पर बने चीतों के इकलौते घर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 12 चीतों के लिए पार्क प्रबंधन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछले साल सितंबर माह में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों (5 मादा और 3 नर) का नया बसेरा बना श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर साउथ अफ्रीका से आने वाले 12 चीतों के स्वागत को तैयार हो गया है। यहां 12 नए मेहमान चीतों को बसाने की तैयारियां यूं तो बीते कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एमओयू की फाइल समझौता हस्ताक्षर के लिए वहां के राष्ट्रपति के पास लंबित थी। अब 26 जनवरी को एमओयू साइन होने के बाद कूनो में अफ्रीकन चीतों का दूसरा जत्था आने का रास्ता साफ होने के बाद तो कूनो प्रबंधन ने 12 चीतों को नए घर में रखने की सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बस अब इंतजार है, चीते लाए जाने की तारीख का। करीब 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी होने के बाद उन्हें मप्र के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था जहां अब वो पूरी तरह ढल चुके हैं। रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले 8 नामीबियाई चीते अपने नए घर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में आराम से चहमकदमी करते हैं जिसे देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। छोटे बाड़ों से बड़े बाड़े में छोड़े गए इन सभी 8 चीतों ने भारतीय मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। इन 8 चीतों में सबसे ज्यादा चर्चा नर चीतों में दो जुड़वा भाइयों एल्टन और फ्रेडी की होती है।

एल्टन और फ्रेडी बड़े बाड़े के एक ही कंपार्टमेंट में रहते हैं। नामीबिया से आने के बाद सबसे पहले इन्हीं दो भाइयों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया था। इसके बाद से दोनों अपने बाड़े में मस्त हैं। पहली बार दोनों की एक साथ तस्वीर भी सामने आई है जिसमें एल्टन और फ्रेडी एक साथ बैठे हुए हैं। वन विभाग के अधिकारी ने इनकी तस्वीर क्लिक की है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ प्रकाश कुमार वर्मा ने बताया कि जब दोनों जुड़वा भाई नामीबिया कूनो लाए गए थे, तब थका हुआ महसूस कर रहे थे। बाड़े में छोड़े जाने के बाद यहां के माहौल में ढल गए हैं। वह बाड़े में अच्छे से शिकार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एल्टन और फ्रेडी साथ में ही शिकार करते हैं और सबसे पहले कूनो में इन्हीं दोनों ने पहला शिकार भी किया था। वन्यप्राणी विशेषज्ञों के मुताबिक इन चीतों का नामकरण मशहूर म्यूजिशियन जोड़ी एल्टन जॉन और फ्रेडी मर्करी के नाम पर रखा गया है। बता दें कि पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को कूनो पार्क के बाड़ों में छोड़ा था।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

ग्रीनबेल्ट में काटे जा रहे प्लॉट

राजधानी की जीवन रेखा कहे जाने वाले बड़े तालाब में बढ़ते अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई की वजह से इसके अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है। आलम यह है कि वेटलैंड एरिया के 20 वर्ग किलोमीटर तक लोगों ने यहां अतिक्रमण कर लिया है, जो अब एफटीएल के 50 मीटर अंदर तक पहुंच चुका है। इसके बाद भी ग्रीन बेल्ट के दायरे में भू-माफिया प्लॉट काटकर लोगों को बेच रहे हैं। बता दें कि बड़े तालाब का जल भराव क्षेत्र 31 वर्ग किलोमीटर और कैचमेंट एरिया 361 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन संत हिरदाराम नगर के सीहोर नाका स्थित आकाश गार्डन के पीछे बड़े तालाब के एफटीएल और डूब क्षेत्र में कुछ भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है। यह खेल बड़े ही जोर-शोर से चल रहा है। सारे नियमों को ताक पर रख भू-माफिया द्वारा यह काम किया जा रहा है। इसमें नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों की पूरी मिलीभगत है जिसके चलते इन भू-माफियाओं के हौंसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इन पर किसी का कोई असर नहीं होता है। इस संबंध में कई शिकायतें भी की गई लेकिन अधिकारियों की **मिलीभगत होने के कारण** इन पर आज तक कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ऐसे भू-माफिया पर तुरंत एक्शन होना चाहिए।

गौरतलब है कि बड़े तालाब में लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है। इसके कैचमेंट एरिया में दो दर्जन से अधिक अवैध शादी हाल संचालित हो रहे हैं। लोगों ने अतिक्रमण कर यहां पक्के गोदाम और फार्म हाउस बना लिए हैं। इनमें शहर के रसूखदार लोगों के साथ सरकार के बड़े अधिकारियों ने भी कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण कर लिए हैं। इनके रसूख के कारण अब तक नगर निगम भी नोटिस भेजने के अलावा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया। जबकि तालाब का तकरीबन 26 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खाली हो चुका है। वेटलैंड के बड़े हिस्से में कब्जा कर पक्के मकान बना लिए गए हैं। आरोप है कि भू-माफिया द्वारा अधिकारियों की जेबें इतनी गर्म कर दी हैं कि उन पर किसी भी गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। वह तो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जिससे भू-माफिया के हौंसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब यह भोपाल के बड़े तालाब का गला घोंटने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें शासन-प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कुछ नेताओं की भी मिलीभगत है, क्योंकि अधिकारियों और नेताओं की शह के चलते ही उनके द्वारा यह अवैध कार्य किए जा रहे हैं। इन्हें न तो शासन का डर है और न ही प्रशासन का। बस अपनी जेब भरने से काम है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सीहोर नाके के पास आकाश गार्डन के पीछे की जमीन ग्रीन बेल्ट व डूब क्षेत्र में होते हुए भी यहां पर भू-माफिया द्वारा प्लाटिंग का कार्य धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। बरसात के समय में यह पूरा क्षेत्र जल मग्न हो जाता है। यह पूरा क्षेत्र तालाब के एफटीएल, यानी फुल टेंक लेवल के दायरे में आता है। यहां पर कोई भी पक्का निर्माण कार्य किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसके बाद भी भू-माफियाओं द्वारा यहां पर फार्म हाउस के नाम पर प्लाटिंग की जा रही है। भोपाल-इंदौर हाईवे पर आकाश गार्डन के पीछे भू-माफिया पुरुषोत्तम तोतलानी, आकाश गार्डन के संचालक बबलू संभवानी सहित अन्य के द्वारा फार्म हाउस के नाम पर प्लाटिंग का बड़ा खेल खेला जा रहा है। जहां पर इनके द्वारा फार्म हाउस के नाम पर प्लाटिंग की जा रही है, वह क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के साथ-साथ डूब क्षेत्र में आता है। इनके द्वारा करीब 19 एकड़ जमीन पर 700 से लेकर 1 हजार रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से प्लाट बेचे जा रहे हैं। मौके पर पत्नी के साथ प्लाट देखने पहुंचे आरके शर्मा ने कहा कि उन्हें यह पता नहीं था कि यह अवैध काम हो रहा है वरना वह नहीं आते। ऐसे ही कई लोग ठगे जा रहे हैं। अब बात करते हैं, मुद्दे की, बता दें कि भोपाल-इंदौर मार्ग पर आकाश गार्डन के पीछे करीब 19 एकड़ में फार्म हाउस के नाम पर प्लाटिंग का कार्य बड़े ही जोर-शोर से चल रहा है, इसका नक्शा भी पूर्व में वायरल हो चुका है। अभी इस जमीन पर मुरम का रोड़ डाला जा रहा है, जिससे ग्राहकों को डेवलपमेंट दिखाकर झांसे में लिया जा सके। कई लोगों को तो एग्रीमेंट के आधार पर प्लाट बेचे भी जा चुके हैं। राजधानी की लाइफलाइन बड़े तालाब की सीमा में लगातार हो रहे अतिक्रमण के चलते बड़े तालाब का स्तर दिन-प्रतिदिन कम होता नजर आ रहा है। यहां पर लगातार कारोबारियों व भू-माफिया की संख्या बढ़ती जा रही है। जिससे तालाब का अस्तित्व खतरे में आ रहा है। वहीं यदि बात की जाए जिम्मेदारों की तो वह मूकदर्शक बनकर बैठे हुए हैं। क्योंकि उनकी जेबें तो पहले ही माफिया द्वारा भर दी गई हैं।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

बड़े तालाब में अतिक्रमण से अटका मास्टर प्लान 2031

2002 में बड़ा तालाब को रामसर साइट घोषित किया गया था। गौरतलब है कि तालाब व नदी के किनारे की नम व दलदल वाली जमीन को वेटलैंड कहा जाता है। इसके तहत ऐसे नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, जहां विदेशी पक्षी और जैव विविधता ज्यादा होती है, उसे रामसर साइट घोषित किया जाता है। करीब 1000 साल पुराना मानव निर्मित बड़ा तालाब प्राकृतिक रूप से नम भूमि है। इतने सालों से इसका ईको सिस्टम बरकरार है। बड़े तालाब और इसके कैचमेंट एरिया में करीब 20 हजार से ज्यादा पक्षी आते हैं। इसमें करीब 100 से 120 सारस पक्षी भी आते हैं। जैव विविधता के तहत यहां करीब एक हजार प्रजाति के फ्लोरा और फौना कीट और छोटे पौधे पाए जाते हैं। लेकिन यहां बढ़ते अतिक्रमण की वजह से 2005 का मास्टर प्लान देरी से पास हुआ था, लेकिन यहां फिर यही स्थिति है। जानकारों का कहना है कि बड़े तालाब के अतिक्रमण की वजह से राजधानी का मास्टर प्लान 2031 खटाई में पड़ सकता है। पर्यावरणविद् सुभाष सी पांडे का कहना है कि कैचमेंट एरिया के दायरे में करीब 26 गांव शामिल थे। इसके बावूजद सबसे अधिक अतिक्रमण खानूगांव, बैरागढ़ व सूरज नगर में हुआ है। जिससे तालाब के प्राकृतिक तंत्र को बीते सालों में काफी नुकसान पहुंचा है।

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार का सबसे अधिक फोकस खेती-किसानी पर रहता है। सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि प्रदेश का किसान खुशहाल रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को कई तरह की सौगातें देते रहते हैं। चुनावी साल में भी सरकार किसानों पर पूरी तरह मेहरबान है।

अन्नदाता को मिलेगा ब्याज रहित ऋण

डिफाल्टरों के ब्याज का भुगतान करेगी सरकार

जानकारी के अनुसार सरकार उन किसानों के ब्याज का भुगतान स्वयं करेगी जिन्हें बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इससे ऐसे ऋणी किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वे जल्दी ऋण मुक्त होकर दोबारा बैंक से कर्ज ले सकेंगे। जैसा कि किसानों को खेती-किसानी के कई कामों के लिए बैंक से ऋण लेना पड़ता है। कई बार प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है। इसके कारण वे ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में बैंक उन किसानों को डिफाल्टर घोषित कर देता है जिससे वे आगे नया लोन नहीं ले पाते हैं। इन किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से बैंक द्वारा डिफाल्टर किए गए किसानों के ऋण पर ब्याज की रकम चुकाने की घोषणा की गई है। इससे लाखों किसानों को लाभ होगा। सूत्रों का कहना है कि चुनावी साल में किसानों को उम्मीद है कि भाजपा सरकार फसल ऋण माफी कर देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किसानों के हित में ब्याज माफी की घोषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई घोषणाएं की हैं। इसमें डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करने की बात भी कही गई है। किसानों की जो भी जायज समस्याएं हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की राजस्व और विद्युत देयक संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। बता दें कि प्रारंभ में किसान संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को सुझाव-पत्र दिया गया था। उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पूर्व की तरह किसान कर्जमाफी होगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ज्यादातर जिलों के किसानों ने कर्ज चुकाना बंद कर दिया है।

चुनावी साल में सरकार अन्नदाताओं को कई तरह की सौगातें देने जा रही है। ऋणी किसानों को प्रदेश सरकार ब्याज माफी की सौगात देने के साथ ही प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से फिर ब्याज रहित ऋण देने के लिए कृषक समाधान योजना लागू करने जा रही है। इसकी घोषणा बजट में होगी। गौरतलब है कि मप्र की कुल आबादी में से करीब 70 फीसदी लोग कृषि कार्य में लगे हैं। यानी किसान प्रदेश का बड़ा वोट बैंक हैं, जिन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि मप्र का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। 27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में चुनाव की झलक दिखेगी। सरकार का सबसे अधिक फोकस किसानों पर होगा। इसके तहत शिवराज सरकार कृषक समाधान योजना लागू करने जा रही है। इसमें समय पर ऋण न चुकाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों को ही शामिल किया जाएगा। इसके बाद इन्हें सहकारी समितियों से फिर ब्याज रहित कृष्णि ऋण, **खाद-बीज** मिलने लगेगा। योजना पर एक हजार करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में कमलनाथ सरकार ने किसान ऋण माफी योजना लागू की थी। इसमें सहकारी समितियों के ऋणी किसानों को 2 लाख रुपए तक ऋण माफ करने का प्रविधान था। योजना के पहले चरण में चालू खाते पर 50 हजार और 2 लाख रुपए तक के कालातीत ऋण को माफ किया गया। दूसरे चरण में चालू खाते पर 1 लाख रुपए की ऋण माफी का प्रविधान था। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई ही थी और मार्च 2020 में अल्पमत में आने के कारण कांग्रेस सरकार चली गई और योजना ठप हो गई। इसके कारण लाखों किसान डिफाल्टर हो गए क्योंकि ऋण माफी की आस में इन्होंने ऋण नहीं चुकाया था। अब स्थिति यह है कि इन किसानों को सहकारी समितियों से न तो खाद-बीज मिल रहा है और न ही साख सीमा के अनुसार ऋण राशि प्राप्त हो रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को ब्याज माफी देने की घोषणा की थी और बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रविधान भी किया था लेकिन योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अब नए सिरे से योजना तैयार की जा रही है। इसमें ऋण माफी योजना के 4 लाख 41 हजार 840 उन किसानों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें लाभ नहीं मिला। इसके अलावा अन्य डिफाल्टर किसानों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से डिफाल्टर किसानों की जानकारी मांगी गई है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रविधान करना प्रस्तावित किया गया है।

मप्र सरकार की ओर से ब्याज माफी योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण बैंक से डिफाल्टर हुए 14 लाख 57 हजार किसानों को सरकार ब्याज माफी का लाभ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग वन टाइम सेटलमेंट योजना तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक किसान के मूलधन चुकाने पर उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। योजना में 30 मार्च 2018 के पहले के कर्जदार किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसके लिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि वह प्रदेश के सभी जिलों में समाधान योजना शुरू करेगी। इसमें अगर किसान शामिल होते हैं और लिए गए ऋण का मूलधन जमा करते हैं तो अब तक का पूरा का पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। उसे केवल मूलधन ही जमा करना होगा।

● **लोकेंद्र शर्मा**

सड़क हादसों में मप्र नंबर-2

ओवर स्पीड और लापरवाही से बढ़े हादसे

देशभर में ओवर स्पीड और लापरवाही की वजह से 83 फीसदी लोगों की सड़क हादसों में जान गई है। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भी सड़क हादसे की मुख्य वजह बन गई है। इसलिए ट्रैफिक नियमों को अब शिक्षा के साथ पढ़ाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटती है। लेकिन इसके बावजूद भी ओवर स्पीड और लापरवाही की वजह से सबसे ज्यादा मौत हो रही हैं। वर्ष 2021 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5742 दो पहिया वाहन चालकों की मौत हुई है। इनमें 4199 ऐसे चालक थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट लगाना भी जरूरी माना गया है। यदि तीन साल यानी वर्ष 2020, 2021 और 2022 के सड़क दुर्घटनाओं पर नजर डाली जाए तो साल दर साल घायल और मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो कि गंभीर है। वर्ष 2020 में जहां सड़क दुर्घटनाएं 45266 थीं, वर्ष 2022 में बढ़कर 54432 पहुंच गईं।

मप्र सड़क हादसों का प्रदेश बन गया है। सरकार के प्रयासों के बाद भी देश में रोड एक्सीडेंट के मामले में मप्र दूसरे नंबर पर है। ओवरस्पीड और लापरवाही की वजह से सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। जबकि सड़क दुर्घटना में मृत्यु में चौथा स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और 2021 में हुई सड़क दुर्घटना के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो तमिलनाडु के बाद मप्र दूसरे स्थान पर है। मप्र में वर्ष 2020 में 45266 और 2021 में 48877 दुर्घटनाएं हुईं। देश में 3.54 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.33 लाख लोगों जान चली गई। इनमें 56.6 प्रतिशत मौतें ओवरस्पीड की वजह से हुईं। साथ ही 26.4 प्रतिशत मौतें ड्राइवर की लापरवाही और ओवरटेक करने की वजह से हुईं।

प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों मप्र राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति की जानकारी दी। बताया गया है कि मप्र में सबसे ज्यादा सड़क हादसे शाम 6 से लेकर रात 9 बजे तक होते हैं। जबकि सबसे कम मध्यरात्रि के बाद 3 से 6 बजे के बीच होते हैं। राज्य में हर 43 मिनट में सड़क दुर्घटना में एक मौत हो रही है। साल 2021 में ऐसे हादसे 11.37 प्रतिशत बढ़े तो मौतों की संख्या 11.36 प्रतिशत और घायल 12.69 प्रतिशत बढ़े हैं। शहरों की तुलना में गांव में हादसे ज्यादा हो रहे हैं। ये कुल हादसों का 71 प्रतिशत है। इसी तरह 2021 में प्रदेश के नेशनल हाईवे पर 155, स्टेट हाईवे पर 140 तो पीडब्ल्यूडी (एनएच) पर 60 हादसे हुए हैं। हाईवे पर दुर्घटनाएं और मौतें 25 से 28 प्रतिशत तक हैं। जबकि अन्य मार्गों पर 47 प्रतिशत हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले इस परिषद ने तय किया है कि 2023 में सारे ब्लैक स्पॉट खत्म किए जाएंगे। यहां पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी।

नेशनल हाईवे पर दुर्घटना व मौत में मप्र का चौथा तो स्टेट हाईवे पर दुर्घटना में दूसरा और मौतों में चौथा स्थान है। हर 100 दुर्घटनाओं में एक मौत के मामले में मप्र का स्थान देश में 29वां है। रोड सेफ्टी रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में सबसे ज्यादा 3855 सड़क हादसे जबलपुर, 3676 इंदौर, 2616 भोपाल, 1973 धार और 1830 ग्वालियर में हुए हैं। जबकि सबसे ज्यादा 627 मौतें धार, 434 इंदौर, 467 सागर, 467 जबलपुर, 396 खरगोन में हुईं। हादसे का शिकार सबसे ज्यादा युवा हैं। मृतकों में 27 प्रतिशत लोग 25-35 वर्ष के, 22 प्रतिशत लोग 35-45 वर्ष के और 22 प्रतिशत ही संख्या 18-25 वर्ष के निकले हैं। कुल 71 प्रतिशत लोग 18 से 45 वर्ष के हैं। तेज रफ्तार से वाहन चलाकर दुर्घटनाग्रस्त होने वालों की संख्या 2021 में 79.1 प्रतिशत निकली है। यह चौंकाने वाला तथ्य है। वर्ष 2022 में कुल दुर्घटना 54,432, मौतें 13,427 और घायलों की संख्या 55,168 है।

प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। वाहन नियंत्रित स्थिति में चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकें निर्धारित समय पर हों। सड़कों पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लेक स्पॉट चिन्हित कर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा तय कर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सड़कों का सुधार कार्य किया जाए। ब्लेक स्पॉट के कारण दुर्घटनाएं नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों से संबंधित विभाग तालमेल बनाकर कार्य करें। रोड इंजीनियरिंग के कार्य ठीक ढंग से किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। अभियान के तहत सख्ती से कार्य करें। लोगों की जिंदगी बचाना बेहद जरूरी है। छोटी-छोटी वीडियो, फिल्मों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। लोग हेलमेट लगाएं एवं वाहन चलाने के नियमों का पालन करें। तकनीक का इस्तेमाल कर चालान बनाने की कार्यवाही करें। चालान की वसूली शत-प्रतिशत हो। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन देखने या बात करने से भी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं को सख्ती से रोका जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की वाहन चलाते समय असावधानी रखने की गलत आदतें बदलने के लिए सजगता से कार्य करें। समाजसेवी, स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और जनता को जोड़कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि वाहनों की फिटनेस जांच का कार्य प्रभावशाली तरीके से किया जाए। हर जिले में ट्रामा केयर सेंटर्स खोले जाएं। मवेशी रोड पर आवागमन को बाधित करते हैं, उनको हटाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था अच्छी रहे। सड़कों से अतिक्रमण हटाने का भी अभियान चलाया जाए, जिससे ब्लेक स्पॉट न रहे। सड़क पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसे ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस की भर्तियां निरंतर जारी रहें।

● **अरविंद नारद**

हेरिटेज शराब 'मोंड'

लंबा समय लग गया शराब तैयार करने में

महुए की ये शराब क्षेत्र में आदिवासी समाज घरों में सीमित संसाधन में ही तैयार कर देता है। उसी शराब को बनाने में प्रशासन को महीनों का वक्त लग गया। महीनों की तैयारी, विशेष प्रशिक्षण और लाखों के खर्च के बाद भी दो बार इसे टेस्टिंग के लिए भेजा, तो हेरिटेज शराब का वो क्वालिटी टेस्ट नहीं आ पाया था। इसे तैयार करने के बाद लोकल स्तर पर टेस्टिंग प्रोसेस में कई लोगों ने महुए की स्मेल की शिकायत की थी, तो कई ने पारंपरिक स्वाद ना होने की। अब पर्यटन विकास निगम की होटल से मिले फीडबैक का भी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, मामले में अधिकारियों का कहना है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट तैयार होता है, तो उसमें समय लगता है। चूंकि, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार का पायलट प्रोजक्ट भी, इसलिए वक्त लिया जा रहा है। पर्यटन विकास निगम की होटल में शराब को टेस्ट करवाने के बाद कई बिंदुओं पर फीडबैक फॉर्म भरवाया जा रहा है। अब तक मिले फीडबैक में हेरिटेज शराब को अच्छा प्रतिसाद मिला है। वहीं, कुछ लोगों ने इसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर की है। रेंटिंग के लिहाज से भी शराब को किसी ने 3 स्टार से नीचे रेटिंग नहीं दी है। इसके स्वाद से लेकर महक तक को लेकर फॉर्म में पूछा जा रहा है। इंदौर रीजन के मांडू में मालवा रिसोर्ट में इसे रखवाया गया है, तो भोपाल रीजन के पलाश रेसीडेंसी, विंड एंड वेल्स, लेक व्यू रेसीडेंसी और कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसे रखा गया है।

मप्र की बहुप्रतिक्षित हेरिटेज शराब 'मोंड' का ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल में ही यह शराब लोगों को खूब पसंद आ रही है।

गौरतलब है कि प्रदेश को देश-दुनिया में पहचान दिलाने के मकसद से तैयार की गई महुए की हेरिटेज शराब को मप्र पर्यटन विकास निगम की होटल में फीडबैक के लिए पहुंचा दिया गया है। प्रदेश के दो रीजन की पांच होटलों में पहुंचाई गई इस शराब को लेकर फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। मप्र पर्यटन विकास निगम की होटलों में टेस्टिंग के लिए इसे रखवाया गया है। इस हेरिटेज शराब को 'मोंड' नाम दिया गया है।

प्रदेश सरकार ने महुए से बनने वाली इस हेरिटेज शराब के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अलीराजपुर और डिंडोरी जिले का चयन किया था। सबसे पहले आलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। जिला प्रशासन के निर्देशन में लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था। टेस्टिंग के बाद पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में इसे पर्यटन विकास निगम के होटल में पहुंचाया गया। प्रदेश के 6 रीजन में से फिलहाल इसे इंदौर रीजन के मांडू और भोपाल रीजन की चार जगह पर इसे रखवाया गया है, जहां आने वाले मेहमानों को उनकी मांग पर इसे टेस्ट करवाया जा रहा है और उनसे इसे लेकर फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। अभी हेरिटेज शराब मप्र पर्यटन निगम के होटलों के बार में ट्रायल के तौर पर परोसी जा रही है। बार में जो भी व्यक्ति शराब पीने जा रहे हैं, उन्हें हेरिटेज शराब का 60 मिलीलीटर का एक पैग मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ ही उनसे हेरिटेज शराब को लेकर एक फॉर्म भरवाकर फीडबैक लिया जा रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है कि हेरिटेज शराब का टेस्ट कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है, यह स्ट्रांग है या लाइट आदि। लोगों से मिले सुझाव के आधार पर हेरिटेज शराब की क्वालिटी में आवश्यक बदलाव किया जाएगा। इसके बाद हेरिटेज शराब का वृहद स्तर पर उत्पादन शुरू कर इसकी मार्केट में बिक्री शुरू की जाएगी। मप्र पर्यटन निगम के होटलों में 18 बार हैं।

सरकार ने पिछले साल आबकारी नीति में अलीराजपुर और डिंडोरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हेरिटेज शराब का उत्पादन करने का फैसला किया था। अलीराजपुर और डिंडोरी में आदिवासी स्व सहायता समूहों द्वारा हेरिटेज शराब बनाने की यूनिट लगाई गई हैं। अलीराजपुर में हनुमान **आजीविका स्वसहायता समूह** ने हेरिटेज शराब का उत्पादन शुरू कर दिया है। हेरिटेज शराब के ब्रांड को 'मोंड' नाम दिया गया है। हेरिटेज शराब 180 मिलीलीटर की पैकिंग में उपलब्ध होगी। डिंडोरी यूनिट से भी हेरिटेज शराब का उत्पादन जल्द शुरू किया जाएगा। हालांकि, आने वाले समय में ये 90 एमएल और 750 एमएल की पैकिंग में भी उपलब्ध होगी।

कट्ठीवाड़ा में हेरिटेज शराब निर्माण के लिए तैयार यूनिट का संचालन स्वसहायता समूह कर रहा है। समूह में काम करने वाली टीम के सदस्य को इसके लिए पुणे के वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी दिलवाई जा चुकी है। इसी इंस्टीट्यूट में शराब की गुणवत्ता की जांच भी हुई है।

दरअसल, मप्र देश का पहला राज्य है, जो महुए से शराब का निर्माण कर उसे वैध तरीके से बेचने जा रहा है। सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान हेरिटेज शराब की शुद्धता पर है, क्योंकि सरकार इसकी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि यदि हेरिटेज शराब की ठीक से ब्रांडिंग की जाए, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी अलग पहचान बन सकती है। यही वजह है कि सरकार हेरिटेज शराब की क्वालिटी को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद इसकी बिक्री शुरू करेगी। सरकार हेरिटेज शराब निर्माण करने वाले स्वसहायता समूहों को कई तरह की रियायतें देने जा रही है। उपसचिव वाणिज्यिक कर ओपी श्रीवास्तव का कहना है कि अलीराजपुर यूनिट में हेरिटेज शराब का उत्पादन शुरू हो गया है। हेरिटेज शराब बाजार में जल्द उपलब्ध होगी।

महुआ शराब प्लांट में सरकार ने करीब 65 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें करीब 30 लाख की मशीन ही है। कट्ठीवाड़ा के पुराने सरकारी वेयर हाउस में इस प्लांट को लगाया गया है, जहां आने वाले समय में जिला प्रशासन अन्य कुछ यूनिट लगाने की तैयारी में भी है। हेरिटेज शराब का निर्माण महुए के फूलों से किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया की एकमात्र शराब है, जो फूलों से बनाई जाती है। भारत में अकेले मप्र में इसका निर्माण किया जाता है। इस शराब में मिथाइल एल्कोहल नहीं होता, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अन्य सभी प्रकार की शराब में मिथाइल एल्कोहल होता है। मप्र में बनने वाली हेरिटेज शराब के निर्माण में किसी भी तरह के कैमिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला पानी उच्च गुणवत्ता का होगा। हेरिटेज शराब की उत्पादन इकाई में हाईजीन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हेरिटेज शराब बनाने वाले हर स्वसहायता समूह को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का सर्टिफिकेट लेना होगा।

● **जितेंद्र तिवारी**

सूत न कपास नेताओं में लट्ठम-लट्ठा

नवंबर में मप्र में चुनावी डंका बजेगा। लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। खासकर भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। चुनावी तैयारी के प्रथम चरण में दोनों पार्टियां जनता के दर पर दस्तक दे रही हैं। इसलिए मप्र में यात्रा पॉलिटिक्स का माहौल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह की मैदानी रिपोर्ट मिल रही है, उससे यह साफ दिख रहा है कि मतदाता दोनों पार्टियों से नाखुश हैं।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में चुनावी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की कोशिश है कि अधिक से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाए। इसके लिए कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि उसका संगठन पूरी तरह कमजोर है। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 5 फरवरी से विकास यात्रा निकाल रही है। विकास यात्रा के दौरान मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियों की स्थिति सूत न कपास, नेताओं में लट्ठम-लट्ठा वाली है। यानी दोनों पार्टियां बिना तैयारी के यात्रा पॉलिटिक्स पर हैं। अब देखना यह है कि इस यात्रा पॉलिटिक्स का फायदा किसे मिलता है। वैसे दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। लेकिन प्रदेश की जनता न तो सत्तापक्ष और न ही विपक्ष से खुश है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां इनका गणित बिगाड़ने के लिए सक्रिय हो गई हैं।

लक्ष्य केवल सरकार बनाना

मप्र अब पूरी तरह चुनावी मोड और मूड में नजर आने लगा है। भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तरह मैदानी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों पार्टियों का फोकस अधिक से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने पर है। इसके लिए प्रदेश में यात्रा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, वहीं भाजपा 5 फरवरी से विकास यात्रा निकाल रही है। दोनों पार्टियां प्रदेश की सभी 230 सीटों की स्कैनिंग में जुटी हुई है। ताकि उस हिसाब से चुनावी रणनीति बनाई जा सके। मप्र में नवंबर में विधानसभा का चुनाव संभावित है। भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं कांग्रेस 150 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। अपनी-अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में अब तक जातिगत पॉलिटिक्स करने वाली भाजपा और कांग्रेस ने यात्रा पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश में जहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के सहारे प्रदेशवासियों के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही है तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस की ही तर्ज पर विकास यात्रा निकाल रही है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि भाजपा और कांग्रेस में से किसकी यात्रा सफल होती है और किसे प्रदेश सत्ता की चाबी मिलती है। इन यात्राओं को दोनों ही प्रमुख दलों का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 2018 की तरह 2023 के विधानसभा चुनाव में भी सफलता हासिल करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेसी जिले, ब्लॉक, मंडल और फिर गांव-गांव के बाद हर घर तक पहुंचेगी। कांग्रेस की यह यात्रा एक महीने तक चलेगी, जिसका मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत पार्टी मतदान केंद्र स्तर पर पदयात्रा निकाल रही है। इसमें गांव-गांव पहुंचकर घर-घर संपर्क किया जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताने के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की असफलताएं बताई जा रही हैं। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जवाब प्रदेश में निकाली जाने वाली विकास यात्रा के माध्यम से दे रही है। इस यात्रा में हर जिले, गांव में भाजपा के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। यात्रा के दौरान आमजनों को प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हो रहे हैं। विकास यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधियों की आमसभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। आमसभा के माध्यम से भाजपा के जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं से आमजनों को अवगत कराएंगे।

भाजपा के गढ़ में नए चेहरों को उतार सकती है पार्टी

भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट चयन में एक नई रणनीति अपनाने वाली है। जिसके तहत कद्दावर विधायकों को उनकी परंपरागत सीट से हटाकर जीतने वाली अन्य सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी ने इस फंडे को अपनाया तो भोपाल में हुजूर और गोविंदपुरा विधानसभा सीट से नए चेहरों को मौका मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। खास बात यह है कि इन सीटों के मौजूदा विधायक चर्चित और कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। भाजपा ने आकांक्षी विधानसभा सीटों (हारी सीटों) से जीतने के लिए रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत इन सीटों पर पार्टी के बड़े नेताओं को उतारा जाएगा। सभी जिलों की आकांक्षी सीटों पर पार्टी काम कर रही है। भोपाल जिले की बात करें तो यहां 7 विधानसभा सीट हैं। इनमें से 4 सीट नरेला, गोविंदपुरा, हुजूर और बैरसिया भाजपा के कब्जे में हैं। जबकि 3 विधानसभा सीट उत्तर, मध्य और दक्षिण-पश्चिम कांग्रेस के कब्जे में है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कब्जे से सभी सीटों को छीनना है। उत्तर विधानसभा सीट को छोड़ दें तो मध्य और दक्षिण-पश्चिम से मौजूदा विधायकों को उतारने पर पार्टी में लगभग सहमति है। ऐसे में मध्य विधानसभा सीट से गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर को उतारा जा सकता है। जबकि दक्षिण-पश्चिम से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके पीछे पार्टी के नेताओं का तर्क है कि शर्मा भाजपा के कद्दावर नेता हैं और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। वे प्रदेश स्तर के नेता हैं। ऐसे में उन्हें दूसरी सीट जीतने में भी आसानी होगी।

विकास यात्रा ने पकड़ी रफ्तार

5 फरवरी से शुरू हुई भाजपा की विकास यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद विकास यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी विकास यात्राएं निकाल रहे हैं। विकास यात्रा के बी-प्लान पर भी भाजपा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। विकास यात्रा में जहां भाजपा कमजोर है या जहां भाजपा के विधायक नहीं हैं, उन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब खुद पहुंचेंगे और सरकार के विकास बताएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की सभी विधानसभा में विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा मैदानी आंकलन के आधार पर आगे जमावट करेगी। इसके तहत विकास यात्राओं का भी फीडबैक लेना शुरू कर दिया गया है। इससे विधानसभा सीटों पर विधायकों, हारे नेताओं और मौजूदा मंत्रियों तक के फीडबैक को देखा जाएगा। भविष्य में इन्हीं फीडबैक के आधार पर निर्णय होंगे। दरअसल, भाजपा सभी 230 सीटों पर विकास यात्राओं के जरिए फीडबैक भी लेगी, जिससे आने वाले दिनों में संगठनात्मक कार्यों को लेकर जिम्मेदारियां देने के निर्णय किए जाएंगे। इसका दूरगामी असर टिकटों तक भी दिखेगा। भाजपा ने 230 सीटों पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। इसके तहत बूथ स्तर तक की

अब चुनावी मोर्चा संभालेंगे दिग्विजय

प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां मोर्चे पर सक्रिय हो गई हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी तक केवल कमलनाथ मोर्चे पर थे लेकिन अब पीसीसी चीफ के निर्देश पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मप्र में सक्रिय होंगे। 17 फरवरी से दिग्विजय सिंह प्रदेश की विधानसभाओं के सघन दौरे करेंगे। पहले चरण में 17 फरवरी को भोपाल जिले के बैरसिया व गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रथम सत्र की बैठक में मंडलम व सेक्टर के कार्यकर्ताओं से वन टू वन बातचीत करेंगे। बैठक के दूसरे सत्र में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, एनएसयूआई एवं अन्य समस्त मोर्चा पदाधिकारी गणों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम 3:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में भोपाल शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक के प्रथम सत्र में मंडलम सेक्टर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वे शाम 5 बजे दूसरे सत्र में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त मोर्चा संगठनों, विभागों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे।

भी रिपोर्ट बनेगी। इसमें विधायक व अन्य स्थानीय नेताओं को लेकर क्या स्थिति बनी इस पर निगाहें हैं। 25 फरवरी के बाद भाजपा का बूथ सशक्तिकरण अभियान चलना है। इसलिए उसके पूर्व ही इनकी रिपोर्ट भी तैयार होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने प्रवास व दौरे भी इन यात्राओं के बाद शुरू करेंगे। हर सीट पर भाजपा ने प्रभारी तैनात किए हैं। खासतौर पर हारी हुई 103 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा गंभीरता है। भाजपा इन सभी सीटों की जरूरत व स्थानीय नेताओं के समन्वय के हिसाब से आगे टीम तैयार करेगी। गौरतलब है कि अब तक दो सर्वे टिकटों को लेकर हो चुके हैं। अब आगे तीसरा सर्वे भी होना है, लेकिन उसके पूर्व ही यात्राओं का फीडबैक भी रहेगा। पिछली बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस बार दावेदारी करने वाले नेताओं पर इस फीडबैक का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। खास बात ये कि जो बड़े चेहरे चुनाव हारे थे, उनमें से तो कुछ को स्थानीय प्रभाव के कारण टिकट मिल सकता है, लेकिन जो जद्दोजहद वाले चेहरे हैं उनके लिए फीडबैक मायने रखेगा। अभी संगठन के पास कई सीटों पर समन्वय में दिक्कत की शिकायतें हैं। इनसे जुड़े फैसलों पर भी फीडबैक असर डालेगा।

गौरतलब है कि मिशन 2023 में 200 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही भाजपा 2018 में हारी 114 विधानसभा सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी के रणनीतिकार एक-एक हारी सीट पर मंथन कर जीत की रणनीति बनाएंगे। इसी सिलसिले में गत दिनों भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने अचानक मालवा अंचल के 3 प्रमुख जिले रतलाम, मंदसौर और नीमच के सभी बड़े नेताओं की बैठक रतलाम में तलब कर ली। तीनों जिलों के कोर ग्रुप की इस बैठक में 5 मंत्री, 3 सांसद और विधायकों के अलावा जिलाध्यक्ष और जिले के प्रभारी शामिल हुए। रतलाम में साढ़े 3 घंटे चली इस मैराथन बैठक में चिंतन-मंथन का मुद्दा मिशन 2023 ही रहा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान बगावत के दृश्य और विधानसभा की हारी हुई सीटों को लेकर भाजपाई दिग्गजों की चिंता बढ़ गई है। इसी के तहत शिवप्रकाश ने तीनों जिलों के सभी नेताओं से पंचायत निकाय चुनाव के अनुभव और कमियों पर चर्चा की। ज्यादातर लोगों ने चुनाव में हुई बगावत और अनुशासन का मुद्दा उठाया। मंत्री-विधायकों ने यह भी कहा कि चुनाव लंबे चलने के कारण भी समन्वय में दिक्कत हुई, अधिकृत उम्मीदार के खिलाफ कई बागी मैदान में कूद गए। अनुशासन की अवहेलना भी हुई। सभी सदस्यों के सुझाव और संस्मरण सुनने के बाद शिवप्रकाश बोले कि विधानसभा चुनाव में इन कमियों को दूर करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

बिना संगठन कैसे जुड़ेंगे हाथ

भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट टू के तौर पर शुरू किए गए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के साथ 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर शुरू किया है। इसमें 10 लाख पोलिंग सेंटर से लेकर ढाई लाख ग्राम पंचायत और 6 लाख से ज्यादा गांव तक पहुंचने का टारगेट तय किया गया है। लेकिन, सवाल ये है कि मप्र में जिस रफ्तार से इस अभियान की शुरुआत हुई है क्या तीन महीने में टारगेट पूरा हो सकेगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लक्ष्य गांव और ब्लॉक स्तर तक पहुंचना है, लिहाजा मप्र में इस अभियान की शुरुआत भी ग्रामीण इलाके से की गई। भोपाल के नजदीक मुगलिया छाप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की। लेकिन शुरुआत के साथ ही अभियान की जैसी धार और रफ्तार दिखाई देनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। असल में करीब तीन महीने के इस अभियान में ब्लॉक और ग्राम स्तर तक पार्टी को पहुंचना है, जबकि संगठन स्तर पर इस अभियान की तैयारी का मामला ये है कि ब्लॉक स्तर तक का रूट ही फाइनल नहीं हो पाया जिसकी वजह से अब तक मप्र के 52 जिलों में से कई जिलों में अभियान शुरू नहीं हो पाया। इसी तरह मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बड़े नेताओं के दौरे और कार्यक्रम भी हैं, अभियान शुरू हो जाने के बाद भी जिन्हें अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

असल में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस में जो जमीनी माहौल बना है, कांग्रेस पार्टी अब अपने बैनर पर उसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। देशव्यापी इस अभियान में पार्टी का लक्ष्य 10 लाख मतदान केंद्र के साथ 6 लाख गांवों तक पहुंचना है। हर घर तक पहुंचने वाले इस अभियान में पार्टी ने मोदी सरकार की नाकामियों के साथ राज्य स्तर पर भाजपा सरकार की विफलताओं का ड्राफ्ट तैयार किया है। मप्र में कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने पेश किया जाएगा और शिवराज सरकार की नाकामियां गिनाई जाएंगी। पहली बार आइडियोलॉजी पर भी फोकस कर रही है कांग्रेस और इस अभियान के जरिए कांग्रेस की विचारधारा से जनता को जोड़ने का काम भी किया जाएगा।

हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जिले में जिम्मेदारी संभाले पार्टी के नेता अवनीश भार्गव

बताते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अब जनता से पार्टी के सीधे जुड़ाव का कार्यक्रम है। इसके पहले भारत छोड़ो यात्रा कांग्रेस के बैनर पर नहीं हुई थी। ये अभियान पूरी तरह से कांग्रेस का है। इसमें मप्र के 52 जिलों के हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य है। अभी शुरुआत है इसलिए तैयारियां की जा रही हैं। जल्द से जल्द ये अभियान रफ्तार पकड़ लेगा और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को आम भारतीय का समर्थन मिला इस कार्यक्रम में भी आम भारतीय बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगा। कांग्रेस का अभियान पूरी तरह राजनीतिक है। भार्गव बताते हैं इस अभियान के साथ हम घर-घर शिवराज सरकार का कच्चा चिट्ठा, उनकी नाकामियां भी लेकर जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता हितेष वाजपेयी कहते हैं कि कांग्रेस ने जनता से जुड़ाव के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है, लेकिन अभियान की शुरुआत में जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे तो लग रहा है कि इस अभियान से पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने ही हाथ जोड़ लिए हैं। वो ही अभियान में कोई रूचि नहीं दिखा रहे।

बैठक में बूथ मजबूती, वोट शेयर बढ़ाने से लेकर हर महीने कोर ग्रुप की बैठक बुलाकर आपस में संवाद और संपर्क बढ़ाने की नसीहत भी दी गई। नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए मुहिम चलाने को कहा गया है। यह भी कहा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा वहां मैदानी स्तर पर और मेहनत करें। सीटों के साथ बूथ का ग्रेड ए, बी, सी एवं डी तय करने को भी कहा गया है। अचानक बुलाई गई इस बैठक में सांसद गुमान सिंह डामोर, सुधीर गुप्ता, अनिल फिरोजिया, मंत्रीगण जगदीश देवड़ा, ओम प्रकाश सखलेचा, ओपीएस भदौरिया, हरदीप सिंह डंग और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी पहुंच गए थे। इनके अलावा तीनों जिलों के सभी भाजपा विधायक, जिलाध्यक्ष और जिलों के प्रभारियों ने अपने क्षेत्र में निकाय चुनाव का ब्योरा दिया।

एक-दूसरे की सीटों पर नजर

मिशन 2023 को लेकर इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिशन मोड में काम कर रही हैं। भाजपा की कोर कमेटी और प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के साथ ही आला नेताओं के बीच हुए मंथन के बाद यह साफ हो गया है कि अब पार्टी ने उन 114 सीटों पर विशेष फोकस करने का फैसला किया है, जिन पर पार्टी प्रत्याशियों को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा में भाजपा को 109 सीटों पर ही विजय मिली थी। कांग्रेस के खाते में 114 सीटें गई थीं, हालांकि उपचुनाव के बाद तस्वीर बदल गई और भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीत ली थीं। इसके बाद भी पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव को आधार बनाकर इन विधानसभा क्षेत्रों में हार के कारण, कमियों को तलाशने के लिए प्रभारी बनाए हैं।

मप्र में मिशन-2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने कांग्रेस के कब्जे वाली 96 विधानसभा सीटों को छीनने के लिए पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का इन सीटों पर विशेष फोकस रहेगा। सभी सीटों पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। उनकी निगरानी में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को घेरने की तैयारी की जाएगी। इसके अलावा उन सात सीटों पर भी भाजपा फोकस कर रही है, जिन पर सपा-बसपा और निर्दलीय विधायक चुनाव जीते थे। 230 सीटों वाली मप्र विधानसभा में भाजपा के पास 127 सीटें हैं। वहीं, कांग्रेस के कब्जे में 96 और अन्य के पास सात सीटें हैं। भाजपा इस तैयारी में है कि कांग्रेस के मौजूदा विधायकों के प्रति नाराजगी का वह फायदा उठा ले। इसी उद्देश्य से भाजपा ने कुल 103 सीटों पर चुनावी तैयारी प्रारंभ कर दी है। इनमें सभी सीटों पर कद्दावर नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। इनमें प्रदेश के मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा के प्रभारी सबसे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारण जानेंगे। पार्टी ने सभी प्रभारियों से कहा है कि संबंधित विधानसभा में भाजपा की कमजोरी का अध्ययन करें। कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर सभी मोर्चा-प्रकोष्ठ और संगठन के नेताओं के साथ समन्वय बनाना है। सामाजिक और जातिगत समीकरणों का अध्ययन कर उनके हिसाब से चुनावी जमावट करना। भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं की 2023 के चुनाव से पहले घेराबंदी करना चाहती है ताकि उन्हें बाहर प्रचार का मौका न मिल पाए।

मालवा और ग्वालियर-चंबल में होंगे बहुकोणीय मुकाबले

मप्र में जातिगत आधारित क्षेत्रीय दल अस्तित्व के लिए करीब आने में संकोच कर रहे हैं और यही भाजपा के लिए शुभ संकेत दे रहा है। यानी वोटों में बिखराव की दशा में भाजपा के सामने सीधे मुकाबले की चुनौती कमजोर पड़ेगी और जीत की राह आसान होगी। दरअसल, मप्र में भीम आर्मी और जयस (जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन) जैसे संगठन चुनावों में ताल ठोंकने की तैयारी में हैं। राजधानी के भेल दशहरा मैदान में रैली आयोजित कर इन संगठनों ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी तैयारियों को भी जमीन पर टटोल लिया है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए प्रदेश में 82 सीटें आरक्षित हैं। फिलहाल इन पर भाजपा और कांग्रेस का कब्जा है और इसमें सेंध लगाने की तैयारी में क्षेत्रीय संगठन दमखम आजमाने के लिए इन क्षेत्रों में पैठ बढ़ा रहे हैं। हालांकि, सियासी हालात कुछ और ही संकेत कर रहे हैं, जिसके मुताबिक इन क्षेत्रीय दलों की सक्रियता और अलग-अलग चुनाव लड़ने से भाजपा को विधानसभा चुनाव में बड़ा लाभ होने की संभावना है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जयस की कांग्रेस से नजदीकी के कारण मालवांचल में एसटी वर्ग के वोट का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में चला गया था। वहीं, ग्वालियर-चंबल में एससी वर्ग का वोट एट्रोसिटी आंदोलन की नाराजगी के चलते भाजपा से दूर हटकर कांग्रेस के पास चला गया था। सीधे मुकाबले में वोट के एकतरफा मुड़ जाने का सीधा नुकसान भाजपा को हुआ और उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी।

भाजपा की माइक्रो प्लानिंग

2023 के चुनाव के लिए इस बार प्लानिंग नहीं माइक्रो प्लानिंग हो रही है। 2018 में अपने ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ अन्य फेक्टर्स के चलते सत्ता में आने से चूकी भाजपा, इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। चुनाव में भले ही 9 माह बाकी हों लेकिन भाजपा की रणनीति अभी से बनना शुरू हो चुकी है। तरकश में रखे तीरों से तीन खास निशान भेदने हैं। ये तीर संभालेंगे त्रिदेव और पूरा करेंगे भाजपा का मिशन 114। मिशन 114 सुनकर आप जरूर सोच सकते हैं कि सत्ता में आने के लिए सिर्फ शतक लगाना काफी नहीं। एक मुतमईन सरकार बनाने के लिए सीटें तो इससे बहुत ज्यादा चाहिए। ताकि पांच साल इत्मीनान से काटे जा सकें। फिर भाजपा की सुई सिर्फ 114 पर ही क्यों अटक गई है, तो बता दें कि ये 100 का आंकड़ा भाजपा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर रणनीति कामयाब रही तो भाजपा का ये मिशन 114 अगले चुनाव में कांग्रेस की सिट्टी-पिट्टी गुम कर देगा। वैसे भाजपा के इस मिशन के आगाज से पहले कांग्रेस नींद से तो जाग चुकी है।

हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन का मूल मंत्र है सुशासन, अनुशासन और जनता का सम्मान। इसके लिए वे चरैवेति... चरैवेति... चरैवेति में विश्वास करते हैं। सदैव जनहित के नए लक्ष्य तय करते हैं और पूरी दृढ़ता के साथ फिर आगे बढ़ जाते हैं। वे शासन और प्रशासन के अपने साथियों को भी कहते हैं नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत् चलना, सतत् चलना, यही तो मंत्र है अपना। इसी मंत्र के आधार पर वे मप्र को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वे जहां प्रशासन पर नकेल कसे रहते हैं, वहीं मंत्रियों को सक्रिय रखते हैं। वहीं इन सभी से आगे निकलकर वे अपनी जिद्द, जुनून और परिश्रम से औरों के लिए मील का पत्थर बनते हैं। यानी काम और चुनाव छोटा हो या बड़ा शिवराज उसे चुनौती के रूप में लेते हैं। शिवराज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हमेशा मिशन मोड में रहते हैं। शिवराज जैसा जुनून और परिश्रम करने की क्षमता प्रदेश में किसी अन्य नेता की नहीं हैं। जनता के बीच रहना और कार्यकर्ताओं से संवाद करना उनका पैशन है। इसलिए उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री चौथी पारी के करीब 3 साल पूरे कर चुके हैं और इसी साल विधानसभा के चुनाव होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अवधि का बेहतर उपयोग कर जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश में तेजी से जुटे गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सक्रियता के मामले में अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के मुकाबले कहीं आगे नजर आते हैं, तो उनके साथ राज्य का भाजपा संगठन भी सातों दिन 24 घंटे काम करता दिखता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। इस कारण उनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है और हर वर्ग तक पहुंचने के साथ उसे खुश करने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कदम उठाते रहते हैं। प्रदेश के 46 नगरीय निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस जुनून और जज्बे के साथ चुनाव प्रचार किया उसका तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ की सत्ता में वापसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री एक बड़ी चुनौती की तरह हो रहे हैं। खास बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को प्रवास करना, सभाएं कर जनता के बीच जाना और कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद करना खूब रास आता है। जनता के बीच रहकर वे खुद को सहज पाते हैं। यही वजह है कि भाजपा के पास भी मप्र में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का विकल्प नहीं है।

यात्रा से लिखी जाएगी विधायकों की विकास गाथा

प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा बेशक सरकारी है और योजनाओं का प्रचार और लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन इसके जरिए विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट भी तैयार रही है। यह रिपोर्ट विधायकों को टिकट दिलाने और काटने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। विकास यात्रा में सरकारी मशीनरी के साथ-साथ विधायक एवं सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। यात्रा गांव-गांव घूम रही है और सरकारी तंत्र हर गांव की समस्या, शिकायतें, हितग्राही लाभ, भ्रष्टाचार आदि का लेखा-जोखा जुटा रहा है। इधर सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता भी जनता की नाराजगी, विधायक अथवा अन्य नेताओं के प्रति नाराजगी, भ्रष्टाचार, विरोध, स्वीकारता-अस्वीकारता आदि का रिकॉर्ड मेंटेन करने में लगे है। सरकारी तंत्र का रिकॉर्ड शासन के पास पहुंचेगा और दल का रिकॉर्ड संगठन के पास पहुंचेगा। यात्रा के बीच भाजपा के पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। वे भी विधायकों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सत्ता और संगठन की रिपोर्ट विधानसभा वार अगले दो महीने के भीतर तैयार हो जाएगी। इसका उपयोग भाजपा टिकट चयन में कर सकती है। साथ ही चुनाव प्रचार का रोडमैप भी इसी के आधार पर बनेगा। यहां बता दें कि विकास यात्रा का सबसे बड़ा सियासी फायदा यह होगा कि सरकार को जमीनी हकीकत का पता चलेगी।

सर्वे से तय होगा भविष्य

मप्र में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन विधायकों का टेंशन बढ़ गया है, जिन्होंने चार साल तक अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है। दरअसल, भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने विधायकों की परफॉर्मेंस का आंकलन करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। जिनका पार्टी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस खराब निकलेगा, उनका टिकट संकट में पड़ जाएगा। इसलिए दोनों पार्टियों में सर्वे की खबर से खलबली मची हुई है। चुनाव के पहले प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने टिकट को लेकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इन सर्वे ने विधायकों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। भाजपा सर्वे के अलावा बूथस्तर तक रायशुमारी भी कराएगी तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे टिकट के लिए विशुद्ध रूप से सर्वे को ही आधार बनाएगी।

गौतम अडानी का तिलिस्म

अमेरिकी फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक हफ्ते पहले आई और तब से भारत के शेयर बाजार में इस पर पर्याप्त कोहराम मच चुका है। 24 जनवरी की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की सातों लिस्टेड कंपनियों के शेयर धड़ाम हुए हैं और गौतम अडानी खुद दुनिया की रईसों की लिस्ट में तीसरे से सातवें नंबर पर आ गए। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया और रिपोर्ट को भारत की ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ साजिश बताया। इसके बाद हिंडनबर्ग ने भी पलटवार किया और कहा कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद की आड़ में छिपा नहीं सकते। हालांकि, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग और इसके मकसद को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि कहीं तगड़ा मुनाफा कमाने के लिए तो यह पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई।

दरअसल, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के साथ खुलासा किया था कि उसने अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजिशन ले रखी है। अमेरिकी इनवेस्टमेंट फर्म के डिस्क्लेमर के मुताबिक ही हिंडनबर्ग एक मंदड़िया है यानी शॉर्ट सेलिंग का धंधा करता है। वह बाजार की गिरावट का फायदा उठाता है। यानी वह बेच पहले देता है और जब स्टॉक के दाम गिर जाते हैं तो वह बाद में खरीद लेता है। उसका यही इतिहास इस रिपोर्ट पर लोगों को थोड़ा शक पैदा हो रहा है। कंपनी ने खुद बताया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसने शॉर्ट पोजिशन ले रखी है। जाहिर सी बात है कि अडानी ग्रुप के शेयर गिरेंगे तो हिंडनबर्ग को फायदा होगा। यानी साफ-साफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। शेयर बाजार के कुछ जानकारों का मानना है कि क्योंकि इस रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह की कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, जिसका हिंडनबर्ग को सीधे-सीधे फायदा होना है।

हिंडनबर्ग पर दूसरा सवाल रिपोर्ट जारी करने की टाइमिंग को लेकर है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब अडानी समूह अपनी मूल कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ बाजार में लेकर आया है, जो प्राइवेट सेक्टर में देश का सबसे बड़ा एफपीओ है। 27 से 31 जनवरी के दौरान इस एफपीओ के जरिए अडानी ग्रुप बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट के कारण एफपीओ ऑफरिंग को झटका लगा है। एफपीओ के पहले दिन 4.55 करोड़ शेयर के बदले केवल 4.7 लाख शेयरों के लिए ही बोली आई। कंपनी ने एफपीओ के लिए प्राइस बैंड 3,112 से 3,276 रुपए प्रति शेयर रखा हुआ है। लेकिन, गत दिनों इसका शेयर बीएसई में 2,762.15 रुपए के भाव पर बंद हुआ। खुदरा निवेशकों ने 4 लाख शेयरों के लिए ही आवेदन किए, जबकि उनके लिए 2.29 करोड़ शेयर रिजर्व हैं। संस्थागत खरीदारों और गैर-संस्थागत निवेशकों ने भी पहले दिन एफपीओ में कोई खास रूचि नहीं दिखाई। यही हाल रहा तो अगले दो दिनों में एफपीओ के पूरी तरह से सब्स्क्राइब होने की उम्मीद कम है। कंपनी को भी इस जोखिम का अंदाजा है। इसलिए उसने अपने बयान में कहा है कि रिसर्च रिपोर्ट फर्जी है और उसके एफपीओ को नाकाम करने के इरादे से लाई गई है।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इशारों-इशारों में सवाल दुनिया की कुछ दिग्गज ब्रोकर हाउसों ने भी उठाए हैं। जेफरीज ने अपनी अलग-अलग रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप में बैंकों का एक्सपोजर मैनेजेबल लिमिट में है यानी बैंकों ने इतना लोन नहीं दिया हुआ है कि जोखिम को मैनेज न किया जा सके। अडानी समूह पर करीब 2 लाख करोड़ का लोन है और सीएलएसए के विश्लेषकों का कहना है कि इसमें से 70,000-80,000 करोड़ रुपए ही बैंकों के हैं। उनका यह भी कहना है कि पिछले तीन सालों में ग्रुप का कर्ज एक लाख करोड़ से 100 प्रतिशत बढ़कर दो लाख करोड़ हो गया है, जबकि बैंकों का लोन 25 प्रतिशत ही बढ़ा है। इसके मुताबिक ग्रुप के कुल लोन में बैंकों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है, जिसमें 30 प्रतिशत सरकारी बैंकों के हैं और 10 प्रतिशत प्राइवेट बैंकों के। जेफरीज के अनुसार, भारतीय बैंकों ने जितनी राशि लोन के रूप में दी है उसमें अडाणी समूह का हिस्सा मात्र 0.5 प्रतिशत है। पीएसयू बैंकों के लिए ऋण कुल ऋण का 0.7 प्रतिशत है और निजी बैंकों के लिए यह 0.3 प्रतिशत है। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च का खुलासा सामने आने के बाद स्वाभाविक ही आर्थिक हलकों में एक तरह की अनिश्चितता और उथल-पुथल देखी जा रही है। इसमें अडानी समूह को हुए तात्कालिक नुकसान से जाहिर है कि उसके कारोबार को लेकर विश्वसनीयता में तेज गिरावट आई है। मगर इस सबके बीच अहम पक्ष यह है कि अडानी समूह के कारोबार पर भरोसा करके पैसा लगाने वाले आम निवेशकों की पूंजी कितनी सुरक्षित है या फिर उस पर कितना जोखिम है।

● **राजेश बोरकर**

लोन घटाने के लिए एफपीओ है लाया अडानी ग्रुप

एडवायजरी फर्म इन गवर्न का कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के हाई वैल्यूएशन यानी शेयरों की अधिक कीमत और ओवर लेवरेज यानी अधिक कर्ज की बात की गई है, लेकिन अडानी समूह की कंपनियां जिन सेक्टरों में काम करती हैं उस पर गौर किया जाए और कंपनियों में कर्ज के आंकड़े इतर कहानी बताते हैं। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा था कि अडानी ग्रुप के पास कैश फ्लो की समस्या है, ऐसे में लोन रीपेमेंट कैसे होगा। इसके जवाब में एडवायजरी फर्म का कहना है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां मोनोपोली वाले इंफ्रा सेक्टर में काम कर रही हैं। यानी ऐसे सेक्टरों में काम कर रही हैं, जहां ज्यादा कॉम्पटिशन का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बंदरगाहों वाले बिजनेस से उन्हें काफी बढ़िया कैश फ्लो हो रहा है, जबकि कुछ अन्य इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आने वाले वर्षों में कंपनियों के लिए कैश फ्लो बढ़ाने वाले होंगे। अधिक लोन के सवाल का जवाब इन गवर्न ने यह कहते हुए दिया है कि समूह कर्ज का भुगतान करने और लेवरेज कम करने के लिए हमेशा इक्विटी बेच सकता है। एफपीओ इस दिशा में ही उठाया गया कदम था। दरअसल, अडानी समूह एफपीओ के जरिए 20 हजार करोड़ जुटाकर बैंक का कुछ लोन चुकता करना चाह रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो पदयात्रा की, जिसमें उन्होंने भाजपा विरोधी सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। मगर उनके यात्रा में भी कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शामिल होने से इंकार कर विपक्ष की एकता को पलीता लगा दिया। विपक्षी दलों की आपसी फूट का फायदा उठाकर भाजपा 2024 में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की योजना बना रही है।

विपक्ष की अपनी ढफली, अपना राग है!

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल को उम्मीद थी कि यात्रा के दौरान कई दल उसके साथ जुड़ेंगे व राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बन 2024 में उन्हें ही भाजपा का विकल्प बन प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। पर यात्रा के समापन के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। वैसे शेरे कश्मीर स्टेडियम के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई। लेकिन कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इससे दूर रहीं। तभी कांग्रेस ने सफाई भी दी कि यात्रा का समापन कार्यक्रम विपक्षी एकता बनाने का अभियान नहीं है। कांग्रेस महासचिव और संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने यह बात कही। जाहिर है कांग्रेस ने राहुल की **समापन रैली** में बड़े विपक्षी नेताओं की गैरहाजिरी पर उठने वाले संभावित सवालों को पहले ही टालने का बहाना बता दिया है। सवाल है कि अगर यह विपक्षी एकता बनाने का अभियान नहीं है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों 23 विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी लिखी और उनको श्रीनगर के समापन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया? कांग्रेस इसे अपना ही कार्यक्रम रखती या ज्यादा से ज्यादा यूपीए के घटक दलों को न्योता देती। लेकिन कांग्रेस ने यूपीए से बाहर की भी लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा। आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अलावा करीब-करीब सभी विपक्षी पार्टियों को खड़गे ने चिट्ठी लिखी।

इनमें से कोई पार्टी समापन कार्यक्रम में नहीं शामिल हुई। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी जनता दल यू के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत जोड़ यात्रा और समापन रैली को लेकर कहा कि वह कांग्रेस का अपना अभियान है। जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा ने भी खड़गे को चिट्ठी लिखकर यात्रा की शुभकामनाएं दीं लेकिन शामिल होने से मना कर दिया। इनके अलावा खड़गे ने जिन लोगों को चिट्ठी लिखी थी उनमें से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आदि कोई भी पार्टी 30 जनवरी के समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई।

कांग्रेस को गठबंधन का सहारा

कांग्रेस ने असम में अपने गठबंधन सहयोगी सांसद बदरुद्दीन अजमल की आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से गठबंधन को समाप्त कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बदरुद्दीन अजमल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के इशारों पर कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। यह सब कुछ ऐसी ताजा घटनाएं हैं जो देश की राजनीति की दिशा व दशा तय करेगी। विपक्ष की राजनीति कर रहे कुछ दलों को कांग्रेस से आपत्ति है। वह कांग्रेस व भाजपा से समान दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। हालांकि केरल, त्रिपुरा में वामपंथी दल और कांग्रेस आमने-सामने चुनाव लड़ते हैं। मगर पश्चिम बंगाल व देश के अन्य प्रदेशों में एकसाथ गठबंधन कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में उप्र में कांग्रेस से गठबंधन करने से इंकार कर दिया था। इस कारण कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। तमिलनाडु में पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में द्रमुक ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जिसमें दोनों ही दलों को जबरदस्त सफलता मिली थी। द्रमुक को विधानसभा में अकेले ही बहुमत मिलने के कारण उसने राज्य सरकार में कांग्रेस को अभी तक शामिल नहीं किया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल व जनता दल यूनाइटेड की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। मगर कांग्रेस को सत्ता में नाम मात्र की हिस्सेदारी मिली है। जिससे बिहार के कांग्रेसी नेता संतुष्ट नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भाजपा को दूर कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी। जो सफलतापूर्वक चल भी रही थी। मगर शिवसेना के कुछ नेताओं द्वारा बगावत करने के कारण अघाड़ी सरकार गिर गई थी।

प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मिल रही चुनौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हुए करीबन पौने नौ साल का समय हो चुका है। वह बिना किसी चुनौती के एक छत्र राज कर रहे हैं। हालांकि कई प्रदेशों में क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत है तथा वहां उनकी सरकार चल रही है। मगर केंद्र से मिलने वाले लाभ की बदौलत कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं यथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सहित अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से अघोषित समझौता कर रखा है। जब भी केंद्र को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत होती है तो विपक्षी दलों के कई नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं। ये नेता किसी भी पार्टी से चुनावी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। पूर्वात्तर राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी के नेता भी आर्थिक हितों के चलते केंद्र सरकार को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इससे विपक्ष की राजनीति कमजोर होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो पदयात्रा की, जिसमें उन्होंने भाजपा विरोधी सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित भी किया था। मगर उनकी यात्रा में भी कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शामिल होने से इंकार कर विपक्ष की एकता को पलीता लगा दिया। विपक्षी दलों की आपसी फूट का फायदा उठाकर भाजपा 2024 में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की योजना बना रही है। यदि विपक्षी दलों की सिर फुट्टवल इसी तरह चलती रही तो भाजपा को लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है।

सबसे हैरानी की बात है कि त्रिपुरा में कांग्रेस से तालमेल करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां भी यात्रा में शामिल नहीं हुईं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से राहुल गांधी के बहुत अच्छे संबंध हैं लेकिन उन्होंने कांग्रेस की यात्रा में कहीं भी अपनी पार्टी को नहीं शामिल किया। इसी तरह का मामला बिहार की सबसे पुरानी सहयोगी राजद का भी है।

कांग्रेस की तमाम सहयोगी पार्टियों या यूपीए के घटक दलों के भी बड़े नेता यात्रा में शामिल नहीं हुए। तभी कांग्रेस की ओर से पोजिशनिंग की गई कि इसका मकसद विपक्षी एकता बनाना नहीं है। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि अधिकतर दलों ने उनके कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया तो उनका मकसद क्या है? देखा जाए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को जुटाने की कोशिश की है।

उनकी रैली में केजरीवाल, भगवंत मान और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंचे, जिससे ये साफ संकेत जाता है कि केसीआर एक ऐसा मोर्चा बनाने की कोशिश में हैं जो गैर कांग्रेसी हो। इसे कई नजरिए से देखा जा सकता है। केसीआर ने अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति की एक मेगा रैली की, जिसमें विपक्ष के ऐसे नेता पहुंचे जिन्हें कांग्रेस ने न्योता नहीं दिया था। वहीं ऐसे नेता भी केसीआर के साथ दिखे जिन्हें कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए न्योता दिया था। ये भारतीय राजनीति में काफी अहम वक्त है। इस वक्त सभी ये चाहेंगे कि कहीं न कहीं उनकी जगह बनी रही।

केसीआर की काफी पहले से ये कोशिश रही है कि भाजपा के खिलाफ वो अपना दम दिखाएं और लोगों को जुटाकर आगे की इच्छाओं को पूरा करें। केसीआर के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे नेताओं का पहुंचना काफी दिलचस्प है। वहीं ये भी काफी खास बात है कि सीपीआई के डी राजा भी वहां पहुंच जाते हैं। सवाल ये उठता है कि एक तरफ कांग्रेस ने उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के लिए न्योता दिया, वहीं दूसरी तरफ वो लोग केसीआर के साथ पहुंच जाते हैं।

इससे यही साफ होता है कि सभी दल अपने-अपने दांव बचाकर रखना चाहते हैं। एक बात और है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां, केसीआर की सरकार है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। भाजपा भी तेलंगाना में अपना आधार बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा की हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा ने जिन 9 राज्यों में जीत का लक्ष्य रखा है, उसमें तेलंगाना मुख्य रूप से है। क्योंकि, इससे भाजपा के लिए साउथ की राह आसान हो जाएगी। ऐसे में केसीआर नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर वे ऐसे किसी गठबंधन में शामिल हो, जिसमें कांग्रेस या भाजपा शामिल हो। इस पूरी पिक्चर में लेफ्ट फ्रंट की रणनीति को भी समझने की जरूरत है। एक तरफ तो लेफ्ट फ्रंट का कुछ हिस्सा त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ केसीआर की रैली में जा रहे हैं। ऐसे में लेफ्ट फ्रंट की मनोस्थिति समझने की जरूरत है। क्या लेफ्ट फ्रंट अलग चलने की कोशिश कर रहा है या फिर दोनों नाव में पैर रखने की कोशिश में है। लेफ्ट अपने अस्तित्व को बचाने की भी कोशिश में जुटा है।

कुल मिलाकर लेफ्ट अपनी सही जगह तलाशने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस से इतर थर्ड फ्रंट बनाने की सिफारिश करने वाले नेताओं में ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन, ममता बनर्जी का केसीआर की रैली में न शामिल होना **कई सवाल खड़े** कर रहा है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी केसीआर के नेतृत्व में खड़े हो रहे थर्ड फ्रंट में वामदलों की एंट्री से खफा हैं। क्योंकि, पश्चिम बंगाल में वामदल ममता बनर्जी की खिलाफत करता है। लिहाजा, ममता बनर्जी नहीं चाहती कि थर्ड फ्रंट में वामदल की एंट्री हो। क्योंकि, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति वामदलों के खिलाफ ही की और उन्हीं की राजनीति को पछाड़ते हुए अपनी राजनीति चमकाई। चर्चा यह भी है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंदर खाने तालमेल हो गया है। जिसके चलते वह विपक्ष से अलग हटकर अपना अलग ही राग अलापने लगी हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कुछ दिनों पूर्व अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर विपक्षी दलों को झटका दिया है। मायावती ने कहा है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से चुनावी गठबंधन नहीं करेंगी।

● **विपिन कंधारी**

इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कई राज्यों में सत्तारूढ़ या विपक्षी पार्टियों ने राजभवन का न्योता ठुकरा दिया। राजभवन में होने वाले गणतंत्र दिवस के पारंपरिक आयोजन में पार्टियां नहीं गईं। तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल और तेलंगाना तक ऐसी घटना हुई। यह भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

सरकारों-राज्यपालों के बीच टकराव...

राज्यपाल का पद बेहद सम्मान और गरिमा वाला माना जाता है। अंग्रेज के जमाने से लाट साहेब का कल्चर इस पद के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में राज्यपालों की गरिमा लगातार घटती जा रही है और राजभवन पहले जैसे पवित्र नहीं रह गए हैं। पहले जो घटनाएं अपवाद के तौर पर होती थीं अब आए दिन होती हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कई राज्यों में सत्तारूढ़ या विपक्षी पार्टियों ने राजभवन का न्योता ठुकरा दिया। राजभवन में होने वाले गणतंत्र दिवस के पारंपरिक आयोजन में पार्टियां नहीं गईं। तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल और तेलंगाना तक ऐसी घटनाएं हुईं।

यह भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। राज्यपालों का विपक्षी दलों की सरकारों के साथ टकराव का सवाल पिछले सालभर मीडिया और सियासत के गलियारों में गूंजता रहा है। देश की राजधानी से लेकर दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना से पश्चिम बंगाल होते हुए पंजाब और झारखंड तक जहां भी विपक्षी पार्टी यानी गैर-भाजपा सरकार है उन सभी जगहों पर निर्वाचित सरकार और राज्यपालों के बीच घमासान है। कई बार तो राज्यपाल चुनी हुई सरकार से अधिक शक्तिशाली नजर आते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच मतभेद या विवाद रहे हैं लेकिन वर्तमान समय में ये जिस हद तक आगे बढ़ चुका है वो बेहद चिंताजनक है।

सबसे हैरानी का मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां भाजपा ने राज्यपाल के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। सोचें, भाजपा की केंद्र सरकार ने ही सीवी आंनदा बोस को राज्यपाल नियुक्त किया है। लेकिन भाजपा उनका बहिष्कार कर रही है। भाजपा के एक नेता ने तो उनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जेरोक्स कॉपी बताया। भाजपा के नेता इसलिए नाराज हैं क्योंकि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के प्रति सद्भाव दिखाया है। उन्होंने बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा देने की शुरुआत करने का एक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के दिन राजभवन में रखा तो ममता बनर्जी भी उसमें शामिल हुईं। इसी वजह से भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन के साथ काफी समय से टकराव चल रहा है। उन्होंने भी 26 जनवरी को राज्यपाल के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। वे राजभवन में होने वाले आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उलटे उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तेलंगाना का राज्यपाल बनने से पहले तमिलनाडु में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष थीं और उसी अंदाज में राज्यपाल के तौर पर भी काम कर रही हैं। पहले भी सक्रिय राजनीति में रहने वाले लोग राज्यपाल बनाए जाते थे और इस तरह की बातें शायद ही कभी सुनने को मिलती थीं। उधर तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि से पूरे सत्तारूढ़ गठबंधन का टकराव चल रहा है। इसके बावजूद गठबंध का नेतृत्व कर रही डीएमके के नेता गणतंत्र दिवस पर राजभवन के कार्यक्रम में शामिल हुए लेकिन वीसीके और कुछ अन्य पार्टियों ने राज्यपाल के न्योते को ठुकरा दिया। दिल्ली की कहानी और कमाल की है।

दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल साल 2013 में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे लेकिन 2015

13 राज्यों में फेरबदल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद इन राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अब झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भगत सिंह कोश्यारी की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर की जगह पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ. बीडी मिश्रा को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल, गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस अब्दुल नजीर को आंध्रप्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। आंध्रप्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

से जनता लगातार उन्हें अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुन रही है। इस दौरान कई उपराज्यपाल बदल चुके हैं लेकिन सरकार के साथ उनका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बल्कि ये विवाद लगातार और बढ़ता ही जा रहा है। कई बार न्यायालयों ने भी हस्तक्षेप किया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि एलजी उनकी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति में रोड़ा अटका रहे हैं तो वहीं एलजी का कहना है कि सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है।

उन्होंने सरकार पर फिजूल खर्ची का भी आरोप लगाया है। इसको लेकर वे कई पत्र भी लिख चुके हैं। यही नहीं अभी वर्तमान में एलजी ने मुख्यमंत्री को एक रिकवरी नोटिस भी भेज दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के प्रचार में खर्च किए गए पैसों को एक पार्टी का प्रचार बताया और अब रिकवरी की मांग की है। अब सवाल उठता है क्या कोई एलजी चुने हुए मुख्यमंत्री से रिकवरी कर सकता है? मामला यहीं नहीं रुका है।

एलजी ने दिल्ली सरकार की कई योजनाओं के लिए जांच समितियों का गठन कर दिया है। अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम चुनाव हुए जिसमें केजरीवाल की पार्टी को बहुमत मिला था लेकिन एलजी और केजरीवाल सरकार के विवाद से ये भी अछूता नहीं रहा। यही वजह है कि आजतक दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिला है। एलजी ने चुनी हुई सरकार को बिना पूछे 10 कथित भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर निगम में पार्षद के तौर पर नॉमिनेट कर दिया जबकि आमतौर पर इसका अधिकार चुनी हुई राज्य सरकार के पास होता था। और उनके सुझाए नामों पर ही एलजी मुहर लगाते रहे हैं लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे ये लिस्ट भाजपा कार्यालय से आई हो।

इसी तरह जब पीठासीन अधिकारी चुनने का सवाल आया तो दिल्ली सरकार ने सबसे वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल का नाम दिया जिसे एलजी ने खारिज कर दिया और भाजपा पार्षद सत्या शर्मा को नियुक्त कर दिया। इसके बाद शपथ वाले दिन यानी 6 जनवरी का हंगामा हमने देखा ही है। उस दिन शपथ तक नहीं हो सकी। इसके अलावा टकराव का ताजा मामला दिल्ली सरकार के स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को विदेशों मे ट्रेनिंग को लेकर है। केजरीवाल सरकार कहती है कि वो अपने शिक्षकों को बेहतर गुणवत्ता के लिए विदेश भेजना चाहती है लेकिन एलजी ने इसमे भी अड़ंगा लगा दिया है। इसके खिलाफ पार्टी ने विधानसभा से लेकर एलजी के घर तक विरोध मार्च भी किया था।

केरल की विजयन सरकार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ टकराव जारी है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा था कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आरएसएस के एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। केरल में निर्वाचित सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाली वाम संयुक्त मोर्चे की सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ कई बार टकराव हो चुका है। कुछ समय पहले राज्य में तब संवैधानिक संकट खड़ा हो गया जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। जबकि मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने उन पर संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर न करने के लिए राज्यपाल के खिलाफ अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा, 11 अध्यादेशों की मियाद समाप्त हो गई, क्योंकि राज्यपाल ने अपनी मंजूरी नहीं दी। सरकार द्वारा पारित कई विधेयकों पर भी राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) और राज्यपाल के बीच लगातार विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में हद तब हो गई जब राज्य के राज्यपाल ने टिप्पणी की, कि राज्य को तमिलनाडु के बजाय तमिझगम के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए, जिसने न केवल सत्तारूढ़ डीएमके बल्कि उसके सहयोगियों के साथ जनता मे भी एक भारी रोष पैदा कर दिया है। इसके बाद राज्य में विरोध-प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल का पुतला भी जलाया गया। हालांकि उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वो इतिहास के संदर्भ में ऐसा बोल रहे थे। इससे पहले राज्यपाल ने अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान सीएन अन्नादुरई और एम करुणानिधि के साथ-साथ द्रविड़ विचारक, पेरियार और भारतीय संविधान के निमार्ता डॉ. बीआर अंबेडकर सहित डीएमके के कई दिग्गजों की प्रशंसा करने वाले कुछ अंशों को छोड़ दिया था। जबकि राज्यपाल हमेशा सरकार का तैयार अभिभाषण पढ़ते हैं।

इसके बाद सत्ताधारी दल के लोगों ने गवर्नर गो आउट जैसे नारे भी लगाए। इस घटना के एक दिन बाद, 13 जनवरी को डीएमके सांसदों के एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि राज्यपाल संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। जबसे राज्य में नई सरकार आई है और आरएन रवि ने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया तबसे राज्य सरकार के साथ उनके नियमित टकराव होते रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में महाराष्ट्र में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी की वजह से पिछली महाविकास आघाडी सरकार के दौरान एक साल तक महाराष्ट्र में विधानसभा के स्पीकर का चुनाव नहीं हो सका था। इसके अलावा उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने 12 लोगों को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश साल 2020 में नवंबर के पहले सप्ताह में की थी। लेकिन पूर्व राज्यपाल कोश्यारी हमेशा से इस पर आनाकानी करते रहे और मंजूरी नहीं दी।

● इन्द्र कुमार

आरक्षण पर घमासान

छत्तीसगढ़ विधानसभा आरक्षण विधेयक को लेकर अभी राज्य स्तर से मामला अटका है

क्योंकि पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर नहीं किया है। वहीं इस पर अब सामाजिक स्तर पर राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं पूर्व राज्यपाल का तर्क था कि जब 58 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है, तो 76 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर के लिए सरकार क्या कर सकती है? तकनीकी तौर पर पूरी तरह समझ लूं कि सरकार की क्या तैयारी है। आज मैं साइन कर दूं, और कल कोई व्यक्ति कोर्ट चला गया तो क्या होगा? वहीं कांग्रेस का तर्क है कि सरकार ने सभी संवैधानिक पहलुओं की पड़ताल करने के बाद ही आरक्षण संशोधन विधेयक बनाया है। जिसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

आप बिगाड़ेगी सबका खेल!

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब उनकी नजर छत्तीसगढ़ पर है। पिछले एक महीने से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्य के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं आम आदमी पार्टी के रोड शो में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि क्या ये भीड़ विधानसभा चुनाव में वोट में तब्दील हो जाएगी और ऐसा हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी गेम चेंजर हो सकती है?

दरअसल आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 455 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं। पार्टी यहां अपने संगठन का तेजी से विस्तार कर रही है। इसके अलावा पार्टी ने पूरे प्रदेश में लोकसभा प्रभारी और लोकसभा सचिवों का ऐलान कर दिया है। साथ ही सभी जिलों में जिला प्रभारी और जिला सचिवों की भी घोषणा कर दी गई है। इसके साथ-साथ आम आदमी पार्टी यहां मार्च में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। पार्टी अभी से इसकी तैयारियों में भी जुट गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल को भी छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया जाएगा। इसी दिन छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने विधानसभा चुनाव का आगाज करेगी।

आम आदमी पार्टी के लगातार संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2023 का विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने वाली है। हालांकि पार्टी ने अब तक ये घोषणा नहीं की है कि वो कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन प्रदेश प्रभारी संजीव झा पूरे छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकले हैं। संजीव झा बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के दौरे कर चुके हैं। इसके बाद अब उनका दुर्ग संभाग का दौरा शुरू हो गया है। आखिरी में वो रायपुर संभाग के दौरे पर जाएंगे। इसके बाद ही पार्टी ये तय करेगी कि वो 90 में से कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे?

आप आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने चुनावी अभियान को लेकर दुर्ग में मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की आप सरकार ने पूरी दिल्ली में सिर्फ 5 साल में बहुत से कार्य किए, फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रही है। बिजली के भाव बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। सरकार वहां मुफ्त पानी भी दे रही है। वहां लोगों की स्वास्थ्य जांच भी मुफ्त हो रही है। साथ ही सरकार लोगों को मुफ्त दवाई भी दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सब अब भी कोसो दूर हैं क्योंकि भाजपा और कांग्रेस यहां सिर्फ झूठे वादे कर रही है। दोनों पार्टियां लोकलुभावन घोषणाओं को विज्ञापन तक ही सीमित रखते हैं। वो इन्हीं लोकलुभावन घोषणाओं के विज्ञापन के जरिए वोट लेना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी की एंट्री पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राज्य में सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है। इसके बाद भाजपा, जेसीसीजे और बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। क्योंकि 90 में से 71 विधायक कांग्रेस के ही हैं। आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस के वोट कट सकते हैं। इससे दूसरी पार्टियों को फायदा मिल सकता है। ये गुजरात चुनाव में भी देखने को मिला था। गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। राजनीतिक पंडितों ने ये भी बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट एक फीसदी से भी कम रहा है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में झाड़ू चलने के आसार कम हैं।

प्रदेश प्रभारी झा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने चारागाह बना दिया है। गांव, गरीब, किसान और बेरोजगारों के हित में काम करने का झांसा देकर लूट करते हैं। यहां प्राकृतिक संसाधन और खनिज का भंडार है। इसके बाद भी यहां ना तो गांव का विकास हो रहा है और ना ही किसानों को उनका अधिकार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि, जिसकी भी सरकार बनती है सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देते हैं। उन्होंने तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ मे दिल्ली मॉडल लागू करने का लक्ष्य है। संजीव झा ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पार्टी के कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। चुनाव से पहले स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि, अभी प्रदेशभर में जाकर लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ली जा रही है। इसके बाद रायपुर में बड़ी जनसभा कर राज्य सरकार के पांच साल के कार्यकाल के भ्रष्टाचार और भाजपा के 15 सालों में हुए घोटालों को जनता के बीच रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता दोनों पार्टियों से परेशान है। जनता आप की ओर एक मजबूत और सशक्त सरकार लाने की चाहत में देख रही है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

आदिवासी बेल्ट में आप का फोकस

गौरतलब है कि बस्तर और सरगुजा संभाग कांग्रेस का गढ़ है। इन दोनों संभाग की 26 सीट पर कांग्रेस की एकतरफा जीत है। ये इलाका ट्राइबल बेल्ट में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण घटने पर वो नाराज हैं। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा संभाग में धर्मांतरण के मामले पर भी राजनीति तेज है। इस पर भी सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। खासकर आम आदमी पार्टी आदिवासियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। राज्य में बस्तर के आदिवासी नेता कोमल हुपेंडी को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पिछले साल पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी कोमल हुपेंडी को ही बनाया था।

शिंदे की ब्रांडिंग

चीन के स्टार के फीका पड़ने पर भारत ने दावोस में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। दावोस से लौटे भारतीय तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला, बेशक, आरके सिंह का भोजन, ऊर्जा और पानी की परस्पर क्रिया पर एक सत्र में शानदार प्रदर्शन है। जब न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट और सीएनबीसी पर सह-एंकर एंड्रयू रॉस सॉर्किन ने यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस से तेल आयात पर भारत को घेरने की मांग की, तो सिंह ने ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई में भारत के नेतृत्व के बारे में तथ्यों और आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्हें चुप करा दिया। सिंह ने कहा, मैं रूस से आयात बंद कर दूंगा लेकिन पहले यूरोपीय देशों को करने दीजिए।

दावोस में चर्चा का दूसरा बिंदु यह था कि कैसे योग गुरु श्रीश्री रविशंकर ने दक्षिण एशिया के पुनर्जागरण पर एक सत्र में पाकिस्तान की कनिष्ठ विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार को आड़े हाथ लिया। जब उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय लड़ाकू जेट 2019 में पाकिस्तानी क्षेत्र (बालाकोट हवाई हमले) में प्रवेश कर गए क्योंकि (लोकसभा) चुनाव जीतना था, तो शंकर भी ताबड़तोड़ जबाव देते हुए बोले- पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कहां पनप रहा है। ओसामा बिन लादेन कहां था? हिना रब्बानी मुस्कुरा रही थीं जब उन्होंने कहा कि वह सरकार से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक क्षेत्र से हैं। वह एक आध्यात्मिक गुरु के साथ एक मौखिक द्वंद्व में शामिल नहीं होने के लिए दृढ़ थीं क्योंकि वह अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र- शांति के लिए ध्यान पर चर्चा करना चाहती थीं। वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का और उनका बचाव करते रहे।

दावोस से भारतीयों की तीसरी याद के साथ लौटे हैं कि कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डब्ल्यूईएफ में हलचल पैदा की। दो अन्य मुख्यमंत्री (उप्र के योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के बसवराज बोम्मई) और महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। लेकिन इन भाजपा नेताओं ने दावोस के बजाय नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। एकनाथ शिंदे ने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया और 1.37 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। शिंदे दावोस में किसी सत्र का हिस्सा नहीं थे। फिर भी, वह दावोस शहर में एमओयू की वजह से चर्चा में बने रहे। जब उन्हें 1.37 लाख करोड़ रुपए का हवाला दिया, तो उन्होंने उससे कहा- यह एक सौ सैंतीस हजार करोड़ रुपए हैं। क्यों ये अधिक प्रभावशाली लग रहा है, है ना? महाराष्ट्र पवेलियन का उल्लेख द वाशिंगटन पोस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में भी मिला है क्योंकि यह वह जगह थी जहां रूसी मंडप हुआ करता था। अब घर वापसी की बात करें तो, विपक्ष के नेता आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा पर 30-40 करोड़ रुपए के खर्च का आरोप लगा रहे थे।

ऐसे समय में जब हर कोई शिंदे और ठाकरे की शिवसेना के बीच बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत पर लड़ाई पर सवार है, मुख्यमंत्री एक प्रशासक के रूप में अपनी ब्रांडिंग पर काम कर रहे हैं। वह फडणवीस मंत्रिमंडल में थे और फिर ठाकरे मंत्रिमंडल में लेकिन वे ठाकरे परिवार के संरक्षण में सिर्फ एक अन्य शिवसैनिक बने रहे। मुख्यमंत्री के रूप में, वह अब सामने आ रहे हैं। या ऐसा लगता है कि जिस तरह से वह अपने शासन के बारे में बात करते हैं, राजनीति पर सवालों को अलग रखते हैं। महाराष्ट्र के लिए उनके 'दृष्टिकोण' को इस तर्क के साथ खारिज करना आसान है कि वे जिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हवाला दे रहे हैं, उनमें से कई की कल्पना फडणवीस या उद्धव सरकार के दौरान की गई थी। तथ्य यह है कि शिंदे उनमें से अधिकांश की देखरेख कर रहे थे। पहले लोक निर्माण मंत्री के रूप में, जिन्होंने फडणवीस सरकार के दौरान महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम का नेतृत्व किया और फिर उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार में शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री के रूप में भी, वह पीडब्ल्यू (पब्लिक अंडरटेकिंग) पोर्टफोलियो अपने पास रख रहे हैं। यह महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण मंत्री (1995-99) के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान था कि नितिन गडकरी 'भारत के बुनियादी ढांचे के आदमी' के रूप में राष्ट्रीय सुर्खियों में आए, जो बहु-प्रशंसित मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पीछे थे। 2014 से लोक निर्माण मंत्री के रूप में, शिंदे मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे और अन्य बुनियादी परियोजनाओं के लिए भी श्रेय का दावा कर सकते हैं, भले ही उनमें से कई के पीछे फडणवीस का दिमाग था।

● **बिन्दु माथुर**

अपनी अलग पहचान बना रहें है

शिंदे का इंफ्रा फोकस हमें उनकी राजनीति के बारे में क्या बताता है? यह कि वह बिल्कुल भी फडणवीस की छत्रछाया में नहीं है, जिन्हें पीछे से महाराष्ट्र सरकार को चलाने वाला माना जा रहा है। और यह कि शिंदे उद्धव खेमे से 'विश्वासघात' के नारे और शिवसैनिकों की वफादारी और शिवसेना के प्रतीक को हासिल करने के संघर्ष से दबे नहीं हैं। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लिए अपने खुद के प्रशासनिक कौशल और दूरदर्शिता को दिखाने में व्यस्त हैं। भारत का चुनाव आयोग जल्द ही सेना के चुनाव चिन्ह-धनुष और बाण-पर निर्णय लेने वाला है। स्पष्ट रूप से शिंदे के लिए अपनी सेना को एक साथ रखना और उद्धव के खेमे से उन्हें दूर करना महत्वपूर्ण है। आने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव में यह उनके गुट, बालासाहेबंची शिवसेना के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिंदे एक योजना पर काम कर रहे हैं और सभी परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने पांच सहयोगियों-राहुल शेवाले, दीपक केसरकर, दादा भुसे, उदय सामंत और अब्दुल सत्तार को संगठनात्मक कार्य सौंपा है। वह अपने सांसद पुत्र श्रीकांत, एक युवा नेता, को आगे नहीं ला रहे हैं। जब आप वंशवाद के खिलाफ लड़ते हैं तो आप अपने वंश का प्रचार नहीं करते। जहां शिवसैनिक उद्धव या शिंदे के प्रति अपनी वफादारी को लेकर असमंजस में हैं, वहीं शिंदे उनके दिमाग को घुमाने के लिए अपने शासन मॉडल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आम लोगों की पहुंच से दूर माने जाने वाले उद्धव ठाकरे के विपरीत, शिंदे सैनिकों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं। वह अब 'शाखाओं' को सशक्त बनाने और उन्हें लोगों और सरकार के बीच मध्यस्थ बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं।

कांग्रेस में बढ़ रही रार

4 सालों में 9 उपचुनाव, कांग्रेस को मिली तवज्जो

राज्य में वर्ष 2018 के बाद कुल नौ उपचुनाव हुए हैं। इन उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। 9 में से 6 उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा महज दो सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। धौलपुर से शोभारानी कुशवाह (भाजपा), राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी (भाजपा) ने जीत हासिल की। खींवसर के उपचुनाव में आरएलपी के नारायण बेनीवाल ने चुनाव जीता। बाकी उपचुनाव की सभी सीटें कांग्रेस की झोली में गईं। धरियावद से नगराज मीणा (कांग्रेस), वल्लभ नगर से प्रीति शक्तावत (कांग्रेस), सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल (कांग्रेस), सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी (कांग्रेस), मंडावा से रीटा चौधरी (कांग्रेस) और अब सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा ने जीत हासिल की। उपचुनाव में सहानुभूति फैक्टर जीत का बड़ा आधार रहा है। खासकर जब उपचुनाव सिटिंग विधायक के आकस्मिक निधन के बाद हो रहा हो। पिछले उपचुनावों की बात करें तो वल्लभनगर से कांग्रेस के दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत, सहाड़ा सीट से कांग्रेस के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी, सुजानगढ़ से कांग्रेस के दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को मतदाताओं ने अपना विधायक चुना। इन सभी सीटों पर सहानुभूति वोट और सिम्पैथी फैक्टर हावी रहा। लेकिन जब भाजपा ने धरियावद से पार्टी विधायक गौतमलाल मीणा के निधन से हुए उपचुनाव में उनके बेटे कन्हैयालाल मीणा का टिकट काटकर खेत सिंह को चुनाव लड़ाया, तो कांग्रेस के पूर्व विधायक नगराज मीणा के हाथों उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।

आप भारत का नक्शा देख लीजिए, दक्षिण के एक छोर पर केरल है, और पश्चिम के एक छोर पर पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ राजस्थान है। केरल से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस टूट रही है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस बिखर रही है। राहुल गांधी केरल से यात्रा करते हुए आगे बढ़े थे। अब केरल के सबसे पुराने कांग्रेस नेताओं में से एक एके एंटनी, जो मुख्यमंत्री भी रहे, देश के रक्षामंत्री भी रहे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे, उनका बेटा अनिल एंटनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी की फिल्म का समर्थन करने पर कांग्रेस छोड़ गया। इससे पहले पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद कांग्रेस की पिछली सरकार का वित्तमंत्री मनप्रीत बादल कांग्रेस छोड़ गया। अब राजस्थान सरकार के कुछ मंत्री कांग्रेस छोड़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र खत्म होते ही अशोक गहलोत सरकार पर संकट आने वाला है। संभव है विधानसभा चुनाव से पहले ही गहलोत सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन में विधानसभा के चुनाव हों।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राहुल गांधी के राजस्थान की सीमा पार करते ही सचिन ने अपनी राजनीतिक दुकान अलग खोल ली है। सचिन पायलट न तो मंत्री हैं, न कांग्रेस में पदाधिकारी, लेकिन वह उसी तरह दौरे कर रहे हैं, जैसे 2018 में विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाते करते थे। हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी दो फाड़ हो गए हैं, कुछ गहलोत के साथ हैं, तो कुछ सचिन पायलट के साथ। सचिन पायलट प्रदेशभर में किसान सम्मेलन करके अपने समर्थकों को अपने पीछे लामबंद कर रहे हैं और अशोक गहलोत की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। हालांकि वह दावा यही कर रहे हैं कि 30 साल की परंपरा तोड़कर राज्य में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाएंगे। अपनी किसान रैलियों के माध्यम से वह असल में भाजपा की ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उनके अपने प्रभाव वाले क्षेत्र दौसा में सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में किसान सड़कों पर आ गए थे। किसानों के सड़कों पर आने से यह बात खुलकर सामने आ गई थी कि पिछले चुनाव में किया गया किसानों की कर्ज माफी का वायदा पूरा नहीं हुआ है।

किरोड़ीलाल मीणा तो उसके बाद से युवाओं को साथ लेकर पेपर लीक मामले में भी आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के बाद उन्होंने जवानों को भी साथ ले लिया है। गहलोत राज में नौकरियों की जितनी भी परीक्षाएं हुईं, उन सबके पेपर लीक हो गए थे, जिस कारण किसानों की तरह बेरोजगार जवानों में भी आक्रोश है। राजस्थान में लग रहा जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस की खटिया खड़ी कर रहा है। इसलिए संशय पैदा होता है कि सचिन पायलट किसानों को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद कर रहे हैं या उनमें गहलोत के प्रति आक्रोश को हवा देकर भाजपा के पक्ष में। पायलट खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं बोलते, वह उनका नाम ही नहीं लेते, लेकिन इशारों ही इशारों में सारे हमले उन्हीं पर होते हैं। सच यह है कि राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह दो फाड़ हो चुकी है। कहने को पायलट कुछ भी कहें, लेकिन वह भी अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस लौटकर नहीं आएगी। इसलिए अगले 5 साल के लिए राजनीति तय करने का अभी समय है।

अंदर ही अंदर खुसुर-पुसर तो यह भी चल रही है कि गहलोत सरकार के कुछ मंत्रियों के कांग्रेस और सरकार छोड़ते ही सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़कर अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना लेंगे। यदि राजस्थान में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में किसी भी सरकार का बनना निर्दलियों और छोटी पार्टियों के हाथ में आ जाएगा। सचिन पायलट सोचते हैं कि अगर वह अलग पार्टी बनाकर 25-30 विधायक जिता लाए, तो उन्हें नीतीश कुमार और कुमारस्वामी की तरह मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए वह किसानों को गहलोत के खिलाफ और अपने समर्थन में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार और संगठन में **बयानबाजी का दौर** जारी है तो वहीं अशोक गहलोत भी सरकार की ताकत दिखा रहे हैं। गहलोत-पायलट की खुली जंग के बीच अब सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट ने राजनीति को गर्म दिया है कि सरकार के पांच मंत्री जल्द ही पाला बदल सकते हैं और उनमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इन सबके भाजपा में जाने की चर्चा है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

बदल रही सपा

कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ मुखर हो रही पार्टी

आमतौर पर सपा कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ नहीं बोलती रही है या नरम रूख अख्तियार करती है, लेकिन अडानी के धोखाधड़ी प्रकरण पर अखिलेश यादव ने आक्रामक रूख अख्तियार किया है। उन्होंने 4 फरवरी को मुरादाबाद की अपनी प्रेसवार्ता में अडानी के साथ धोखाधड़ी में शामिल एलआईसी और स्टेट बैंक के अधिकारियों के जेल भेजने की बात की। उन्होंने कहा, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं। एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ना जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को दे दिया। आज कई लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। क्या अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? आम लोगों का पैसा चला गया और सरकार कहती है कि हम निवेश लाएंगे। जहां एक ओर सपा रामचरितमानस और जाति जनगणना के सवाल पर आक्रामक रूख अख्तियार कर पिछड़े-दलितों के सचेत हिस्से को अपने साथ लामबंद करने की कोशिश करती हुई दिख रही है, तो दूसरी ओर अडानी के सवाल पर मुखर होकर अडानी-मोदी गठजोड़ विरोधी मतदाताओं को भी अपने साथ करने का प्रयास करती लग रही है। मुस्लिम वोट भी खिसकने न पाए इसके लिए भी जोर लगा रही है।

समाजवादी पार्टी इन दिनों बदली-बदली सी नजर आ रही है। रामचरितमानस और जातिगत जनगणना पर पार्टी का स्टैंड हो, या फिर पार्टी के भीतर उन चेहरों पर भरोसा जो पिछड़ों की राजनीति के चेहरे रहे हैं। हाल ही में दिखा स्वामी प्रसाद मौर्य का बेखौफ अंदाज हो या फिर पार्टी का इस पर चुप रह जाना। कई बातें पार्टी में पहली बार हो रही हैं और वो इस बात का संकेत भी दे रही हैं कि पार्टी अपनी राजनीतिक दिशा बदलने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि खुद को उप्र में 2024 में भाजपा के एकमात्र राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है? मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 4 अक्टूबर 1992 को सपा के गठन के बाद भले ही उसका मुख्य राजनीतिक आधार पिछड़ी जातियां और मुस्लिम रहे हों, लेकिन सपा ने सचेत तौर पर कोई ऐसा क्लियर स्टैंड कभी नहीं लिया जिसमें सवर्णों के नाराज होने की कोई संभावना दिखी हो। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले सपा ने सवर्णों को रिझाने के लिए तरह-तरह के जतन किए। जिसमें परशुराम की मूर्तियां लगाने और विष्णु का भव्य मंदिर बनाने का वादा भी शामिल था, चुनाव से पहले सपा और बसपा के बीच सवर्णों और विशेषकर ब्राह्मणों को खुश करने और उनका वोट पाने के लिए होड़ मची हुई थी।

अखिलेश यादव की नजर हिंदू वोटों पर कुछ इस तरह थी कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार की असंवैधानिक आक्रामक कार्रवाई का भी कोई पुरजोर विरोध नहीं किया। उन्होंने आजम खां के खिलाफ योगी सरकार की बदले की कार्रवाई के खिलाफ भी कोई कारगर राजनीतिक कदम नहीं उठाया। मोदी सरकार की जन-विरोधी आर्थिक नीतियों और अडानी-अंबानी के गठजोड़ के खिलाफ भी खुलकर खड़े नहीं हुए। लेकिन हाल के कुछ समय में सपा अपनी राजनीतिक दिशा बदलती दिख रही है। पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को दलित-पिछड़ा विरोधी बताकर प्रतिबंध लगाने और उन्हें रामचरितमानस से निकालने की मांग की। लोगों को लगा कि इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करेंगे, उन्हें बयान वापस लेने को कहा जाएगा या उन्हें कहा जाएगा कि वे भविष्य में कोई ऐसा बयान न दें। कुछ लोगों को तो यहां तक लगा कि शायद उन्हें निकाल भी दिया जाएगा।

लेकिन इन सारी अटकलों के विपरीत अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और उन्हें जाति जनगणना के सवाल पर पूरे प्रदेश में अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चैनलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामचरितमानस की चौपाइयों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्हें दलितों-पिछड़ों को अपमानित करने वाला बता रहे हैं। 97 प्रतिशत बनाम 3 प्रतिशत की बात कर रहे हैं। इससे सवर्णों के बीच सपा के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है, फिर भी पार्टी इससे ज्यादा चिंतित नहीं दिख रही है। यहां तक पार्टी के भीतर के सवर्ण नेता भी मुखर होकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध कर रहे हैं और उसे सनातन धर्म और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला बता रहे हैं। इस सबके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस के प्रश्न पर आक्रामक रूख अख्तियार किए हुए हैं। सच ये भी है कि ये सब कुछ वो पार्टी अध्यक्ष की सहमति और इशारे के बिना नहीं कर सकते हैं। इस सबसे आगे बढ़कर अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को 'शूद्र' पहचान के साथ जोड़ते हुए इन चौपाइयों को शूद्रों के खिलाफ बताते हुए, तीखा आक्रोश प्रकट किया था। ये सपा के इतिहास में पहली बार है जब किसी शीर्ष नेता ने खुद को शूद्र पहचान के साथ जोड़ा है।

रामचरितमानस विवाद पर सपा का यह स्टैंड उसकी ऐतिहासिक वैचारिक स्थिति से विपरीत दिशा में है। सामाजिक समूह के तौर पर सपा का आधार भले ही पिछड़े रहे हों, लेकिन सपा ने कभी भी खुद को बहुजन वैचारिकी के साथ नहीं जोड़ा। उसने अपने नायकों के रूप में कभी ज्योति राव फुले, शाहू जी, पेरियार और आंबेडकर आदि को नहीं स्वीकारा। उसने हिंदी पट्टी के पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा जैसे चिंतकों-नेताओं को अपने नायक के रूप मे स्वीकार नहीं किया और न ही उनकी वैचारिकी को अपना आदर्श माना। सपा लोहिया के विचारों पर चलने का दावा करती रही है और उन्हीं के विचारों को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत मानती रही है। हिंदुओं के धर्मग्रंथों के खिलाफ पहली बार सपा के किसी बड़े नेता ने मुंह खोला और उस नेता को पार्टी का समर्थन मिलता भी दिख रहा है। यह सपा की पुरानी परिपाटी से अलग दिशा है। ध्यान रहे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते ही, लोटन राम निषाद को तो तुरंत ही सपा के पिछड़े वर्ग के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। इसके साथ ही सपा ने जाति जनगणना के सवाल पर भी आक्रामक रूख अख्तियार किया है। जाति जनगणना हिंदी पट्टी के दलितों-पिछड़ों की अहम मांग रही है। इसके पक्ष में ये समुदाय लगातार अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार आरएसएस और सवर्णों के दबाव में यह गणना नहीं करा रही है, क्योंकि इससे यह पता चल जाएगा कि कैसे मुट्ठीभर सवर्णों ने देश के अधिकांश संसाधनों और संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। अखिलेश गाहे-बगाहे **जाति जनगणना** के पक्ष में बोलते रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने गंभीरता से यह सवाल नहीं उठाया। इस बार पार्टी ने इस व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंपी है। जाति जनगणना का प्रश्न हिंदी पट्टी के बहुजनों के दिल-दिमाग को छूने वाला बड़ा प्रश्न है। जाति जनगणना की मांग को लेकर ओबीसी संगठन लगातार अभियान चला रहे हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

जाति के जंजाल में बिहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जाति गणना की कवायद शुरू कर दी है। 7 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान के 15 दिनों के पहले चरण में मकानों की गिनती होगी जबकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले दूसरे चरण में लोगों से उनके स्किल (कौशल) के साथ-साथ जाति भी पूछी जाएगी। इस बड़े अभियान में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और लगभग 2 लाख कर्मी इसमें भाग लेंगे। इसी वर्ष इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। नीतीश के अनुसार, जाति गणना से राज्य सरकार को नीति निर्धारण करने और प्रदेश में हर तबके का उत्थान करने की दिशा में काफी मदद मिलेगी।

गौरतलब है, बिहार में सभी जातियों की गणना आखिरी बार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1931 में हुई थी। वर्ष 2011 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल के दौरान सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण (एसईसीएस) तो हुआ लेकिन डेटा में आई खामियों का हवाला देकर बाद में जातियों की मौजूदा संख्या को सार्वजनिक नहीं किया। बिहार में यह मुद्दा उसके बाद हर चुनाव में उभरता रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2021 में नीतीश के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देशभर में जाति गणना करवाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला, लेकिन केंद्र से मांग खारिज किए जाने के बाद बिहार सरकार ने अपने स्तर पर राज्य में जाति गणना करवाने की घोषणा की।

सत्ता के गलियारों में नीतीश के निर्णय के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि अगले चुनाव के लिए बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का एजेंडा निश्चित हो गया है। उनका कहना है कि जनता दल-यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल अपने सभी सहयोगी दलों के साथ अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरने की कोशिश की रणनीति के तहत यह कर रहा है। जाहिर है, इस पर अभी से विवाद शुरू हो गए हैं। बिहार में हो रही जाति गणना के लिए जारी नीतीश सरकार की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिस पर इसी महीने सुनवाई होनी है। सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार का फैसला अवैध, मनमाना, तर्कहीन और असंवैधानिक है, जिसके जरिए प्रदेश में जातिगत दुर्भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

नीतीश इस तरह के विरोध पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जाति गणना पर विवाद पैदा करने का औचित्य उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री मीडिया से कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर ऐतराज क्यों है, यह मेरी समझ से परे है। गरीबों के उत्थान के लिए ही यह हो रहा है। सभी पार्टियों की सहमति से हो रहा है। यह सही है कि बिहार विधानमंडल से जाति गणना का प्रस्ताव दो बार सर्वसम्मति से पारित करवा के 2019 और 2020 में केंद्र सरकार को भेजा गया था। इस प्रस्ताव को भाजपा का भी समर्थन प्राप्त था और बाद में पार्टी इस संबंध में प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल थी। इसके बावजूद विरोधी दलों का मानना है कि भाजपा शुरू से ही जाति गणना के पक्ष में नहीं रही है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि भाजपा जाति गणना के पक्ष में 100 प्रतिशत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में दायर याचिका के खिलाफ बिहार सरकार को मजबूती से लड़ने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा चाहती है कि इस मुद्दे पर सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए जिसमें इससे जुड़े तमाम तथ्यों को स्पष्ट किया जाए। यह सही है कि भाजपा ने बिहार में जाति गणना के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है, लेकिन पूर्व में प्रदेश के नेता अपने स्तर पर इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। उनके अनुसार प्रदेश में सिर्फ दो जातियां अमीर और गरीब हैं और जाति गणना कराने का कोई औचित्य नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश के राजद अध्यक्ष लालू यादव से हाथ मिलाने के बाद लगातार बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में उसने अपना रुख बदला। जानकारों के अनुसार, नीतीश और लालू जाति गणना को गरीबों के हित के लिए निहायत जरूरी बताकर भाजपा को इसके विरोधी के रूप में चित्रित कर रहे हैं। वर्ष 2017 में नीतीश के महागठबंधन से बाहर होकर भाजपा से फिर संबंध जोड़ने के बाद राजद ने इस मांग को दोबारा दोहराया, जिसके बाद नीतीश सरकार ने विधानमंडल से दो बार इसका प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा ताकि सिर्फ राजद को इसका सियासी लाभ न मिल सके। अब नीतीश और लालू फिर एक साथ आ गए हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब यह मामला फिर तूल पकड़ने लगा है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि जाति गणना के माध्यम से समाज के वंचित तबकों की वास्तविक संख्या पता लगने से सरकार और नीति-निर्धारकों को उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में अवश्य मदद मिलती है, बशर्ते इसे सिर्फ सियासी वजहों से न किया जा रहा हो। बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस पूरी कवायद को प्रदेश की चुनावी राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। चाहे जो भी हो, नीतीश सरकार के इस फैसले का असर बिहार में होने वाले आगामी चुनावों पर नहीं होगा, ऐसा तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है।

● **विनोद बक्सरी**

चुनावी राजनीति की धुरी जाति

जाहिर है, ऐसे प्रदेश में जहां चुनावी राजनीति की धुरी जातिगत समीकरणों के इर्द-गिर्द दशकों से घूमती रही है, भाजपा अपनी छवि इस गणना के विरोधी के रूप में दिखाने का खतरा नहीं मोल ले सकती। 90 के दशक की शुरुआत में लालू ने केंद्र में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के बाद ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों को गोलबंद करके लंबे समय तक सत्ता में बने रहने में सफलता पाई थी। अब भाजपा फिर से लालू या उनके सहयोगी नीतीश को वैसा मौका देना नहीं चाहती। यही नहीं, पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण भाजपा ने बिहार सहित देश की पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ बढ़ाई है जिसे वह खोना नहीं चाहती। विपक्षी पार्टियां भाजपा पर लगातार हमलावर हैं और पार्टी पर जाति गणना रोकने के लिए कोर्ट केस सहित तमाम तरह के अड़ंगे लगाने का आरोप लगा रही हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पूछते हैं कि जाति गणना गलत कैसे है। वे कहते हैं, यह जाति आधारित सर्वे है जिसे कई राज्यों ने अपने स्तर पर कराया है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और यह कल्याणकारी योजनाओं को सटीक तरीके से लागू करने के लिए जरूरी है। इससे बहुत फायदा होगा। ऐसी ही दलील तेजस्वी के पिता लालू यादव वर्षों से दे रहे हैं।

पाकिस्तान के 40 टुकड़े होंगे

पाकिस्तान की हालत पिछले दो साल से बहुत खराब है। पाकिस्तान की हालत जैसी है उसके लिए खराब शब्द भी असल में मौजूदा सूरत-ए-हाल में एक साधारण शब्द है। वहां जिस तरह की स्थितियां हैं उसे भयावहता का सर्वोच्च शिखर कहा जाएगा। बलूचिस्तान समेत तमाम इलाकों में पाकिस्तानी सरकार और सेना का अब कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। जमीनी हकीकत यही है। पाकिस्तान पूरी तरह बिखर चुका है, दिवालिया हो चुका है, लेकिन घोषणा नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि आधिकारिक घोषणा करते ही पाकिस्तान के कई टुकड़े अस्तित्व में आ जाएंगे। पाकिस्तान जो छिपा रहा है, उसकी पोल खुल जाएगी। पिछले दो साल से पाकिस्तान इसे रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है।

रोजमर्रा के जीवन में लोगों पर दबाव इतना बढ़ चुका है कि कभी भी अराजकता चरम पर होगी। लोग विद्रोह पर उतारू हैं और पाकिस्तान चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों को भूखे सोना पड़ रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर लोग पेट भरने में असमर्थ हैं। वहां, गरीबों की हालत का अंदाजा क्या ही लगाया जाए। अच्छा खासा मध्यवर्ग भी रसोईघर के खर्च को पूरा नहीं कर पा रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के पोषण (2400 कैलोरी) के लिहाज से महीनेभर एक व्यक्ति को 14,098 रुपए खर्च करना पड़ सकता है।

सिर्फ एक व्यक्ति के खाने भर का खर्च साफ बता रहा कि उसकी वहां हालात कितने खराब हैं। जिस परिवार में 10 या उससे ज्यादा लोग होंगे, आज की तारीख में उसे पोषक भोजन पर कितना खर्च करना पड़ता होगा समझा जा सकता है। बावजूद इसके एक गरीब आदमी को सामान्य भोजन पर भी वहां महीनेभर में कम से कम 5-8 हजार रुपए खर्च करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जिसके पास काम नहीं है, वह भूखा सो रहा होगा। यह उस देश की हालत है जिसने मजहबी आधार पर 1947 में एक नया भूगोल और नई संस्कृति चुनी थी। बावजूद इसके वह संतुष्ट नहीं हुआ और एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने 75 सालों में भारत को बर्बाद करने की कोशिशें ना की हों। पाकिस्तान के **तमाम नैरेटिव** के असर को भारत में साफ-साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान कितना सही था, इसका अंदाजा 75 साल बाद आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के दो सबसे नजदीकी इलाकों में आटा-तेल की कीमतों से भी समझ सकते हैं।

पंजाब में भारत और पाकिस्तान की स्थलीय सीमा है। असल में कभी पंजाब की एक ही जमीन, भाषा और संस्कृति थी जो बंटवारे में अलग-अलग हो गई। बावजूद कि आसमान, धूप, हवा, माटी का रंग आज भी दोनों तरफ एक जैसा है। मगर जब आटा-तेल के भाव को कसौटी पर कसते हैं तो समझ में आता है कि असल में 74 सालों ने दोनों देशों को कितना अलग कर दिया है। लगातार घाव खाने के बावजूद भारत जहां खड़ा दिखता है, हम अपने देश का शुक्रगुजार हो सकते हैं। अमृतसर में अटारी रेलवे स्टेशन से करीब 3.1 किमी दूर पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन वाघा है। पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का विषय है।

पाकिस्तान के वाघा में एक लीटर दूध की कीमत 145 रुपए, आधा किलो व्हाइट ब्रेड की कीमत 100 रुपए, एक किली चावल की कीमत 200 रुपए, एक दर्जन अंडे की कीमत 234 रुपए, एक किलो आटा 150 रुपए, एक किलो चिकन की कीमत 550 रुपए, एक किलो रेड मीट की कीमत 857 रुपए, एक किलो टमाटर की कीमत 128 रुपए, एक किलो आलू की कीमत 66 रुपए, एक किलो प्याज की कीमत 77 रुपए और डेढ़ लीटर नॉर्मल बोतलबंद पानी 70 रुपए में है।

भारत के अटारी में इन्हीं चीजों की कीमत कुछ यूं है। एक लीटर दूध की कीमत 55 रुपए, आधा किलो व्हाइट ब्रेड की कीमत 39 रुपए, एक किलो चावल की कीमत 56 रुपए, एक दर्जन अंडे की कीमत 76 रुपए, एक किलो चिकन की कीमत 261 रुपए, एक किलो आटा 30 रुपए, एक किलो रेड मीट की कीमत 468 रुपए, एक किलो टमाटर की कीमत 35 रुपए, एक किलो आलू की कीमत 10-15 रुपए, एक किलो प्याज की कीमत 30 रुपए और डेढ़ लीटर नॉर्मल बोतलबंद पानी 30 रुपए में है। भारत में फूड आइटम की कीमतें स्टैण्डर्ड हैं। समझना मुश्किल नहीं कि एक साधारण गरीब के वश की बात नहीं। पाकिस्तान में खाने-पीने की चीजों का जो हाल है उसमें एक गरीब आदमी को इस वक्त भरपेट भोजन के लिए भारी संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। वह भूखा भी सोता होगा। उसका संघर्ष कितना बड़ा होगा अंदाजा, लगाना मुश्किल है। और भारत है कि पता नहीं क्यों अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ बराबरी वाला रीट्रीट सेरेमनी कर उसे चिढ़ाता रहता है। क्या यह ठीक बात है। पाकिस्तान को निश्चित ही ऐसे आयोजनों के लिए भी बजट का इंतजाम करना पड़ता होगा। भारत, पाकिस्तान की बराबरी कैसे कर सकता है। समूचे पाकिस्तान की जीडीपी तो असम से भी बहुत नीचे है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

सैलरी नहीं मिल रही लोगों को, फैक्ट्रियां बंद

तमाम सरकारी कर्मचारियों को पाकिस्तान में महीनों से सैलरी नहीं मिली है। कच्चा माल नहीं मिलने की वजह से कंपनियां बंद हो चुकी हैं। व्यापारियों के पास पैसे नहीं हैं कि बंदरगाह से अपने समन को छुड़ा सकें। पाकिस्तानी व्यापारियों को एडवांस तक देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग बेकाम घरों में बैठे हैं और शाम के खाने के लिए आटा लूटने को भी किसी हद तक जाने को तैयार हैं। पीओके की स्थिति तो यह है कि वे अपने वतन भारत लौटना चाहते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। असल में पाकिस्तान कुछ लोगों की संपत्ति बन चुका है। सेना हो या कारोबार या फिर राजनीति। गिने-चुने मुस्लिम अशराफ समूचे पाकिस्तान को चलाते नजर आ रहे हैं। वहां जब भी सवाल होते हैं, दूसरे मुद्दे खड़े कर दिए जाते थे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते पूरी तरह खत्म क्या किए, चीजें सतह पर आ गई। और अब पाकिस्तान के तमाम टेस्टेड हथकंडे भी काम करते नहीं दिख रहे हैं। दो साल से पाकिस्तान में चीजें सतह पर दिख रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ट्रिक्स से उसे संभालते रहा है। लोग चुप रहे इसके लिए कभी फ्रांस से जुड़े एक कार्टून को पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है।

मलबों में जिंदगी की तलाश...

तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को शक्तिशाली भूकंप आया था। इसमें अब तक 41 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भूकंप के 9 दिन बाद भी 15 फरवरी को इमारतों के मलबों में जिंदगियों को तलाशने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू टीमें कई लोगों को मलबों से जिंदा निकालने में सफल हुईं। तुर्की में जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनमें दो भाई शामिल हैं। इनकी उम्र 17 और 21 साल है। इन्हें कहरामनमारस प्रांत में अपार्टमेंट के मलबे से बाहर निकाला गया। उधर, अंटाक्या में एक सीरियाई पुरुष और महिला का भूकंप के करीब 200 घंटों बाद रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा चार और लोगों का भी रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीमों का दावा है कि अभी और भी लोगों को जिंदा निकाला जा सकता है।

तुर्की में भूकंप से 12 हजार इमारतें तबाह हुई हैं। ऐसे में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ये लोग सड़कों पर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। दूसरी ओर भीषण ठंड का कहर भी तुर्की में जारी है। ऐसे में इन लोगों को भूख के साथ-साथ ठंड का कहर भी झेलना पड़ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने भी शुरुआत में माना था कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अब उन्होंने कहा है कि राज्य में स्थिति काबू में है।

उधर, यूएन का कहना है कि जल्द ही रेस्क्यू अभियान खत्म होने वाले हैं। ऐसे में अब फोकस लोगों को आश्रय, खाना और बच्चों को शिक्षा पर होगा। हसन साइमौआ ने अपने परिवार के साथ गाजियांटेप में एक मैदान में शरण ले रखी है। वे कहते हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हमने टेंट के लिए और राहत साम्रगी के लिए आवेदन दिया है। हालांकि, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। हसन और तमाम सीरियाई लोगों ने युद्ध के बाद तुर्की की शरण ली थी। लेकिन ये लोग अब फिर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में ये लोग अस्थायी टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, लोगों की समस्याएं बड़ी हैं, ये घंटे दर घंटे बढ़ रही हैं। दोनों देशों में करीब 2.6 करोड़ लोगों को मदद की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि भूकंप के बाद अब ठंड, साफ-सफाई और संक्रामक रोगों के प्रसार जैसे स्वास्थ्य मुद्दों पर भी चिंताएं बढ़ रही हैं।

भारतीय सेना ने भी तुर्की में फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। भारतीय सेना की मेजर बीना तिवारी बताती हैं कि शुरुआत में घायल लोग आ रहे थे। लेकिन अब इसमें बदलाव हो रहा है। अब जो लोग अस्पतालों में आ रहे हैं, वे पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले हैं। ये लोग भूकंप के बाद से सदमे में हैं। सीरिया और तुर्की में लोगों का कहना है कि उनके बच्चे के मन में भी भूकंप का डर बैठ गया है। सीरिया के रहने वाले हसन मोएज कहते हैं कि जब उनका 9 साल का बच्चा रात में सोता है, तो वह अचानक से चौंककर उठ जाता है और चिल्लाने लगता है कि डेड भूकंप आया।

तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद इमारतों के मलबे से शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। इस भूकंप ने तुर्की के कई शहरों को तबाह कर दिया है। इस आपदा में जिंदा बचे हुए कई लोग बेघर हो गए हैं। दोनों देशों में मलबे से 40 हजार से ज्यादा के शवों को निकाला जा चुका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया है कि सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होने जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने बताया कि भूकंप से मरने वालों की संख्या 35,418 हो गई है। एर्दोगन ने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही प्रभावित इलाकों को छोड़ चुके हैं और सैकड़ों इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। एर्दोगन ने अंकारा में एक टीवी भाषण में कहा, हम न केवल अपने देश में बल्कि मानवता के इतिहास में भी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहे हैं। तुर्की में राहत और बचाव कार्य में जुटी भारतीय सेना की मेजर बीना तिवारी ने कहा कि शुरुआत में मरीज शारीरिक चोटों के साथ आए थे, लेकिन ये बदल रहा है। उन्होंने कहा कि भूकंप के दौरान हुए सभी झटकों के बाद अब पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीज आ रहे हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र सहायता का पहला काफिला बाब अल-सलाम क्रॉसिंग के माध्यम से तुर्की से विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर-पश्चिम सीरिया में प्रवेश किया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने संयुक्त राष्ट्र की सहायता को तुर्की से दो और सीमा पार से प्रवेश करने की अनुमति दी। सीरिया में 5814 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सीरिया में लगभग 9 मिलियन लोग भूकंप से प्रभावित हुए थे क्योंकि इसने 400 मिलियन डॉलर की फंडिंग अपील की थी।

● **कुमार विनोद**

भारत की ओर से भेजी गई राहत सामग्री

तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर इलाज तक कर रही हैं। सेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए तुर्की और सीरिया में मोबाइल, अस्पताल, दवाइयां और कई राहत सामग्रियों से भरी 5 फ्लाइटें भेजी जा चुकी हैं। इसके अलावा एक सी-130 जे विमान पर भी राहत सामग्री भेजी गई है। तुर्की में भूकंप का पहला झटका 6 फरवरी की सुबह 4.17 बजे आया था, जिसकी रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियांटेप था। इससे पहले कि लोग इससे संभल पाते कुछ देर बाद ही भूकंप का एक और झटका आया, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप के झटकों का यह दौर यहीं नहीं रुका। इसके बाद 6.5 तीव्रता का एक और झटका लगा। भूकंप के इन झटकों ने मालाटया, सनलीउर्फा, ओस्मानिए और दियारबाकिर सहित 11 प्रांतों में तबाही मचा दी। शाम 4 बजे भूकंप का एक और यानी चौथा झटका आया। बताया जा रहा है कि इस झटके ने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके ठीक डेढ़ घंटे बाद शाम 5.30 बजे भूकंप का 5वां झटका आया।

यह कैसा आक्रोश है, जो शिक्षित सजग युवाओं से लेकर ग्रामीण जनों तक सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकतर मामलों में आक्रोश की यह आंच महिलाओं का ही जीना दुश्वार करती है।

अत्याचार के बीच स्त्री

हाल ही में पीलीभीत में 8 माह की गर्भवती पत्नी को बेरहम पति ने मोटर साइकिल के पीछे बांध कर घसीटा। जीवनसाथी द्वारा क्रूरता की सीमा पार करने वाली इस घटना में पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट तो हुई ही, उसका जीवन छीन लेने के इरादे से उसे मोटर साइकिल के पीछे हाथ बांध कर काफी दूर तक घसीटने की हैवानियत की गई। बीते दिनों दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की के क्षत-विक्षत शरीर को कई किलोमीटर तक घसीटने का भयावह मामला सामने आया था। इस बर्बरता में पुलिस की जांच में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे जानते थे कि एक लड़की गाड़ी के नीचे फंसी है। बावजूद इसके, उसे पूरी तरह कुचल डालने के लिए ही कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। इन वीभत्स घटनाओं ने विकृत मानसिकता का चिंतनीय पहलु उजागर किया है। ऐसी ही हिंसक प्रवृत्ति दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ हुई घटना में भी दिखती है। यह आम महिलाओं का मनोबल तोड़ने वाली बात है कि महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को भी दुर्व्यवहार झेलना पड़ा।

गौरतलब है कि हाल ही में एम्स के पास हुए इस वाकये में पहले एक कार चालक ने आयोग की अध्यक्ष को कार में बैठने को कहा। मना करने पर वह दुबारा मुड़कर आया और फिर बैठने को कहा। नशे की हालत में उनसे छेड़छाड़ भी की। अध्यक्ष ने जब उसे पकड़ा, तो गाड़ी के शीशे में उनका हाथ बंद कर चालक ने घसीटने का प्रयास किया। ऐसे में घर से बाहर निकलने वाली हर महिला के मन का असुरक्षा और संशय से घिर जाना लाजिमी है।

अपरिचित महिलाओं के साथ तो ऐसी घटनाएं हो ही रही हैं, पारिवारिक रंजिश और प्रतिशोध लेने की मंशा से भी ऐसे मामले देखने में आते हैं। पिछले दिनों हसनपुर खंड के गांव टप्पा में चुनावी रंजिश के चलते सरपंच के घर पर गांव के ही एक परिवार के छह से ज्यादा लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर ने सरपंच के बुजुर्ग पिता और उनकी तेरह वर्षीय बेटी को कुचल दिया। घटना में उनकी बेटी घायल हो गई, बुजुर्ग पिता की जान चली गई। गौरतलब है कि सरपंच चुनाव में हार के बाद रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। विडंबना है कि नियम-कायदों से परे, अपने मन-मुताबिक कुछ भी न होना, लोगों में एक अनियंत्रित क्रोध को जन्म दे रहा है। बीते दिनों एटा के ग्रामीण क्षेत्र में भी रंजिश के चलते महिला को ट्रैक्टर से रौंदने की अमानवीयता की गई।

गौरतलब है कि ग्राम समाज की जमीन पर उपले रखने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के कारण की गई बर्बरता में मौके पर ही महिला की मौत हो गई। दूर-दराज गांवों से लेकर महानगरों तक ऐसी घटनाओं ने चिंताजनक स्थितियां पैदा कर दी हैं। यह कैसा आक्रोश है, जो शिक्षित सजग युवाओं से लेकर ग्रामीण जनों तक सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकतर मामलों में आक्रोश की यह आंच महिलाओं का ही जीना दुश्वार करती है। चिंताजनक है कि ऐसे वाकये अनजाने हुई कोई दुर्घटना भर नहीं हैं। सोच-समझकर किसी इंसान को कुचलने की यह विकृत मानसिकता हिंसा का उन्मादी रूप है, जिसमें न अपने-पराए का अंतर समझ आता है और न ही सही-गलत की समझ बाकी रहती है। जबकि समाज को इन घटनाओं का हर पक्ष भीतर तक झकझोर जाता है। बिना किसी गलती के राह चलते रौंद दिए जाने का भय एक नया डर पैदा कर रहा है। असल में, ऐसा परिवेश देश के हर हिस्से की महिलाओं का मनोबल तोड़ता है। शिक्षित-सजग महिलाओं के हौसलों को भी ठेस पहुंचाता है। ऐसे में सार्वजनिक परिवेश में डर का यों साए की तरह साथ रहना किसी भी समाज में कानून-व्यवस्था की विफलता ही कही जाएगी। साथ ही विकृत मानसिकता वाले लोगों की बढ़ती हिम्मत भी समाज और कानून दोनों के लिए चिंताजनक है।

दुखद है कि हमेशा से ही स्त्री पीड़ा और भय के एक अजीब वातावरण में जी रही होती है। कानून, समाज और घर-परिवार, सब बेबस नजर आते हैं। न बदलाव की कोई उम्मीद, न त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था और न ही दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने के उदाहरण। हाल के बरसों में महिलाओं के शोषण और दुर्व्यवहार की घटनाओं की सूची में रौंदने-घसीटने के वाकये भी जुड़ गए हैं। ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिनमें रंजिश के चलते किसी महिला को जानबूझकर कुचल दिया गया। किसी घटना के गवाहों या पीड़ित के परिजनों को सोच-समझ कर वाहन से रौंदने के वाकये भी सामने आ चुके हैं। गांव-कस्बे हों या महानगर, क्रोध और प्रतिशोध का भाव इस हद तक बढ़ गया है कि मामूली रंजिश में भी लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन घटनाओं की बढ़ती संख्या बताती है कि अब नैतिकता का कोई मापदंड नहीं बचा है। कहीं बदला लेने का भाव है, तो कहीं सबक सिखाने की सोच। बेवजह का आक्रोश और नैतिक पतन ऐसी अमानवीय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

नशे के कारण बढ़ रहा शोषण

विडंबना ही है कि कभी नशा, तो कभी सामंतवादी सोच का दंभ, किसी की जान का कोई मोल ही नहीं समझता। अधिकतर घटनाओं में नशे की हालत में ऐसी दुर्घटनाएं और दुर्व्यवहार होता है। ऐसे में शराब के सेवन का बढ़ता चलन कई मोर्चों पर चिंता का विषय बन गया है। इस आदत की बढ़ती सामाजिक स्वीकार्यता और खुलापन इसे बढ़ाने वाला भी साबित हो रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक साझा सर्वेक्षण के मुताबिक देश में लगभग सोलह करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। अफसोस कि देश और परिवार की रीढ़ माने जाने वाले युवा वर्ग के बहुत से पुरुष शराब पीने के बाद हुई हिंसा या दुर्घटनाओं में न केवल अपनी जान गंवाते हैं, बल्कि दूसरों का जीवन भी जोखिम में डालते हैं। कभी नशे की हालत में किसी अपराध में भागीदार बनते हैं, तो कभी यौन शोषण को अंजाम देते हैं। आए दिन घटने वाली कोई न कोई घटना इस बात की पुष्टि भी करती है। शोध पत्रिका 'ड्रग एंड अल्कोहल रिव्यू' में लैंगिक अपराध और शराब के संबंध पर किए गए सर्वेक्षणों के नतीजे बताते हैं कि लैंगिक अपराध के लगभग आधे मामले नशे की हालत में होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शराबनोशी की बड़ी भूमिका है। इतना ही सामंती सोच का दंभ भी ऐसी वारदातों के पीछे है।

मानव जीवन पर संगति का प्रभाव

हिंदू धर्म में वैसे तो कई सारे ग्रंथ और शास्त्र हैं जिनमें मानव जीवन से जुड़ी अहम बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन रामचरितमानस को सबसे अधिक पूजनीय और पवित्र माना जाता है। ये सभी ग्रंथों, पुराणों और शास्त्र में श्रेष्ठ है। रामचरितमानस में मानव जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। मान्यता है इसमें लिखी बातों पर जो भी मनुष्य अमल करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख व परेशानी नहीं आती है। व्यक्ति के जीवन में उसके आसपास के वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है अच्छी संगति में मनुष्य हमेशा ही अच्छा सीखता है। वहीं अगर बुरी संगत हो तो व्यक्ति बुरा बन जाता है। इन बातों का जिक्र सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस में भी किया गया है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं-

गगन चढ़इ रज पवन प्रंसगा।
कीचहिं मिलइ नीच जल संगा।।
साधु असाधु सदन सुक सारीं।
सुमिरहिं राम देहिं गनि गारीं।।

तुलसीदास जी के अनुसार जिस तरह से हवा के साथ मिलकर धूल आंधी का असर आकाश तक होता है और मिट्टी में जल मिलकर कीचड़ बन जाता है ठीक उसी तरह का असर मानव के जीवन में संगत का भी होता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का जीवन समाज में उत्पन्न होता है और समाज में ही विलुप्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में जड़ और चेतन के संपर्क में होता है। इन्हीं जड़ चेतन के संपर्क में सतत् रहने के कारण मनुष्य पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से ही पड़ता है। 'मनुष्यों का जड़ चेतन के साथ संलग्नता, संलिप्ता और उनके प्रभाव से प्रभावित होना संगति कहलाता है।' जड़ हमारे चारों ओर के अचल, निर्जीव वस्तु है जैसे प्रकृति प्रदत्त नदि-नाले, पर्वत-पहाड़ आदि या मानव निर्मित मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि आते हैं वहीं चेतन के अंतर्गत जीवित प्राणी आते हैं। किंतु वैचारिक परिवर्तन केवल मनुष्य ही कर सकते हैं इसलिए मनुष्य को चेतन स्वीकार किया गया बाकी प्राणी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी आदि को जड़ रूप में ही माना गया।

रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदासजी लिखते हैं कि-

जड़ चेतन गुण दोष मय,
बिस्व किन्ह करतार।
संत हंस गुण गहहिं पय,
परिहरि बारि विकार।।

सृष्टिकर्ता ने सृष्टि में जड़ चेतन को गुण और अवगुण युक्त रचा है। गोस्वामीजी कहते हैं इस गुण-दोष मय जड़ चेतन से उसी प्रकार गुण को ग्रहण करना चाहिए जैसे हंस जलयुक्त दूध से केवल दूध को ग्रहण करता है। गुण और दोष में दोष को पृथ्क करते हुए केवल गुण को ग्रहण करने वालों को ही गोस्वामीजी संत की संज्ञा देते हैं।

बुराई का संग करना कुसंग है। अर्थात् बुरे व्यक्ति या बुरी वस्तु के संपर्क में रहना। बुराई क्या है इस पर चिंतन करना आवश्यक है। समग्र रूप में जिस कार्य से सृष्टि की हानि हो उसे बुराई कहा जाता है। आजकल इसके लिए अमानवीय शब्द अधिक प्रचलन में है। इस प्रचलित शब्द का अर्थ केवल इतना ही है कि जिस कर्म या कार्य से किसी भी मनुष्य को नुकसान हो वह बुराई है। जो व्यक्ति या जो वस्तु मनुष्य का अहित करता हो उनकी संगति करना ही कुसंग है। सुसंग निश्चित रूप से यह कुसंग का विलोम है। अच्छे का संग करना सुसंग है। अच्छे व्यक्ति या अच्छी वस्तु के संपर्क में रहना सुसंग है। अच्छाई क्या है? अच्छाई एक कर्म है जिसके किए जाने से सृष्टि का लाभ होता है, सृष्टि संरक्षित और संवर्धित होती है। प्रचलित भाषा में मानवता का संरक्षण और संवर्धन करना ही अच्छाई है। अच्छे कर्म करने वाले लोग ही अच्छे हैं और इनकी संगति करना ही सुसंग है।

संगति का प्रभाव- कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। चाहे आप सनातन धर्म के ग्रंथ, वेद, पुराण देखें या किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ या हिन्दी साहित्य के कोई भी कृति देखें सभी स्थानों पर आपको कुसंग और सुसंग का प्रभाव प्रतिपादित किया हुआ मिल जाएगा। यही कारण है जन-जन यह जानते और मानते हैं कि कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कुसंग और सुसंग के प्रभाव को बहुत ही प्रभावोत्पादक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है-

हानि कुसंग सुसंगति लाहू।
लोकहुं बेद बिदित सब काहू
गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा।
कीचहिं मिलइ नीच जल संगा
साधु असाधु सदन सुक सारी।
सुमिरही राम देहिं गन गारी
धूम कुसंगति कारिख होई।
लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई
सोइ जल अनल अनिल संघाता।
होइ जलद जग जीवन दाता
गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा।
कीचहिं मिलइ नीच जल संगा-

तुलसीदास धूल की संगति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि धूल वही है किंतु संगति के प्रभाव से उसका महत्व अलग-अलग हो जाता है। जब धूल वायु के संपर्क में आता है तो वायु के साथ मिलकर आकाश में उड़ने लगता है किंतु जब वही धूल जल की संगति करता है, कीचड़ बनकर पैरों तले रौंदे जाते हैं।

धूम कुसंगति कारिख होई।
लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई-

धुंए की संगति को परख कर देखिए वहीं धुंआ कुसंगति के प्रभाव से धूल-धूसरित होकर कालिख बन अपमानित होता है तो वही धुंआ सत्संगति के प्रभाव से स्याही बन पावन ग्रंथों में अंकित होकर सम्मानित होता है। वही धुआं जल अग्नि और वायु के संपर्क में आकर मेघ बना जाता है और यही मेघ दुनिया के जीवनदाता कहलाता है।

● **ओम**

खुला दरवाजा

दामिनी शर्मा एक ऐसा नाम जिसे लोग बहुत सम्मान से लेते थे। निर्भीक, निडर और स्पष्ट बोलने वाली सबकी प्रिय एक रुतबा था उनका। परिवार को बहुत ही प्यार से और करीने से सींचा था। सीमित संसाधनों में अपने बच्चों के साथ-साथ परिवार के अन्य बच्चों को भी अपने पास रखकर शिक्षा दिलाई। स्वयं भी उच्च शिक्षित थी पर अपनी नौकरी को महत्व ना देकर बच्चों का भविष्य बनाना प्राथमिकता थी। संयुक्त परिवार में रहने की आदत ने ही सबकी सहायता करना सिखाया था। दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाकर शादी करने के बाद बस बेटे की शादी का ही इंतजार था। सबसे कहती बहू नहीं बेटी लाऊंगी जिससे मेरे पास रहे।

रीमा को अपने बेटे आशू के लिए उन्होंने पसंद किया। रीमा मध्यम परिवार की शिक्षित लड़की थी। सारा प्यार दामिनी और मि. शर्मा ने उसके ऊपर उढ़ेल दिया। रीमा भी बहुत खुश थी और खुश भी क्यों ना हो ससुराल में कोई बंदिश ना थी। ननद अपने परिवारों में व्यस्त थी। आशू की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। दामिनी जी चाहती थी कि रीमा कुछ समय उनके पास रहे पर रीमा ने आशू से कहा कि वह अपने साथ ले चले। नई शादी थी आशू भी चाहता था कि रीमा को साथ ही ले जाए। दामिनी ने भी खुशी-खुशी साथ भेज दिया। सब कुछ सही से चल रहा था। मि. शर्मा भी रिटायर हो चुके थे। दामिनी और मि. शर्मा ने आशू के लिए फ्लैट दिलवा दिया जिससे उन दोनों को परेशानी न हो। धीरे-धीरे करके बेटे की पूरी गृहस्थी सजा दी। दो बच्चों की दादी भी बन गई। अभी कुछ समय से दो चार दिन को वह और मि. शर्मा जब भी बेटे के पास जाते रीमा का व्यवहार बदला हुआ लगता। यह सत्यता थी कि रीमा को उन दोनों का आना पसंद नहीं था। जब रीमा ने किसी बात पर कह दिया उसे बस अपने बच्चों और आशू से ही मतलब है। दामिनी बहुत सुलझी महिला थीं इस बात को सुनकर बिना प्रतिक्रिया के मि. शर्मा से कहा- चलिए हम अपने घर चलते हैं। यह घर तो बहू का है। ये दोनों जब चाहे मेरे घर आ सकते हैं क्योंकि वहां आशू का जन्म और बचपन बीता है। यहां हमारा क्या है। मैं शायद अब नहीं आऊंगी। उस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं।

- डॉ. मधु आंधीवाल

लड़कियों सीखो करना वार

तुम ही मात, पुत्री, भगिनी,
सृष्टि का आधार,
कब तक तुम खामोश रहोगी,
सहोगी अत्याचार।
लड़कियों हाथ गहो तलवार,
लड़कियों सीखो करना वार।
घर आंगन में खेली,
मेरी नन्ही राजकुमारी
मां-बाप की गुड़िया रानी,
भाई को जान प्यारी।
घर से निकली तो रस्ते में,
हुआ है अत्याचार
लड़कियों सीखो करना वार।
कभी कर दिया चलती बस में,
तेरे संग दुराचार,
कभी कर दिए पैंतीस टुकड़े,
कभी चढ़ा दी कार,
बेटियों हाथ गहो तलवार,
लड़कियों सीखो करना वार।
जग की नकली चकाचौंध से,
कर बैठी हो प्यार,
जिसको तुमने कान्हा समझा,
वही दुशासन यार।
लड़कियों मत होना लाचार,
लड़कियों सीखो करना वार।

- प्रदीप शर्मा

बेनाम रिश्ता

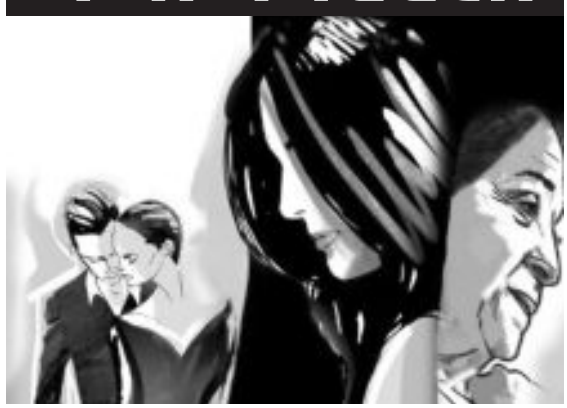

बात कुछ समय पहले की है, फेसबुक के माध्यम से एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले सुंदर स्मार्ट व्यक्ति जिसका नाम था- स्वप्निल, की तरफ से अनुष्का को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली।

धीरे-धीरे बातें शुरू हुई और कुछ समय बाद अनुष्का को एहसास होने लगा कि स्वप्निल उसे दोस्त से कहीं अधिक ऊपर का दर्जा देना चाह रहा है तो उसने उसे वहीं पर अपनी भावनाएं नियंत्रित करने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि अगर यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो वह ब्लॉक होने के लिए तैयार भी रहे, क्योंकि अनुष्का पहले ही शादीशुदा थी। स्वप्निल ने कहा, अनुष्का आपको पसंद करने से कहीं अधिक मैं आपका सम्मान करता हूं और इसीलिए मैं आपके साथ बिना किसी स्वार्थ के हमेशा जुड़े रहना चाहता हूं।

तभी से अपने मन की हर छोटी-बड़ी बात, दुख, चिंता, परेशानी वे एक-दूसरे से सहजता से शेयर कर लेते हैं। नवंबर में स्वप्निल की शादी होने वाली है। स्वप्निल के लिए लड़की अनुष्का ने ही ढूंढी है।

- पिंकी सिंघल

खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दिखा मप्र का दम

13 दिन चले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मप्र ने शानदार प्रदर्शन किया। 27 गेम्स में 973 मेडल्स दिए गए। 36 राज्यों के 5812 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मप्र तीसरे नंबर पर रहा, जबकि महाराष्ट्र टॉप पर। महाराष्ट्र ने 161 मेडल जीते, दूसरे नंबर पर रहे हरियाणा ने 128 और मप्र ने 96 मेडल हासिल किए। मप्र पिछले खेलो इंडिया में आठवें स्थान पर था और इस बार तीसरे पर आ गया। मप्र ने पानी से ही मेडल की शुरुआत की थी और पानी से ही खत्म किया।

टूर्नामेंट का पहला गोल्ड नितिन वर्मा ने कायकिंग केनोइंग में बड़ी झील के पानी में इवेंट के पहले दिन 31 जनवरी को जीता था। आखिरी गोल्ड शनिवार 11 फरवरी को आर्यन एस गणेश ने स्विमिंग में जीता। भोपाल के आर्यन एस गणेश दोहा में रहकर ब्रिटिश कोच माइकल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। वह खेलो इंडिया स्विमिंग में गोल्ड जीतने वाले मप्र के इकलौते स्विमर हैं। टीटी नगर से खेलो इंडिया का आरंभ हुआ था और बड़ी झील पर इसका समापन।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शनिवार को समापन हो गया। मप्र ने 39 स्वर्ण 30 रजत व 27 कांस्य पदक सहित कुल 96 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य का खेलो इंडिया में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ओवरआल विजेता महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण, 55 रजत व 50 कांस्य पदक सहित कुल 161 पदक हासिल किए, जबकि उपविजेता हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत व 55 कांस्य सहित 128 पदक जीते। मप्र वॉटर स्पोर्ट्स, हरियाणा कुश्ती-बॉक्सिंग और महाराष्ट्र स्विमिंग के दम पर टॉप-3 में रहे। मप्र ने वॉटर स्पोर्ट्स में 13 गोल्ड मेडल जीते, जबकि कुश्ती में हरियाणा ने दांव पर लगे 21 गोल्ड में से 9 गोल्ड 8 सिल्वर 24 ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। इसी तरह महाराष्ट्र ने तैराकी में 16 गोल्ड जीते। मप्र को तीसरे स्थान पर पहुंचाने में एथलेटिक और मलखंभ का योगदान भी रहा। एथलेटिक्स में भी उसे 6 गोल्ड समेत 14 मेडल मिले, जबकि मलखंभ में 5 गोल्ड समेत 9 मेडल मिले। मप्र के खाते में बॉक्सिंग में भी 13 मेडल आए।

समापन अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मप्र में खिलाड़ियों को भरपूर सुविधाओं के साथ सम्मान भी दिया जाएगा। खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी एक पृथक कार्यक्रम में पुरस्कृत और सम्मानित किए जाएंगे। पिछले खेलो इंडिया गेम्स में देश में 8वें क्रम पर रहने वाले मप्र ने अब तीसरे क्रम पर स्थान बनाया है। यह गर्व और गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। इसमें खेल क्षेत्र भी शामिल है। खेलों के लिए बजट राशि बढ़ाई गई है।

टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल्ड

महाराष्ट्र की अपेक्षा फर्नांडेज ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। वे पांचवें खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी रही। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के स्विमर अभिनेता आर. माधवन के बेटे वेदांत ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। मप्र के नितिन वर्मा ने 3 गोल्ड जीते, जो सबसे ज्यादा रहे। खेलो इंडिया मप्र के 8 शहरों में आयोजित किया गया। इसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन (महेश्वर) शामिल हैं। एक गेम (साइकिलिंग) दिल्ली में हुआ। 13 दिन चलने वाले खेलो इंडिया में 27 खेल 23 गेम वेन्यू रहे। इसमें करीब 6 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके अलावा इस पूरे गेम में करीब 2 हजार वॉलंटियर भी शामिल रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खेलों के आयोजन के लिए मप्र पर भरोसा किया। मप्र उमंग और उत्साह में डूबा रहा। खिलाड़ियों ने जोश दिखाया और हिंदुस्तान का दिल धड़काया। मप्र में 13 दिन खेलमय वातावरण था। मुख्यमंत्री ने मेडल प्राप्त करने वाले और भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेलो इंडिया में ओवर ऑल चेम्पियन महाराष्ट्र विशेष बधाई का पात्र है। हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। मप्र भी तीसरे क्रम पर आया है। मप्र, हरियाणा से थोड़ा ही पीछे रहा। मप्र ने 39 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। एक समय मप्र का खेलों में कोई विशेष नाम नहीं था। देव कुमार मीणा ने राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया है। खेलो इंडिया में 40 प्रतिशत बेटियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। मलखंभ, एथलीट और वाटर स्पोर्टस में मप्र का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोत्साहनकारी रहे। अब इन खेलों में सफल हुए खिलाड़ियों को अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। इनकी मंजिल अब एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलिंपिक हैं। इन सभी में खिलाड़ियों को पदक जीतना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, स्पोर्टस एथारटी ऑफ इंडिया और खेल विभाग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। खिलाड़ियों ने जोश, जिद और जुनून का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को निरंतर विजय प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दीं।

केंद्रीय खेल, युवा कार्य और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मप्र में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अनेक रिकॉर्ड टूटे हैं। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम बधाई और धन्यवाद की पात्र है। ठाकुर ने कहा कि बेटियों ने खेलों में कमाल कर दिखाया है। इन खिलाड़ियों ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक के दावेदार होने का प्रमाण दिया है। मप्र में खेलो इंडिया गेम्स के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गईं। युवा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मंच मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों के आयोजन से खेल क्षेत्र की प्रतिभाएं आगे आ रही हैं। निर्धन परिवारों से आए खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह आवश्यक है कि सरकार, समाज और कॉर्पोरेट घराने, खेल संस्थाएं और फेडरेशन के साथ मिलकर खेलों को प्रोत्साहन देने का कार्य करें। सहयोग राशि भी खेल गतिविधियों के लिए दी जानी चाहिए। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विभिन्न खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बेटियों और अन्य खिलाड़ियों का अलग-अलग उल्लेख भी किया।

● आशीष नेमा

काजोल से दोबारा मिलना नहीं चाहते थे अजय देवगन, फिर यूं शुरू हुई लव स्टोरी

अजय देवगन और काजोल की जोड़ी को बड़े पर्दे पर काफी पसंद किया गया था, और फिर दोनों की रील जोड़ी रियल जोड़ी में तब्दील हो गई थी। अजय और काजोल ने साल 1999 में शादी रचाई थी। शादी के बाद से लेकर अब तक दोनों की जिंदगी काफी हंसी-खुशी बीत रही है। दोनों गजब की बॉन्डिंग भी शेयर करते रहते हैं। दोनों के दो बच्चे भी हैं, बेटी न्यासा देवगन और बेटा युग देवगन।

आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो काजोल और अजय देवगन की पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी और अजय दोबारा कभी भी काजोल से मिलना नहीं चाहते थे। अजय देवगन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि काजोल और उनका पहली नजर वाला प्यार नहीं था। दरअसल, काजोल और अजय देवगन की पहली मुलाकात साल 1995 में आई फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी। काजोल काफी खुश रहने वाली और मजाकिया स्वभाव की रही हैं। इसलिए वह इस फिल्म के सेट पर हमेशा हंसी-मजाक और मस्ती करती रहती थीं। वहीं, अजय देवगन उनके बिलकुल विपरीत थे, वो काफी शांत रहते थे। यही वजह थी कि अजय को काजोल का अंदाज कुछ पसंद नहीं आया था और इसी कारण वह काजोल से दोबारा नहीं मिलना चाहते थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अजय और काजोल के बीच नजदिकियां भी बढ़ी थी।

दरअसल, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान काजोल हमेशा अजय से अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड के बारे में बात किया करती थीं और अजय उन्हें हमेशा राय भी दिया करते थे कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए और फिर धीरे-धीरे दोनों करीब आते चले गए। वहीं, उनके अफेयर के चर्चे मीडिया जगत में फैलने लगे थे। वहीं, अजय और काजोल ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला लिया।

श्रेयस तलपड़े ने जब कर दी थी ऐसी हरकत, लोगों से मांगनी पड़ी माफी

श्रेयस तलपड़े ने हाल में फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग को पूरा किया है। फिल्म को कंगना रनौत ने डायरेक्ट किया है। श्रेयस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में दिखेंगे। इसे लेकर वह काफी चर्चा में हैं। इस बीच, उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में उन्हें 'ऊं' पर पैर रखते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को लेकर वह ट्रोल भी हो रहे हैं। वह, इस वीडियो के वायरल होने पर लोगों से माफी मांग रहे हैं।

इसके साथ ही उन्होंने ऐसा करने पर सफाई भी दी है। दरअसल, यह वीडियो आज से 11 साल पहले आई फिल्म कमाल, धमाल, मालामाल के एक सीन का है। श्रेयस फिल्म में जॉनी नाम के शख्स का किरदार निभा रहे थे। इसमें नाना पाटेकर भी हैं। दोनों क्रिश्चियन हैं। श्रेयस ने गले में क्रॉस का लॉकेट पहना हुआ है। वह रास्ते में खड़े हैं और सामने आ रहे एक टैम्पो को अपने पैर से रोकते हैं। वह टैम्पो पर जहां पैर रखते हैं, ठीक उनके पैर के नीचे 'ऊं' बना होता है। यह वीडियो वायरल होते ही लोग उन्हें आड़े हाथ लेने लगे कि एक क्रिश्चियन ने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया। वायरल वीडियो और लोगों के रिएक्शन देख उन्होंने माफी मांगी और इसकी सफाई भी दी है।

एक्सपेरिमेंट कर जब कानूनी पचड़े में फंसे आमिर खान, लिया सलमान का नाम!

आमिर खान और सलमान खान बॉलीवुड के हाईपेड एक्टर्स हैं। उनकी फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आती हैं। ये अलग बात है कि बीते कुछ सालों से दोनों के प्रोफेशनल में काफी उथल-पुथल रहा है लेकिन इनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं मीडिया अटकलों की मानें तो फिल्म 'अंदाज अपना अपना' के रिलीज के करीब 29 साल बाद एक बार फिर बॉलीवुड के 'दबंग' और 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। फिल्म का नाम अभी तय नहीं है लेकिन इसके स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। इन्हीं सब के बीच आमिर खान का एक थ्रोबैक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है।

जिसमें उन्होंने कहा था 'कपड़े उतार कर मैंने सलमान खान का काम किया है'। बता दें कि आमिर खान का ये बयान साल 2014 में आई थी। जब उनकी फिल्म 'पीके' रिलीज होने वाली है। उन दिनों फिल्म में आमिर खान का लुक यानी पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसमें आमिर खान रेडियो के साथ न्यूड होकर पोज देते हुए दिखे थे। पोस्टर जारी होते ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आमिर खान कानूनी पचड़े में पड़ गए थे। लोगों ने पोस्टर में उनके लुक का जमकर मजाक भी उड़ाया। उन दिनों मिस्टर परफेक्शनिस्ट जहां भी जाते लोग लोग उनसे एक ही सवाल करते थे आखिर आमिर खान को नंगा होने की जरूरत क्यों पड़ी?

आटा न डाटा, पड़ोस में सिर्फ सन्नाटा...

> *माना जाता है कि बच्चा बढ़ती उम्र के साथ समझदार होता है लेकिन यदि उसका नाम पाकिस्तान हो तो वह और शातिर ही बनता है। जन्म लेते ही कश्मीर में कबायली साजिश में मिली मात के बावजूद वह नहीं सुधरा।*

पाकिस्तान में आटा तो पहले ही मयस्सर नहीं था, अब डाटा भी नदारद हो गया है। बत्ती भी गुल है, सो मोबाइल ही चार्ज नहीं हो पा रहे, इंटरनेट तो बाद की बात है। अब खाली पेट खुराफाती दिमाग क्या करे? अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। बेलगाम महंगाई से आटा-दाल-तेल के दाम तो पाकिस्तान को पहले ही पता चल गए थे, अब बत्ती गुल होने से उस अंधकार का अहसास भी हो गया है, जो वह अपने पड़ोसियों के घरों में फैलाने की हमेशा साजिश रचता रहता है, लेकिन इस सब पर हैरानी कैसी? मजहब के नाम पर भारत में नफरत की दीवार खड़ी कर अलग मुल्क बने पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जब बोया ही बबूल है तो उस पर आम कहां से लगेंगे?

वैसे चोरी-चकारी-तस्करी करने वाले तो अंधेरे में ही अपने काम को अंजाम देने में माहिर होते हैं। पाकिस्तान है तो भारत समेत कुछ देशों का पड़ोसी, परंतु पड़ोसी कहलाने के लायक नहीं। जिस शख्स ने भारत की सरजमीं पर मजहबी नफरत के आधार पर पाकिस्तान की दीवार खींची, उसे कायदे आजम करार दे दिया गया। जिस भारत ने पाकिस्तान को घर चलाने की लिए भारी-भरकम राशि मदद के रूप में दी, उसी से कश्मीर छीनने के नापाक मंसूबों के साथ कबायली और उनके वेश में सेना भेज दी।

माना जाता है कि बच्चा बढ़ती उम्र के साथ समझदार होता है, लेकिन यदि उसका नाम पाकिस्तान हो तो वह और शातिर ही बनता है। जन्म लेते ही कश्मीर में कबायली साजिश में मिली मात के बावजूद वह नहीं सुधरा। एक के बाद एक तीन जंग में मुंह की खाई, पर अक्ल फिर भी ठिकाने नहीं आई। हां, अपनी दुर्बुद्धि का इस्तेमाल भारत के विरूद्ध छद्म युद्ध में करने लगा। सीमा पार से अवैध हथियार और नशीले पदार्थों के साथ ही भारत में अशांति फैलाने के लिए बाकायदा आतंकवादी भी भेजने लगा। शायद भारत के नीति-नियंताओं ने संत कबीर को कुछ ज्यादा ही पढ़-गुन लिया है। सो, पाकिस्तान द्वारा हमारे आंगन में कांटे बोये जाने पर भी उसे फूल भेंट करते रहे। वैसे कबीर वाणी सही भी साबित हुई। भारत की बगिया में खिले फूलों की महक विश्व आर्थिकी से लेकर राजनय तक हर क्षेत्र में फैल रही है, पर पाकिस्तान के लिए कांटे त्रिशूल बनते नजर आ रहे हैं।

घास खाकर भी कश्मीर छीनने के लिए भारत से लड़ने के उन्मादी नारे देते हुए पाकिस्तान के नापाक हुक्मरान वतन लूटकर अपनी तिजोरियां भरते रहे तो भारत विरोधी आतंकवाद के लिए बनाई गई नर्सरी के कैक्टस अब खुद उनको चुभने लगे हैं। एक और पड़ोसी अफगानिस्तान में दखल देने के लिए उसने तालिबान को खड़ा किया था। अब तालिबान पाकिस्तान को ही हलकान कर रहा है। पाकिस्तान पहले भी दूसरे देशों की मदद पर पल-चल रहा था, लेकिन पोल खुल जाने के बाद अब उन दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया है। भेद खुल जाने पर आस्तीन के सांपों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। चोरी की तकनीक और तस्करी के सामान से परमाणु शक्ति बने पाकिस्तान का आलम यह है कि आवाम अर्से से आटे से लेकर पेट्रोल-डीजल तक के लिए लाइनों में लगी है तो गहराता बिजली संकट अब बत्ती गुल में तब्दील हो चुका है। दफ्तरी कामकाज तो छोड़िए, संसद का सत्र तक रोकना पड़ रहा है।

जानकार बता रहे हैं कि तंगहाली का यही हाल रहा तो पाकिस्तान इस साल चुनाव कराने की हालत में भी नहीं है। भारत से मदद की गुहार लगाकर पलट जाने वाले छोटे शरीफ हैं तो प्रधानमंत्री, पर फिलहाल कटोरा लिए दुनियाभर में घूम रहे हैं। कर्ज तो दूर, ब्याज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर कोई कब तक खैरात देता रहेगा? अक्सर पढ़ते-सुनते आए हैं कि पाकिस्तान को तीन ताकतें चलाती हैं- अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अमानत में खयानत के लिए बदनाम अपने चहेते पाकिस्तान से आजिज अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया है तो कंगाल मुल्क की सत्ता में आर्मी की भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रह गई लगती है। ऐसे में अल्लाह ही मालिक है, पर सुनते हैं कि अल्लाह भी तो नेक बंदों का ही हाफिज है!

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

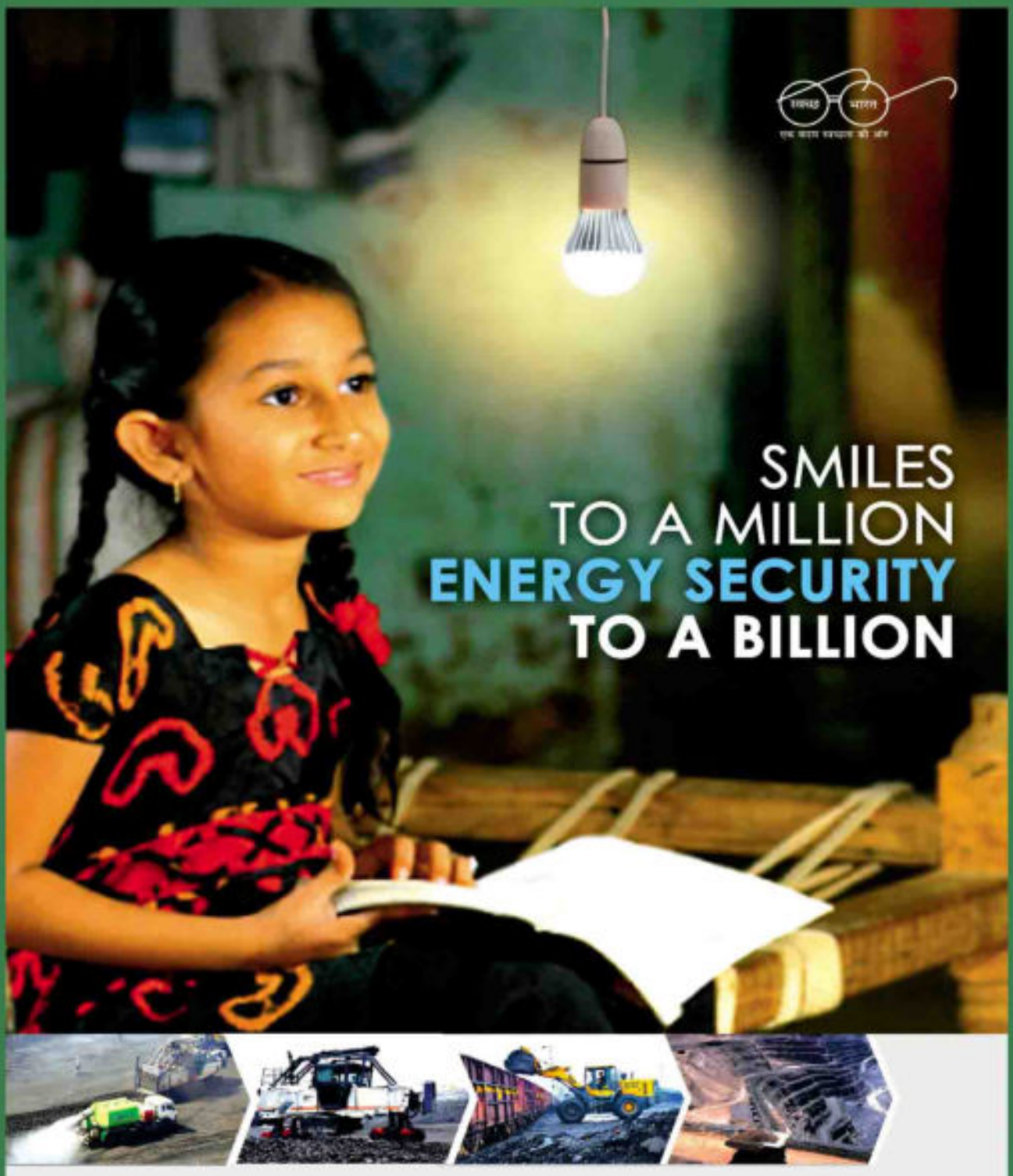

MCL

MAHANADI COALFIELDS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)

Corporate Office: At/Po.- Jagruti Vihar, Burla, Sambalpur, Odisha-768 020

www.mahanadicoal.in mahanadicoal mahanadicoal

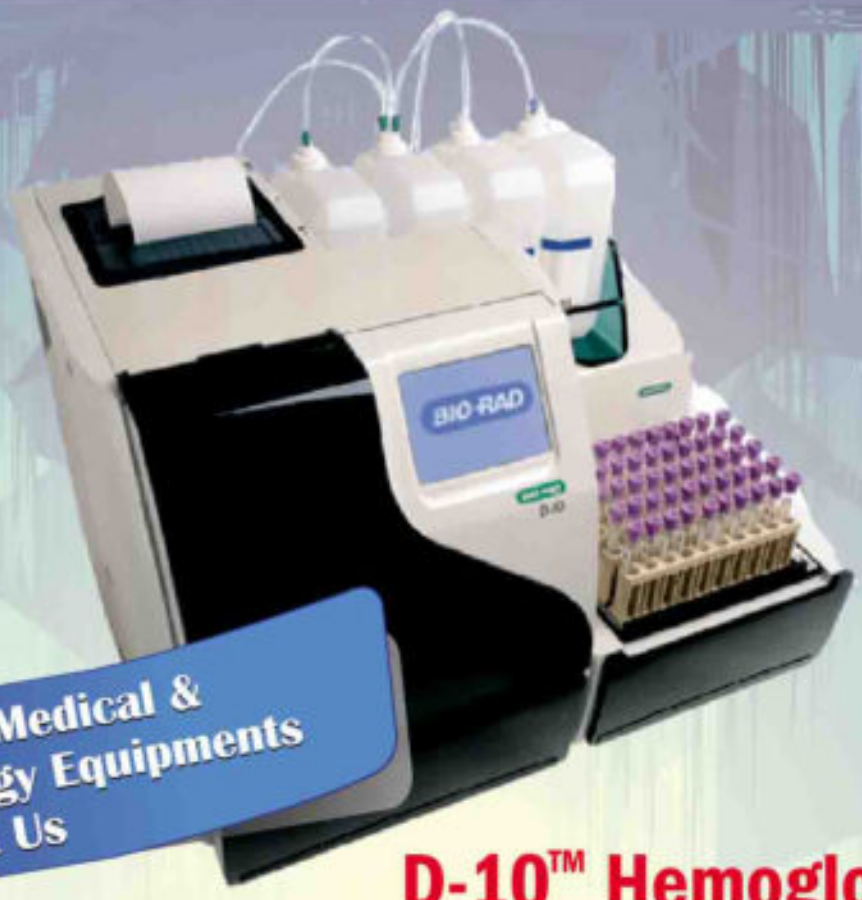

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or HbA_2/FIA_{1c} testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687